रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.) 75 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 22, 1983/आश्विन 30, 1905
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1983/ASVINA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
## PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
## Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of In (other than the Ministry of Defence)

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1983

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का०आ० 3939.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री के० आर० राघवन को, जो पिछले दिनों महानिदेशक (विशेष जांच), नई दिल्ली, के पद पर तैनात थे, 16 सितम्बर, 1983 पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० ए-19011/18/83-प्र० 1]
जी० एस० मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th September, 1983

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 3939.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri K. R. Raghavan, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and lately posted as Director General (Special Investigation), New Delhi as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 16th September, 1983.

[F. No. A. 19011/18/83-Ad. I]
G. S. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर 1983

(आयकर)

का० आ० 3940.—इस कार्यालय की दिनांक 7-2-80 की अधिसूचना सं० 3178 (फा० सं० 203/23/80-आ० क० नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुपयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संमपं" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि बाई जेरबाई वाडिया हास्पिटल फार चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

बाई जेरबाई वाडिया हास्पिटल फार चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूट फ चाइल्ड हैल्थ, बम्बई यह अधिसूचना 12-1-83 से 31-3-84 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 5396 (फा० सं० 203/152/83-आ०क०नि०-II)]
एम०जी०सी० गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 1983

INCOME TAX

S.O. 3940.—In continuation of this Office Notification No. 3178 (F. No. 203/23/89-IIA.II) dated 7-2-1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read, with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Bai Jerbai Wadia Hospital for Children Institute of Child Health, Bombay will maintain a separate accounts of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Bai Jerbai Wadia Hospital for Children, Institute of Child Health, Bombay.

This notification is effective for a period from 12-1-83 to 31-3-1984.

[No. 5396(F. No. 203/152/83-ITA.II)]
M. G. C. GOYAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

का० आ० 3941.—सर्वश्री अलक्वीन टैक्स, के-14, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली को अप्रैल-मार्च, 82 अवधि के लिए 5000 नग ब्लैंक बीडियो कैसेट बी एच एस फारमेट निम्नलिखित ब्रैंड टाइप्स और टाईमिंग्स बैड्स—मेक्सल/हिटाची/नेशनल/स्कॉच/टीडीके/फूजी, टाइप-बी० एच० एस टाइमिंग/ड्यूरेशन 120 से 180 मिनट के आयात के लिए 6,00,000-/ रु० का एक अग्रिम लाइसेंस सं० पी/एल/2952848/सी/एक्स एक्स/81/डी/81, दिनांक 6-11-81 इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया था कि फर्म हांग-कांग को पहले प्रेषण की निकासी की तिथि से 6 मास की अवधि के भीतर 7,50,000-/ रु० जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए 5000 नग के प्री-रिकार्डेड बीडियो कैसेट का निर्यात करेगी।

उन्होंने 1983-84 की आयात तथा निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक की कंडिका 353 के अनुसार यथा अपेक्षित नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति पालम, नई दिल्ली के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् और आंशिक रूप से 1,21,408/- रु० के लिए 1030 नग के ब्लैंक वीडियो, कैसेट का आयात करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और अब 4,78,592- रु० के शेष अप्रयुक्त मूल्य के लिए लाइसेंस की अनुलिपिक मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की आवश्यकता है।

2. मैं संतुष्ट हूं कि अग्रिम लाइसेंस की मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. अद्यतन यथासंशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(1) (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. आवेदक को अब 1983-84 की आयात तथा निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक की कंडिका 352 से 355 दिए गए प्रावधानों के अनुसार 4,78,592/- रु० शेष अप्रयुक्त मूल्य/मात्रा के लिए अग्रिम लाइसेंस सं० पी/एल/2952848 दिनांक 6-11-1981 की अनुलिपि मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा रही है।

[सं० एडीवी/लाइसेंस/यू डी ई एस/101/ए० एम-82/ई०पी० 6/सी०एल०ए०/300]
एस० बालाकृष्णा, पिरलै, उप-मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 23rd May, 1983

S.O. 3941.—M|s. Alcuin Tapes, K-14, Green Park Extension, New Delhi were granted an Advance Licence No. P/L/2952848/C|XX|81|D|81, dated 6th November, 1981 for Rs. 6,00,000 for import of 5,000 No. of Blank Video Cassettee VHS Format of the following Brand Types and bearings Brands=Maxell/Hitachi/National/Scotch|T.D.K.|Fuji, Type of V.H.S. Timing|duration—120 to 180 minutes for AM-82 period with one of the condition that the firm will export 5000 Nos. of pre-recorded video cassettees to Hong Kong for an fob value of Rs. 7,50,000 within a period of six months from the date of clearance of the first consignment.

They have filed an affidavit duly attested by Notary as required in terms of para 353 of Hand Book of Import Export Procedure 1983-84, therein they have stated that the Exchange Control copy of the said licence has been lost/misplaced having been registered with Customs Authorities at Palam, New Delhi and partly utilised to the extend of Rs. 1,21,408 for import of 1030 Nos. of Blank Video Cassettees and duplicate Exchange Control copy of the licence is required for the balance un-utilised value of Rs. 4,78,592.

2. I am satisfied that the original Exchange Control copy of Advance Licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under clause 9(1)(d) of Import Trade Control Order, 1955 dated 7th December, 1955 and as amended up to date, the original Exchange Control copy of the said licence is hereby cancelled.

4. The applicant is being issued duplicate Exchange Control Copy of Advance Licence No. P/L/2952848, dated 6th November, 1981 for the balance un-utilised value/quantity of Rs. 4,78,592 in accordance with the provision of para 352 to 355 of Hand Book of Import Export Procedure 1983-84.

[No. Adv.|Lic|UDES|101|AM. 82|EP. VICLA|300]

S. BALAKRISHNA PILLAI, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

for Jt. Chief Controller of Imports and Exports

खादय एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति मंत्रालय)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1983-09-29

**का० आ० 3942**—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम (4) के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक चिह्न की डिजाइन और उसके शाब्दिक विवरण तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिए है, वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित यह मानक चिह्न 1981-03-01 से लागू होंगे ।

**अनुसूची**

| क्रम सं० | मानक चिह्न की डिजाइन | उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी | तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक | मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | IS : 748-74 | हथकरघे की सूती धोतियां | IS : 748-1974 हथकरघे की सूती धोतियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे "ISI" शब्द होते है स्तम्भ (2) में दिखाई गयी और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या और वर्ष अंकित किया गया है । |

[स सीएमडी/13 : 9)]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1983-09-29

**S.O. 3942.**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1981-03-01:

SCHEDULE

| S. No. | Design of the Standard Mark | Product/Class of Product | No. and Title of the Relevant Indian Standard | Verbal description of the Design of the Standard Mark |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | IS : 748-74 | Handloom cotton dhoties | IS : 748-1974 Specification for handloom cotton dhoties, (first revision) | The monogram of the Indian Standard Institution, consisting of letters 'ISI drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard, alongwith its year, being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design; |

[No. CMD/13:9]

का० आ० 3943.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि हथकरघे की सूती धोतियों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है । यह फीस 1981-03-01 से लागू होगी :

अनुसूची

| क्रम सं० | उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी | तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक | इकाई | प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस |
|---|---|---|---|---|
| 1. | हथकरघे की सूती धोतियां | IS : 748-1974 हथकरघे की सूती धोतियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | एक वर्ग मीटर | 1. 2 पैसे प्रति इकाई पहली 10 0000 इकाइयों के लिए,<br>2. 1 पैसा प्रति इकाई अगली 100001वीं से 200000 तक की इकाइयों के लिए, और<br>3. 1/2 पैसा प्रति इकाई 200001वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए । |

नोट : मुहर लगाने की फीस की दर में 1982-04-01 से निम्न रूप में संशोधन किया गया है :
एक वर्ग मीटर
1. 3 पैसे प्रति इकाई पहली 100000 तक इकाइयों के लिए, और
2. 2 पैसे प्रति इकाई 100001वी और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए ।

[सं० सी एम डी/13 : 10]

S.O. 3943.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee (per unit for handloom cotton dhoties details, of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1981-03-01;

SCHEDULE

| Sl. No. | Product/Class of Proudct | No. and Title of Relevant Indian Standard | Unit | Marking Fee per Unit |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Handloom cotton dhoties | IS:748-1974 Specification for handloom cotton dhoties (first revision) | One Square Metre | (i) 2 Paise per unit for the first 10,000 units;<br>(ii) 1 Paisa per unit for the next 10000 1st to 200000 units ; and<br>(iii) ½ Paisa per unit for the 20000 1st unit and above |

Note:Rate of Marking Fee has since been revised with effect from 1982-04-01 as follows:
One Square Metre (i) 3 Paisa per unit for the first 100000 units; and
(ii) 2 Paisa per unit for the 100001st unit and above

[No. CMD/13:10]

नई दिल्ली, 1983-09-30

का०आ० 3944.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम एवं विनियम 1955 के नियम 14, अधिनियम 4 के अंगर्गत अधिसूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित नीचे अनुसूची में जो लाइसेंसधारी हैं उनके लाइसेंस रद्द हो गये है अथवा फालम 6 के अनुसार उनका नवीकरण स्थगित किया गया है।

अनुसूची

| क्रम सं० | लाइसेंस संख्या | लाइसेंसधारी का नाम और पता | उत्पाद व आई एस संख्या | एस ओ स० व राजपत्र जिसमे अनुदान की सूचना छपी है | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रद्द लाइसेंस | | | | | |
| 1. | सी एम/एल-41 1957-12-10 | फैरचू एवं कं० लिमिटेड नरसमुदा आसनसोल (वे ब) | रेक्टीफाइड स्पिरिट ग्रेड-1 आई एस IS : 323-1959 | एस ओ 52 तिथि 1958-01-04 | 1978-12-15 के बाद रद्द |
| 2. | सी एम/एल-200 1960-06-15 | भारत पलवराइजिंग मिल्स प्रा० लि० मद्रास | डी डी टी धूलन पाउडर— IS : 564-1975 | एस ओ 1632 तिथि 1960-07-02 | 1977-09-30 के बाद नवीकरण किया, अब उसी तिथि से स्थगित किया गया । |
| 3. | सी एम/एल-201 1960-06-15 | भारत पलवराइजिंग मिल्स प्रा० लि० मद्रास | डी डी टी जल परिक्षेपी तेज चूर्ण— IS : 565-1975 | एस ओ 1632 तिथि 1960-07-02 | 1977-09-30 के बाद नवीकरण किया ; अब उसी तिथि से रद्द किया गया है । |
| 4. | सी एम/एल—202 1960-06-15 | भारत पलवराइजिंग मिल्स प्रा० लि० मद्रास | बी एच सी धूलन पाउडर IS : 561-1972 | एस ओ 1632 तिथि 1960-07-02 | नवीकरण 1977-09-30 के बाद निलम्बित किया, उसी तिथि से लाइसेंस रद्द है । |
| 5. | सी एम/एल-363 1961-11-30 | नीलून प्रा० लि० बम्बई 400059 | थ्री फेज प्रेरण मोटर IS : 325-1970 | एस ओ 2940 तिथि 1961-12-16 | नवीकरण 1977-12-15 के बाद निलम्बित किया ; लाइसेंस अब उसी तिथि के बाद रद्द है । |
| 6. | सी एम/एल-474 1962-11-23 | इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता | बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर IS : 561-1972 | — | नवीकरण 1970-04-15 के बाद स्थगित किया लाइसेंस अब उस तिथि के बाद रद्द है। |
| 7. | सी एम/एल-619 1964-01-10 | भोर इंडस्ट्रीज बड़ोदा | बिनाइल चढ़ा कपड़ा (लेदर क्लाथ) IS : 1259-1962 | एस ओ 608 तिथि 1964-02-22 | नवीकरण 1961-02-15 के बाद स्थगित लाइसेंस अब उस तिथि के बाद रद्द है । |
| 8. | सी एम/एल-730 1964-06-29 | नवभारत स्टील रोलिंग मिल्स बम्बई-400078 | हमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | एस ओ 3590 तिथि 1964-08-01 | नवीकरण 1978-01-31 के बाद स्थगित लाइसेंस अब उस तिथि के बाद रद्द है । |
| 9. | सी एम/एल-731 1964-06-29 | ,, | हमारती इस्पात (सामान्य किस्म) IS : 1977-1975 | एस ओ 2590 तिथि 1964-08-01 | नवीकरण 1978-01-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब उस तिथि के बाद रद्द |
| 10. | सी एम/एल-861 1964-11-28 | किनीसन जूट मिल्स क० लि० कलकत्ता-700001 | भारतीय टाट- IS : 2818 (भाग 2)-1977 टाट के थैले IS : 3790-1971 | एस ओ 79 तिथि 1965-01-02 | 1978-11-30 के बाद रद्द है । |
| 11. | सी एम/एल-862 1964-11-28 | केनीसन जूट मिल्स क० लि० कलकत्ता-700001 | ए-ट्विल जूट के बोरे- IS : 1943-1964 भारी सी जूट बेके बोरे- IS . 2874-1964 और बी ट्विल जूट के बोरे- IS : 2566-1965 | एस ओ 79 तिथि 1965-01-02 | 1978-11-30 के बाद रद्द |
| 12. | सी एम/एल-1242 1966-04-14 | एलाय केमिकल्स मद्रास 600019 | एड्रिन ई सी IS. 1310-1974 | एस ओ 1551 तिथि 1966-05-28 | 1979-11-30 के बाद लाइसेंस रद्द |
| 13. | सी एम/एल-1381 1966-12-30 | जे बी मेटल इंडस्ट्रीज बाम्बे | रोल्ड पीतल की पट्टी चादर, पत्ती व पट्टी IS : 410-1967 | एस ओ 243 तिथि 1967-01-21 | नवीकरण 1969-01-15 के बाद स्थगित ; लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 14. | सी एम/एल-1470 1967 07-07 | फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता-700016 | पी वी सी शोधित व पी वी सी खोलवार तार- IS : 3035 (भाग 1)-1965 | एस ओ 2949 तिथि 1967-08-26 | 1978-12-31 के बाद रद्द |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | सी एम/एल–1546 1961-10-13 | अजीत सरिया इंडस्ट्रीज गौहाटी (आसाम) | टी–चेस्ट धातु के फिटिंग IS: 10 (भाग 4)–1976 | एस ओ 4258 तिथि 1967-12-09 | नवीकरण 1977-08-15 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 16. | सी एम/एल–1511 1967-11-23 | कचार प्लाइवुड लि० कलकत्ता | चाय की पेटियों के प्लाईवुड पैनल IS 10 · (भाग 2)–1970 | एस ओ 4568 तिथि 1967-12-23 | नवीकरण 1972-12-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इसी तिथि के बाद रद्द |
| 17. | सी एम/एल–1811 1968-10-14 | एलबियन प्लाइवुड कलकत्ता | लकड़ी के समतल किवाड़ (ठोस कोर की तरह के) ऊपर प्लाईवुड के तख्ते लगे— IS : 2202 (भाग 1)—103 | एस ओ 4257 तिथि 1968-11-30 | नवीनीकरण 1972-10-15 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब उसी तिथि से रद्द |
| 18. | सी एम/एल–1824 1968-10-31 | हिम पाइन इंडस्ट्रीज हरराबाला जिला देहरादून | चाय के पेटियों की पट्टियां IS 10 (भाग 3)–194 | एस ओ 1257 तिथि 1968-11-30 | नवीनीकरण 1977-10-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 19. | सी एम/एल–1956 1969-04-23 | सुदर्शन स्टील रोलिंग मिल्स देहली | संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977–1915 | एस ओ 2238 तिथि 1979-06-07 | नवीकरण 1977-04-30 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 20. | सी एम/एल-2010 1969–07-08 | मा वालेस एंड कं० बंगलोर | पशुओं के लिए मिश्रित आहार— IS : 2052–1968 | एस ओ 3585 तिथि 1979-09-06 | नवीकरण 1973-09-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 21. | सी एम/एल–2035 1969-01-28 | श्री विष्णु रोलिंग मिल्स कलकत्ता | संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226–1975 | एस ओ 3585 तिथि 1969-09-06 | नवीनीकरण 1972-01-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 22. | सी एम/एल–2036 1969-07-28 | " | संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977–1975 | एस ओ 3585 तिथि 1969-09-06 | नवीनीकरण 1972-02-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 23. | सी एम/एल–2074 1969-09-18 | गुरका इंडस्ट्रीज अमृतसर | पानी के मीटर, गीले डायल इंफरेंशल, ए प्रकार के 15 मि०मी० आकार IS . 179–1968 | एस ओ 4310 तिथि 1969-10-25 | नवीनीकरण 1971-07-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 24. | सी एम/एल–2111 1969-10-16 | साउथ इंडिया एलुमिनियम क० मद्रास-600020 | बर्तनो के लिए राट एलुमिनियम व एलुमिनियम मिश्र धातु IS : 21–1975 | एस ओ 4859 तिथि 1969-12-06 | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 25. | सी एम/एल–2211 1970-01-13 | वेस्ट बंगाल आइरन एण्ड स्टील मैनुफैक्चरिंग वर्क्स कलकत्ता–12 | टी चेस्ट मेटल फिटिंग IS : 10(भाग 4)–1976 | एस ओ 771 तिथि 1970-02-08 | 1978-04-30 के बाद रद्द |
| 26 | सी एम/एल–2236 1970-02-09 | भारत पलवराइजिंग मिल्स प्रा० लि० मद्रास 600010 | बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर IS . 632–1972 | एस ओ 1235 तिथि 1970-04-04 | नवीनीकरण 1977-09-30 के बाद स्थगित लाइसेंस इस तिथि के बाद रद्द |
| 27 | सी एम/एल–2115 1970-09-28 | प्रेम चन्द जूट मिल्स कलकत्ता | थ्री-ट्विल पटसन के बोरे IS : 2566–1965 | एस ओ 561 तिथि 1971-01-30 | 1977-09-30 के बाद रद्द |
| 28 | सी एम/एल–2121 1970-10-06 | मल्टी प्लेक्स ऐग्रो इडस्ट्रीज प्रा० लि० अहमदाबाद-2 | एलड्री धूलन पाउडर IS . 1310–1974 | एस ओ 561 तिथि 1971-01-30 | 1978-09-30 के बाद रद्द |
| 29. | सी एम/एल–2429 1970-10-19 | भारत पलवराइजिंग मिल्स प्रा०लि० मद्रास 600019 | फेनीट्रोथइन दसी IS : 5281–1969 | एस ओ 561 तिथि 1971-01-30 | नवीनीकरण 1977-09-10 के बाद स्थगित लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द हैं |
| 30. | सी एम/एल–2432 1970-10-21 | भारत प्लाईवुड एंड टिम्बर प्राडक्ट्स प्रा०लि० बालिया पाटा | लकड़ी का फलस डोर स्टर (सोलिड कोर टाइप) प्लाईवुड फेस पैनल के साथ IS : 2202 (भाग 1) –1973 | एस ओ 561 तिथि 1971-01-30 | नवीनीकरण 1971-10-31 के बाद स्थगित लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द |
| 31. | सी एम/एल–2502 1971-01-04 | निर्मल ट्रेडिंग कं० हावड़ा | चाय की पेटियों के धातु के फिटिंग– IS 10 (भाग 4)–1976 | एस ओ 5028 तिथि 1971-11-06 | नवीनीकरण 1973-12-31 के बाद स्थगित, लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द हैं। |

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|
| 32 सी एम/एल–2580 1971-02-02 | भारत कार्बन एण्ड रिबन मैन्यू कं० फरीदाबाद | स्याही डुप्लीकेटिंग दो मिलिंडर रोटरी मशीनों के लिए IS : 1222–1969 | एम ओ 5037 तिथि 1971-11-06 | नवीनीकरण 1971-06-15 के बाद स्थगित लाइसेंस अब इस तिथि के बाद रद्द है। |
| 33. सी एम/एल–2549 1971-02-18 | किन्नीसन जूट मिल्स कं० लि० टीटागढ़, 24 परगना (प० बं०) | कालीनों में पीछे लगाने का कपड़ा IS : 4900–1969 | एस ओ 5037 तिथि 1971-11-06 | 1978-11-30 के बाद रद्द है। |
| 34. सी एम/एल–2609 1971-03-29 | प्रभात आयरन फाउंड्री एण्ड मैटल इंडस्ट्रीज करकेला | शौच गृह व मूत्रालयों में पानी का फ्लशिंग सिस्टम IS : 774–1971 | एस ओ 2405 तिथि 1971-06-19 | नवीनीकरण 1973-03-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द हैं। |
| 35. सी एम/एल–2676 1971-05-06 | बंगलौर पेस्टीसाइड्स लि० बंगलौर | ऐंड्रेन ईसी— IS : 1310–1974 | एस ओ 5027 1971-11-06 | नवीनीकरण 1978-03-31 के बाद स्थगित, अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द। |
| 36. सी एम/एल–2758 1971-09-07 | मल्टीफलेक्स ऐग्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लि० अहमदाबाद-2 | ऐल्ड्रिन डी पी— IS . 1308–1974 | एस ओ 2403 1972-09-02 | 1978-09-30 के बाद रद्द |
| 37. सी एम/एल–2916 1972-02-16 | हिन्द इनमेल कं० हावड़ा | टी चेस्ट मैटल फिटिंग IS : 10(भाग 4)— 1976 | एस ओ 2801 1972-10-14 | नवीकरण 1974-02-15 के बाद स्थगित, अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 38. सी एम/एल–2936 1972-02-24 | मोदीनगर गालवानाइजिंग वर्क्स, मोदीनगर | सामान्य इंजीनियरिंग के लिए माईल्ड स्टील का तार— IS : 280–1972 | एस ओ 2801 1972-10-14 | नवीकरण 1974-08-31 के बाद स्थगित, अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 39. सी एम/एल–3057 1972-04-28 | केबल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० बम्बई 400066 | 1. एक कोर 250/440 वोल्ट 650/1100 वो० ग्रेड एलुमिनियम चालक युक्त, और | एस ओ 815 1973-03-17 | नवीकरण 1978-10-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द है। |
| | | 2. दो कोर फ्लैट 250/440 वो० और 650/1100 वोल्ट ग्रेड एलुमिनियम कंडक्टर के साथ IS : 3035 (भाग 1) :— 1965 | | नवीकरण 1978-10-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द है। |
| 40. सी एम/एल–3137 1972-08-23 | कैमिकल (इंडिया) कलकत्ता (700053 | इलैक्ट्रो प्लेटिंग के लिए निकेल लवण— IS : 1809–1968 | एस ओ 3471 1973-12-15 | नवीनीकरण 1978-01-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द है। |
| 41. सी एम/एल–3187 1972-10-19 | मेनको इलेक्ट्रीकल्स पालघाट | सामान्य कर्तव्य ऐयर ब्रेक स्विच व एयर ब्रेक स्विच फ्यूज की मिश्रित इकाई— IS : 4064–1967 | एस ओ 846 1874-03-30 | नवीनीकरण 1974-10-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द। |
| 42. सी एम/एल–3700 1974-02-06 | किसपेस्ट प्रा० लि० भोपाल | डीडीटी डीपी IS : 564–1975 | एस ओ 2082 1975-07-05 | नवीनीकरण 1978-01-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द। |
| 43. सी एम/एल–3941 1974-09-02 | अजन्ता आयरन एंड स्टील कं० प्रा० लि० दिल्ली शाहदरा | इमारती इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977–1975 | एस ओ 1762 1976-05-29 | नवीनीकरण 1977-08-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द |
| 44. सी एम/एल–4047 1974-11-07 | ट्रीपलैम फाउन्ड्रेस (इंडिया) नई दिल्ली 110020 | पीतल का बाल वाल्व (समतलीय प्लनजर प्रकार का) IS : 1703–1977 | एस ओ 2022 1976-06-19 | 1978-10-21 के बाद रद्द |
| 45. सी एम/एल-4064 1974-11-25 | जे के मानो एंगी० मशीन लि० कानपुर | डीजल इंजन— IS : 1601—1960 | एस ओ 2022 1976-06-19 | नवीनीकरण 1977-11-30 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | सी एम/एल-4078 1974-11-28 | सीमा लि० बड़ौदा-390002 (गुजरात) | तापनम्य विद्युत रोधन म्रतु-मह केबल-- IS 3055(भाग 1)--1965 IS: 3035(भाग 3)--1967 | एस ओ 2022 1976-06-19 | 1978-11-30 के बाद रद्द |
| 47. | सी एम/एल-4253 1975-03-07 | कृष्णा वाटर मीटर इंडस्ट्रीज नई दिल्ली | पीतल का बाल वाल्व ममसल प्लंजर प्रकार का 15 मिमी माप का — IS:1703-1968 | -- -- | नवीनीकरण 1976-03-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द हैं। |
| 48. | सी एम/एल-4294 1975-04-08 | उतकल पेस्टीमाइड्स एंड केमि० जि० गंजस केमिकल (उड़ीसा) | बीएचसी (एचसीएचईसी)- IS 632-1972 | एस ओ 3550 1976-10-09 | नवीनीकरण 1978-01-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 49. | सी एम/एल-4382 1975-05-15 | कैमिकल ऑरगेनिक्स कटक 752010 उड़ीसा | 2,4-डी सोडियम तकनीकी IS:1488-1969 | एस ओ 3623 1976-10-16 | नवीनीकरण 1976-05-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि से लाइसेंस रद्द |
| 50. | सी एम/एल-4426 1975-06-12 | किलपेस्ट प्रा० लि० भोपाल 462001 (म० प्र०) | ऐल्ड्रिन ईसी-- IS 1307-1973 | एस ओ 3073 1975-09-13 | नवीनीकरण 1978-06-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द |
| 51. | सी एम/एल-4517 1975-07-28 1975-07-12 | रोमर एण्ड कं० (इंडिया) लखनऊ | सील करने का लाख IS 868-1956 | एस ओ 3914 1976-10-31 | नवीनीकरण 1978-03-31 के बाद स्थगित इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द। |
| 52. | सी एम/एल-4565 1975-08-11 | नेशनल इंसुलेटेड कं० आफ इंडिया लि० कलकत्ता | विस्फोट केबल-- IS 5950-1971 | एस ओ 428 1977-03-05 | 1977-08-15 के बाद रद्द |
| 53. | सी एम/एल-4628 1975-09-12 | प्रद्युमना स्टील्स लि० कलकत्ता 700007 | इमारती इस्पात में दुबारा रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात की ढली सिल्ली (मानक किस्म) IS 6914-1973 | एस ओ 832 1977-03-19 | 1978-09-15 के बाद रद्द |
| 54. | सी एम/एल-4629 1975-09-12 | प्रद्युमन स्टील्स लि० कलकत्ता 700007 | इमारती इस्पात में दुबारा रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात की सिल्ली-(साधारण किस्म) IS 6915-1973 | एस ओ 832 1977-03-19 | 1978-09-15 के बाद रद्द |
| 55. | सी एम/एल-4630 1975-09-12 | ,, ,, ,, | वोल्यूट कुंडली व परतदार प्रकार की मोटर कमानी के उत्पादन के लिए ढलवा बिलेट और इंगट IS:8051-1976 | एस ओ 832 1977-03-19 | 1978-09-15 के बाद रद्द |
| 56. | सी एम/एल-4631 1975-09-12 | ,, ,, | वल्यूट व हेलिकल स्प्रींग के उत्पादन के लिए इस्पात सिल्ली व छड़ें (रेलवे रोलिंग स्टाक को) IS 8052-1976 | ,, | 1978-09-15 के बाद रद्द |
| 57. | सी एम/एल-4632 1975-09-12 | प्रद्युमन लि० नेशनल हाईवे नं० 2 जिला हुगली (प० बं०) | परतदार कमानी के उत्पादन के लिए इस्पात सिल्ली व छड़ें (रेल के डिब्बे आदि) IS 8054-1976 | ,, | 1978-09-15 के बाद रद्द |
| 58. | सी एम/एल 4659 1975-09-22 | प्रेम चन्द जूट मिल्स कलकत्ता | खाद बोरी के लिए जूट का कपड़ा— IS 7407-1974 | ,, | 1977-12-31 के बाद रद्द |
| 59. | सी एम/एल-4723 1975-10-15 | एल्डी वायर रोप्स लि० जिला ठाणे (महाराष्ट्र) | सामान्य इंजीनियरी के लिए इस्पात के तार की रस्सी— IS 2266--1970 | एस ओ 1118 1977-04-16 | नवीकरण 1977-10-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि से रद्द। |
| 60. | सी एम/एल-4721 1975-10-15 | ,, | खानों में ढुलाई के लिए इस्पात के तार की रस्सियां-- IS: 1856--1977 | एस ओ 1148 1977-04-16 | नवीकरण 1977-10-15 के बाद स्थगित, अब इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | सीएम/एल-4751 1975-10-27 | बैस्ट एण्ड कोम्पटन इंजि० लिमि० बंगलौर-56001 | बिजली की मोटरें-- IS : 1520--1072 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-15 के बाद रद्द |
| 62. | सीएम/एल-4793 1975-11-24 | एम आर सी इंडस्ट्रीज मद्रास | चमकदार छड़ें (मानक किस्म) IS : 7270-1970 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-15 के बाद रद्द |
| 63. | सीएम/एल-4801 1975-11-24 | ज्ञानम्बिकै मिल्स लि० कोयम्बटूर | खुदरंग सूती धागा-- IS : 171-1973 | " | नवीकरण 1976-11-30 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 64. | सीएम/एल-4992 1976-02-03 | किलपेस्ट प्रा० लि० भोपाल | कारबेरिल जल परिक्षेपी तेज पाउडर-- IS : 7121--1973 | एस ओ 3441 1978-12-02 | नवीकरण 1978-02-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 65. | सीएम/एल-5037 1976-02-20 | किलपेस्ट प्रा० लि० भोपाल | कारबेरिल धूलन पाउडर-- IS : 7122--1973 | एस ओ 3441 1978-12-02 | नवीकरण 1978-02-28 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द। |
| 66. | सीएम/एल-5126 1976-04-19 | जयपाल उद्योग नई दिल्ली-110001 | मालाथियोन पाउडर-- IS : 2568--1973 | एस ओ 314 1979-01 27 | नवीकरण 1978-04-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द। |
| 67. | सीएम/एल-5129 1976-04-19 | हिन्दुस्तान कापर लि० (ए गवर्नमेंट आफ इंडिया इंटरप्राइजज) डि० सिंघभूम (बिहार) | ट्यूबवेल की जाली के निर्माण में प्रयुक्त सीसा पीतल की चादर व पत्ती-- IS : 5494--1969 | " | 1978-09-30 के बाद रद्द |
| 68. | सीएम/एल-5154 1976-04-28 | क्रिपलर्स फाउसेट (इंडिया) नई दिल्ली | पानी के लिए फेरूल-- IS : 2692--1964 | एस ओ 314 1979-01-27 | नवीकरण 1978-04-30 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 69. | सीएम/एल-5185 1976-05-07 | टाईगर लाक्स लि० गुड़गांव-122001 | जल लिए तांबा मिश्र धातु की ढलाई वाली पेंचदार टोटियां और स्टाप वाल्व-- IS : 781-1971 | एस ओ 954 1979-03-17 | नवीकरण 1977-05-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 70. | सीएम/एल-5278 1976-06-07 | डाबरी वाला स्टील एण्ड इंजि० कं० लि० फरीदाबाद | मशीन पेचों के निर्माण के लिये मृदु इस्पात के तार की छड़ें (कोल्ड हेडिंग किया) IS : 2255-1969 | एस ओ | नवीकरण 1978-06-05 के बाद से लाइसेंस रद्द है। |
| 71. | सीएम/एल-5381 1976-08-02 | नेशनल पेस्टीसाइड्स विदिशा 46400 (म० प्र०) | एन्डोसलफेन पायसनीय तेज द्रव IS : 4323-1967 | एस ओ 3548 1979-10-20 | नवीकरण 1978-08-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 72. | सीएम/एल-5413 1976-08-05 | मेकवेल इंडस्ट्रीज भुवनेश्वर 751010 | कोपर सल्फेट तकनीकी IS : 261-1966 | एस ओ 3548 1979-10-20 | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 73. | सीएम/एल-5465 1976-09-02 | अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा० लि० फरीदाबाद | स्कूटर व मोटर साइकिल चालकों के सुरक्षा हेलमेट IS : 4151-1968 | एस ओ 3549 1979-10-20 | नवीकरण 1977-08-31 के बाद स्थगित इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द |
| 74. | सीएम/एल 5478 1976-09-06 | एसीबीन स्टील प्रा० लि० यमुनानगर डि० अम्बाला (हरियाणा) | इमारती इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1975 | " | नवीकरण 1978-08-31 के बाद स्थगित इस तिथि के बाद से लाइसेंस रद्द |
| 75. | सीएम/एल-5503 1976-09-20 | केमीकाइबर नई दिल्ली | स्कूटर मोटर साइकिल वालों के लिये सुरक्षा हेलमेट IS : 4151-1968 | एस ओ 3549 1979-10-20 | नवीकरण 1977-09-15 के बाद स्थगित इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द है |
| 76. | सीएम/एल-5531 1976-09-24 | अरुण स्टील इंडस्ट्रीज कलकत्ता-700043 | इमारती इस्पात (साधारण किस्म)-- IS : 226-1975 | एस ओ 3549 1979-10-20 | 1978-09-30 के बाद रद्द |
| 77. | सीएम/एल-5538 1976-09-24 | जिओ इंडस्ट्रीज एण्ड इनसेक्टीसाइड्स (आई) (प्रा० लि०) मद्रास-600019 | डीडीटी पयासनीन तेज द्रव-- IS : 633-1975 | " | 1978-09-30 के बाद रद्द |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78. | सीएम/एल-5565 1976-10-12 | आन्ध्र इंडस्ट्रीज वर्क्स कुडप्पा (आं० प्र०) | पी वी सी विद्युत रोधी पी वी सी खोलदार केबल एलुमिनियम चालक इक-हरे कोर वाले-250/ 440 वोल्ट IS : 694-(भाग 2)-1964 | एस ओ 3550 1979-10-20 | 1978-10-15 के बाद रद्द |
| 79. | सीएम/एल-5604 1976-10-29 | कृषिकेमिन प्रा० लि० बंगलौर 560011 | कारबेरिल जल परिक्षेपीय तेज पाउडर IS : 7121-1973 | — | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 80. | सीएम/एल-5605 1976-10-29 | कृषि केमिन प्रा० लि० बंग-लोर-560011 | कारबारिल डी पी IS : 17122-1973 | एस ओ 3550 1970-10-20 | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 81. | सीएम/एल-5611 1976-10-29 | भारत हील टिप वर्क्स कान-पुर | जूतों के पंजो के लिये इस्पात के सुरक्षा टोपी IS : 5852-1970 | — | नवीकरण 19771-0-31 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 82. | सीएम/एल-5653 1976-11-18 | गोवन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन नई दिल्ली-110005 | पी वी सी विद्युत रोधी व पी वी सी केबल 250/ 440 वो० IS : 3035(भाग 1)-1965 | एस ओ 3761 1979-11-17 | 1978-11-30 के बाद रद्द |
| 83. | सीएम/एल-6157 1977-06-10 | सोमानी फेरो एलायज लि० कल्यानी 741235 | इमारती इस्पात में दुबारा वल्लन के लिय कार्बन इस्पात के ढले (सामक किस्म)- IS : 6914-1973 | — — | 1978-06-15 के बाद रद्द |
| 84. | सीएम/एल-6158 1977-06-10 | सोमानी फेरो एलायज लि० कल्यानी-741235 | इमारती इस्पात के रूप में दुबारा रोलिंग के लिये कार्बन इस्पात की ढली बिलेट इंगट (साधारण किस्म) IS : 6915-1973 | | 1978-06-15 के बाद रद्द |
| 85. | सीएम/एल-6270 1977-07-25 | अग्रवाल इंडस्ट्रीज आगरा 282 006 | बीएचसी (एचसीएच) धूलन पाउडर— IS : 561—1972 | — | संशोधन 1978-07-15 के बाद स्थगित अब इस तिथि के बाद लाइसेंस रद्द |
| 86. | सीएम/एल-6386 1977-08-31 | रोल्टा इंडस्ट्रीज प्रा० लि० देवास (म० प्र०) | कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत मरोड़ी इस्पात की छड़ें — IS : 1786—1966 | — | 1978-08-31 के बाद रद्द |
| 87. | सीएम/एल-6432 1977-09-30 | स्टील सेल्स इंडिया प्रा० लि० चंडीगढ़ | " | — | 1978-09-30 के बाद रद्द |
| 88. | सीएम/एल-6448 1977-10-10 | ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स फरीदाबाद (हरियाणा) | खेती में प्रयोग के लिए अप-केन्द्री पम्प में लगने वाली तीन फेज की स्क्विरल फेज प्रेरण-मोटर— IS : 7538—1975 | — | 1978-10-15 के बाद रद्द |
| 89. | सीएम/एल-6456 1977-10-12 | हिन्दुस्तान मोटर्स लि० (स्टील फाउंडरी वि०) डाकघर हिन्द मोटर 712233-जिला हुगली | इमारत इस्पात के रूप में दुबारा रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात की ढली बिलेट इंगट (साधारण किस्म)— IS : 6915—1973 | — | 1978-10-15 के बाद रद्द |
| 90. | सीएम/एल-6457 1977-10-12 | " | इमारती इस्पात के रूप में दुबारा रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात की ढली बिलेट इंगट (मानक स्कस्म)— IS : 6914—1937 | — | 1978-10-15 के बाद रद्द |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91. | सीएम/एल/6479 1977-10-24 | बलिस्ता टिम्बर कं० यमुना-नगर-1 | चाय की पेटियों के लिए पट्टियां— IS : 10 (भाग 3)—1979 | — | 1978-10-15 के बाद रद्द |
| 92 | सीएम/एल–6487 1977-10-28 | हिन्दुस्तान मोटर्स लि० (स्टील फाउंडरी डिवीजन) डाकघर हिन्दमोटर -712233 जिला हुगली | परतदार कमानी के उत्पादन के लिए इस्पात रेल के डिब्बों के लिए इंगट और बिलेट— IS : 8054—1976 | — | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 93. | सीएम/एल–6488 1977-10-28 | " | वाल्युट व हेलिकल कमानियों के उत्पादन के लिए इस्पात सिल्लियों के इंगट और बिलेट— IS : 8052—1976 | — | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 94. | सीएम/एल–6495 1977-10-31 | चौगुले ऐग्रो इंडस्ट्रीज बीजापुर-586101 कर्नाटक | जलमल व गैस के बाद पाइपों के लिए ढलवां लोहे के फिटिंग— IS : 8052—1976 | — | 1978-10-31 के बाद रद्द |
| 95. | सीएम/एल–6564 1977-11-24 | प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि० हैदराबाद | इमारती इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977—1975 | — | 1978-11-30 के बाद रद्द |
| लाइसेंस स्थगित : | | | | | |
| 96. | सीएम/एल–64 1958-02-27 | असम फोरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रा० लि० असम | चाय की पेटियों के तख्ते— IS : 10 (भाग 2)—1976 | एस ओ 136 1958-03-01 | 1978-12-31 के बाद स्थगित |
| 97. | सीएम/एल–100 1958-09-18 | सेंट्रल ट्रेनिंग कं० प्रा० लि०, कलकत्ता | चाय की पेटियों के तख्ते— IS : 10 (भाग 2)—1976 | एस ओ 2005 1958-10-04 | 1978-12-31 के बाद स्थगित |
| 98 | सीएम/एल–204 1960-06-28 | जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि० जयपुर | बॉयलर के टांके काबले और रिवेट के लिए तांबे की छड़ें— IS : 288—1960 | एस ओ 1815 1960-07-23 | 1980-10-15 के बाद स्थगित |
| 99. | सीएम/एल–207 1960-07-20 | रिलाउन बिस्कुट कं० बम्बई | बिस्कुट— IS : 1011—1968 | एस ओ 1991 1960-08-13 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 100. | सीएम/एल–225 1960-09-16 | वेनियर मिल्स प्रा० लि०, तिनसुखिया | चाय की पेटियों के छिल्ले— IS : 10 (भाग 2)—1976 | एस ओ 2495 1960-10-15 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 101. | सीएम/एल–450 1962-10-31 | कोयम्बटूर प्रीमियर कारपो० प्रा०लि०, कोयम्बटूर | एक फेज की छोटी ए सी व सर्वप्रयोजन विद्युत मोटर IS : 996—1964 | एस ओ 2985 1962-09-15 | 1978-03-15 के बाद स्थगित |
| 102. | सीएम/एल–467 1962-10-30 | शालीमार तारकोल प्राडक्ट्स (1935) लि० बम्बई | पानी वनमी रोधी बिटूमिन का नमादा— IS : 1322—1970 | एस ओ 3518 1962-11-24 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 103. | सीएम/एल–481 1962-11-29 | गवर्न-सेन्ट्रल लाक फैक्टरी, हावड़ा | ताले एम टाइप पीतल के— IS : 1018—1961 | — | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 104. | सीएम/एल—546 1963-06-05 | बराल टिम्बर असम प्रा० लि० असम | चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10—1977 | एस ओ 2036 1963-07-20 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 105. | सीएम/एल—794 1964-09-30 | नेशनल स्टील वर्क्स लि० बम्बई | इमारती इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977—1975 | एस ओ 3762 1964-10-31 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106. | साएम/एल—831<br>1964-11-02 | अग्रवाल हार्डवेयर वर्क्स प्रा० लि० कलकत्ता | इमारती इस्पात (मानक किस्म)—<br>IS : 226—1975 | एम ओ 79<br>1965-01-02 | 1965-01-02 के बाद स्थगित |
| 107. | सीएम/एल—943<br>1964-11-28 | न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कं० लि० कलकत्ता | भारतीय टाट (सामान्य)<br>IS : 2818—1971 व<br>IS : 3790—1971 | एम ओ 79<br>1965-01-02 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 108. | सीएम/एल—975<br>1964-11-30 | देवीदयाल एलुमियनम इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद | बर्तनों के लिए पिटवां एलुमिनियम व एलुमिनियम मिश्रधातु—<br>IS : 21—1967 | एस ओ 79<br>1965-01-02 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 109. | सीएम/एल/456<br>1967-06-14 | बसन्त प्राप्त एण्ड कं० कलकत्ता | पुनः तार लगाने वाली प्रकार के विद्युत फ्यूज तार 650 वोल्ट तक में प्रयोग के लिए वाहक आधार—<br>IS : 2060—1963 | एस ओ 2650<br>1970-08-05 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 110. | सीएम/एल—1481<br>1967-07-24 | किसान केमिकल चंडीगढ़ | एल्ड्रोनपायसनीय सान्द्र—<br>IS : 1307—1973 | एस ओ 2949<br>1967-09-26 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 111. | सीएम/एल—1526<br>1967-09-15 | इन्सेक्टीसाइड्स एण्ड अलाईड केमिकल्स मद्रास | बीएचसी (एचसीएच) धूलन पाउडर—<br>IS : 561—1972 | एस ओ 3733<br>1967-10-21 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 112. | सीएम/एल—1556<br>1967-11-07 | सहगल सेनीटरी फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जालन्धर | जल के लिए तांबा मिश्र धातु की ढलाई वाली पेंचदार टोंटियां और स्टाप वाल्व—<br>IS : 781—1967 | एस ओ 4568.<br>1967-12-23 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 113. | सीएम/एल—1622<br>1968-01-12 | पेस्टीसाइड्स इंडिया उदयपुर | मालाथियान पायसनीय सान्द्र—<br>IS : 2567—1973 | एस ओ 684<br>1968-02-24 | 1978-07-31 के बाद स्थगित |
| 114. | सी एम/एल-1955<br>1965-04-23 | सुदर्शन स्टील रोलिंग मिल्स दिल्ली-110032 | इमारती इस्पात-(मानक स्तर)<br>IS : 226—1969 | एस ओ 2238<br>1969-06-07 | 1978-07-31 के बाद स्थगित |
| 115 | सी एम/एल-2052<br>1969-08-18 | हुलकोटी को० आ० कॅटिल फोड प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड, धारवाड़ | सूती कपड़े व धागे की स्वदेशी पैकिंग—<br>IS : 1374—1968 | एस ओ 3930<br>1969-09-27 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 116. | सी एम/एल-2072<br>1969-09-10 | सर्वमंगल मैन्यु० कं० कलकत्ता | एसबेस्टॉस सीमेंट के इमारती पाइप, गटर व फिटिंग स्पीगाट व साकेट प्रकार के—<br>IS : 1626—1968 | एस ओ 4310<br>1969-10-25 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 117. | सी एम/एल-2198<br>1970-01-97 | कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, लि०, कुमारधुबी (बिहार) | औसटिनाइटी मेंगनीज इस्पात की ढलाई—<br>IS : 276—1969 | एस ओ 771<br>1970-02-28 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 118. | सी एम/एल-2361<br>1970-07-13 | टिम्बर ट्रेडर्स यमुनानगर | चाय की पेटियों की पट्टियां—<br>IS : 10(भाग 3)—1974 | एस ओ 2109<br>1971-05-29 | 1978-10-30 के बाद स्थगित |
| 119 | सी एम/एल-2427<br>1970-10-19 | यूनीक इंडस्ट्रीज अहमदाबाद | पालीइथाइलीन विद्युत रोधी व पी वी सी खोलदार केबिल-1100 वोल्ट<br>IS : 1996—1962 | एस ओ 561<br>1971-01-30 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 120. | सी एम/एल-2453<br>1970-11-06 | एस के आबिदअली कलकत्ता | चाय की पेटियों के धातु फिटिंग<br>IS : 10 (भाग 4)—1976 | एस ओ 3593<br>1971-10-02 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 121. | सी एम/एल-2509<br>1971-01-15 | यूनीक इंडस्ट्रीज अहमदाबाद | पी वी सी विद्युत रोधक और पी वी सी खोलदार केबल<br>IS : 3035 (भाग 1)—1965 | एस ओ 5028<br>1971-11-06 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |

| (1) (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|
| 122. सी एम/एल-2537 1971-02-08 | बान कोरन एण्ड कं० पटना | यांत्रिक और द्रवचालित सुवाह्य मोटरवाहनों के लिए जैक IS : 4552-1968 | एस ओ 5037 1971-11-06 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 123. सी एम/एल-2951 1972-02-28 | रेनबो सर्जिकल ड्रेसिंग मैन्यु कं० अहमदाबाद | हथकरघा सूती पट्टी वाला कपड़ा— IS : 863-1969 | एस ओ 2801 1972-10-14 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 124. सी एम/एल—3081 1972-06-01 | बसन्त प्राण एण्ड कं० कलकत्ता | अनधिक वोल्टता के लिए बंद वितरण फ्यूज बोर्ड व कटआउट 1000 वोल्ट से IS : 1675—1966 | एस ओ 1552 1973-06-02 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 125. सी एम/एल—3216 1972-11-10 | हीरो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कलकत्ता | खानों व भारी धातु उद्योग के लिए सुरक्षा वाले जूते— IS : 1989—1973 | एस ओ 1700 1973-06-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 126 सी एम/एल-3227 1972-11-28 | सिन्धी केम लिमिटेड वर्धा | एन्ड्रिन पायसनीय सान्द्र IS : 1310—1974 | एस ओ 1700 1973-06-16 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 127. सी एम/एल—3228 1972-11-26 | पी एन एम कम्पनी इरोड | बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर— IS : 561—1972 | एस ओ 1700 1973-06-16 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 128 सी एम/एल-3229 1972-11-28 | ,, | डी डी टी धूलन पाउडर— IS : 564—1961 | एस ओ 1700 1973-06-16 | 1978-06-30 के बाद स्थगित |
| 129. सी एम/एल-3244 1972-12-01 | एवरेस्ट प्लाईवुड इंडस्ट्रीज दार्जिलिंग | चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10 (भाग 2)—1976 | एस ओ-1797 1974-07-20 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 130. सी एम/एल—3358 1973-03-12 | जैसोर काम्ब इंडस्ट्रीज कं० कलकत्ता | पेय पानी की पूर्ति के लिए अल्प घनत्व के पालीइथाइलीन पाइप— IS : 3076-1968 | एस ओ 955 1975-03-29 | 1978-9-15 के बाद स्थगित |
| 131. सी एम/एल—3361 1973-03-14 | अरुण इंजीनियरी इंडस्ट्रीज प्रा० लि० बम्बई | एक फेज स्माल एसी व यूनिवर्सल विद्युत मोटर— IS : 996—1964 | एस ओ 955 1975-03-29 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 132. सी एम/एल-3502 1973-08-02 | रामेर एण्ड कम्पनी लखनऊ | स्याही ड्राइंग जलसह वाली— IS : 789—1971 | एस ओ 1338 1975-05-03 | 1978-05-31 के बाद स्थगित |
| 133. सी एम/एल—3533 1973-09-05 | आन्ध्र स्टील कारपो० बंगलोर | इमारती इस्पात में बेल्लन के लिए हलका कार्बन इस्पात बिलेट व इन-गोट (सामान्य स्तर) IS : 6915—1973 | एस ओ 1389 1975-05-03 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 134. सी एम/एल—3546 1973-09-19 | रेनबो सर्जिकल ड्रेसिंग मैन्यु० कम्पनी अहमदाबाद | हथकरघा सूती अवशोषक गोज— IS : 1758—1969 | एस ओ 1389 1975-05-03 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 135. सी एम/एल—3806 1974-04-16 | प्लास्टिक मोल्डर्स लिमि० कलकत्ता | पेय पानी की पूर्ति के लिए अल्प घनत्व के पालीइथाइलीन पाइप— IS : 4984—1972 | एस ओ 4695 1975-11-01 | 1978-05-31 के बाद स्थगित |
| 136. सी एम/एल—3841 1974-05-16 | यूनियन पेस्टीसाइड्स विदिशा | मालाथियान पायसनीय सान्द्र— IS : 2567—1973 | एस ओ 4695 1975-11-01 | 1978-08-15 के बाद स्थगित |
| 137. सीएम/एल-3853 1974-06-14 | कुमार आयरन एण्ड स्टील प्रा लि. गुवाहटी | इमारती इस्पात (मानक) किस्म IS : 226-1975 | एस ओ 4703 1975-11-01 | 1978-07-30 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 138. | सीएम/एल-3854 1974-06-14 | कुमार आयरन एण्ड स्टील प्रा० लि० गुवाहाटी | इमारती इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1975 | एस ओ 9703 1975-11-01 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 139. | सीएम/एल-3961 1974-09-23 | मोतीलाल पेस्टीसाइड्स (इंडिया) मथुरा | मालाथियान पायसनीय सान्द्र- IS : 2567-1973 | एस ओ 1762 1976-05-29 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 140. | सीएम/एल-3989 1974-10-14 | कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्कस, लि. कुमारधुबी (बिहार) | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | एस ओ 1763 1976-05-29 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 141. | सीएम/एल-3990 1979-10-14 | " " | इमारती इस्पात (साधारण किस्म)- IS : 1977-1975 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 142. | सीएम/एल-3991 1974-10-14 | " " | इमारती इस्पात में कार्बन के लिए पुनर्बेलन इस्पात के ढले बिलेट इंगट (मानक किस्म) IS : 6914-1973 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 143. | सीएम/एल-3992 1974-10-14 | " " | इमारती इस्पात के रूप में दुबारा रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात की ढली बिलेट इंगट (साधारण किस्म) IS : 6915-1975 | " " | 1978-10-14 के बाद स्थगित |
| 144. | सीएम/एल-4011 1979-10-29 | अरुण इंजि. इंडस्ट्रीज प्रा. लि. बम्बई | विद्युत यंत्र ज्वालासह खोल- IS : 2148-1968 | " " | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 145. | सीएम/एल-4073 1974-11-28 | कोहेनूर पेन्टस प्रा. लि. अमृतसर | खिड़की के फ्रेमों पर प्रयोग होने वाली पुटीन- IS : 419-1976 | एस ओ 2022 1978-06-19 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 146. | सीएम/एल-4147 1975-01-14 | कुमारधुबी इजी. वर्क्स लि. कुमारधुबी (बिहार) | लकड़ी के पैंच बनाने के लिए इस्पात तार का उत्पादन के लिए इस्पात के इंगट और बिलेट- IS : 8053-1976 | एस ओ 2465 1976-07-10 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 147. | सीएम/एल-4148 1975-01-14 | " " | मशीन पेंचों के निर्माण के लिए तार छड़ों के उत्पादन के लिए इस्पात के (इंगट और बिलेट) (शीतसिर बनाने की क्रिया द्वारा) IS : 8057-1976 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 148. | सीएम/एल-4149 1975-01-14 | " " | गद्देदार फर्नीचर की स्प्रिंग के लिए सख्त खिंचे इस्पात तार के उत्पादन लिए इस्पात के इंगट और बिलेट- IS : 8056-1967 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 149. | सीएम/एल-4369 1975-05-09 | महाराष्ट्र ब्रास एण्ड मेटल प्रोडक्टस, बम्बई | जल के लिए तांबा मिश्रधातु की ढलाई वाली पेंचदार टोटियां और स्टाप वाल्व- IS : 781-1967 | आई एस ओ 3523 1976-10-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 150. | सीएम/एस-4381 1975-05-15 | गेलसन्सज प्रा. लि. बम्बई | द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयोग होने वाला घरेलू गैस के चूल्हे- IS : 4246-1972 | " " | 1978-11-15 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151. | सीएम/एल-4387<br>1975-05-15 | महाराष्ट्र ग्रास एण्ड मैटल प्राडक्ट्स बम्बई | जल वितरण के लिए फ्लोट के साथ गोला (समतल प्लंजर टाइप)<br>IS : 1703-1968 | एस ओ 3623<br>1976-10-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित । |
| 152. | सीएम/एल-9399<br>1975-05-29 | कुमार धुबी इंजि. वर्क्स लि. कुमारधुबी, (बिहार) | वौल्यट व हेलीकल स्प्रिंग के उत्पादन के लिए इस्पात की सिली व छड़ें–(रेलवे रोलिंग स्टोक को)<br>IS : 8052-1976 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 153. | सी एम/एल–4400<br>1975-05-29 | कुमार धुबी इंजि० वर्क्स लि० कुमार धुबी (बिहार) | वाल्यूट हैलिकल व परतदार स्प्रिंग के उत्पादन के लिए इस्पात इंगट व बिलेट (चलनशील वाहनों में निलम्बन के लिए)<br>IS : 8051—1976 | एस ओ 3623<br>1976-10-16 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 154 | सी एम/एल-4401<br>1975-05-29 | " " | परतदार कमानी स्प्रिंग के निर्माण के लिए इस्पात इंगट व बिलेट (रेलवे के डिब्बों के लिए)<br>IS : 8054—1976 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 155. | सी एम/एल-4402<br>1975-05-30 | " " | स्प्रिंग वाशर के उत्पादन के इस्पात के इंगट व बिलेट—<br>IS : 8055—1976 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 156. | सी एम/एल-4556<br>1975-08-11 | नार्दर्न मिनरलस प्रा० लि० गुड़गांव | मैलाथियान पायसनीय सान्द्र—<br>IS 2567—1973 | एस ओ 426<br>1977-02-05 | 1978-08-15 के बाद स्थगित |
| 157. | सी एम/एल-4642<br>1975-09-12 | वेलूमानी इंजी० इंडस्ट्रीज कोयम्बतूर | भूरे लोहे की ढलाइयाँ—<br>IS : 210—1970 | एस ओ 838<br>1977-03-19 | 1978-09-15 के बाद स्थगित |
| 158 | सी एम/एल-4643<br>1975-09-12 | कोहनूर रबड़ वर्क्स कलकत्ता | खानों के लिए रबड़ केनवास के सुरक्षा बूट—<br>IS : 3976—1967 | एस ओ 832<br>1977-03-19 | 1978-09-15 के बाद स्थगित |
| 159. | सी एम/एल-4677<br>1975-09-29 | किलपेस्ट प्रा० लि० भोपाल | डाइसेल्फेन पायसनीय सान्द्र—<br>IS . 4323—1967 | एस ओ 832<br>1977-03-19 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 160 | सी एम/एल-4691<br>1975-09-29 | महाराष्ट्र ग्रास एण्ड मैटल प्रोडक्ट्स बम्बई | मिनट टोंटी<br>IS . 1795—1974 | एस ओ 832<br>1977-03-19 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 161. | सी एम/एल-4692<br>1975-09-29 | ओरियंटल इंजी वर्क्स प्रा० लि० यमुनानगर | जलकल कार्यों के लिए स्लस वाल्व—<br>IS : 780—1969 | एस ओ 832<br>1977-03-19 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 162. | सी एम/एल-4718<br>1975-10-15 | न्यू इलेक्ट्रिकल प्रा० लि० कलकत्ता | रबड़ के सर्जरी के दस्ताने—<br>IS : 4148—1968 | एस ओ 1148<br>1977-04-16 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 163. | सी एम/एल-4720<br>1975-10-15 | स्टार स्टील प्रा० लि० बंगलोर | परतकमानी स्प्रिंग के निर्माण के लिए इस्पात इंगट बिलेट (रेल के डिब्बों के लिए)<br>IS : 8054—1976 | " " | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 164. | सीएम/एल-4721<br>1975-10-15 | स्टार स्टील प्रा० लि० बंगलोर | लकड़ी के पेचों के निर्माण के लिए इस्पात तार के उत्पादन को इस्पात के इंगट और बिलेट—<br>IS : 8053-1976 | एस ओ 1148<br>1977-04-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165. | सीएम/एल-4726 1975-10-15 | बी एम इंडस्ट्रीज कारपोरेशन बम्बई | शौच गृह व पेशाब घरों के पानी के लिए फ्लश की टंकियां— IS : 774-1971 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 166. | सीएम/एल-4760 1975-10-29 | डालिमा बिस्कुट लि० राजपुरा | वेफर्स— IS : 2397-1972 | ,, ,, | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 167. | सीएम/एल-4761 1975-10-29 | स्पन रबड़ इंडस्ट्रीज कानपुर | ढले हुए पहिये के रबड़ के तले और एड़ियां— IS : 5676-1970 | ,, ,, | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 168. | सीएम/एल-4762 1975-10-29 | श्री अम्बिका मेटल वर्क्स कलकत्ता | द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे— IS : 4246-1972 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 169. | सीएम/एल-4765 1975-10-31 | यूनाइटेड फॉटिलाइजर्स इंडस्ट्रीज ठाणे | डीडीटी जलविसर्जनीय तेज पाउडर— IS : 565-1975 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 170. | सीएम/एल-4766 1975-10-31 | ,, ,, | सामान्य कार्यों के लिए समगति अंतर्दाही इंजन की कार्यकारिता— IS : 2567-1973 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 171. | सीएम/एल-4778 1975-10-31 | हेमल आइल इंजन्स प्रा० लि० कोल्हापुर | सामान्य कार्यों के लिए समगति अंतर्दाही इंजन की कार्यकारिता— IS : 1601-1960 | एस ओ 1148 1977-04-16 | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 172. | सीएम/एल-4791 1975-11-24 | इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्टरी रांची | तीन फेज वाली प्रेरण मोटर— IS : 325-1970 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 173. | सीएम/एल-4802 1975-11-24 | कोरोमंडल इंडग प्रोडक्ट्स प्रा० लि० मद्रास | पायसनीय तेज द्रव— IS : 7122-1973 | ,, | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 174. | सीएम/एल-4803 1975-11-24 | बिटूमैन प्राडक्ट्स (इंडिया) कलकत्ता | पानी व नमी रोधक बिटूमिल नमदा IS : 1322-1970 | एस ओ 1147 1977-09-16 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 175. | सीएम/एल-4804 1975-11-24 | आंध्र स्टील को० आ० लि० बंगलौर | मोटर गाड़ियों में निलम्बन के लिए वाल्यूट हेलिकल व परतदार कमानी के लिए इस्पात— IS : 3431-1965 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 176. | सीएम/एल-4805 1975-11-24 | ,, ,, | परतदार कमानी उत्पादन के लिए रेल के डिब्बों आदि के लिए इस्पात— IS : 8054-1976 | ,, ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 177. | सीएम/एल 4806 1975-11-24 | ,, ,, | कमानीदार वाशर के उत्पादन के लिए इस्पात के इंगट व बिलेट— IS : 8055-1976 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 178. | सीएम/एल-4807 1975-11-24 | ,, ,, | वोल्यूट हेलिकल कमानी के इंगट और बिलेट उत्पादन के लिए इस्पात (रेलवे डिब्बों आदि के लिए ) IS : 8052-1976 | ,, ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 179. | सी एम/एल-4826 1975-11-24 | सहगल सेनिटरी फिटिंग प्रा० लि० जलन्धर | जल सेवा के लिए जोड़ घड़ी (फैरूल)— IS : 2692—1964 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 180. | सी एम/एल-4836 1975-11-24 | उषा पेपर इंडस्ट्रीज कलकत्ता | खाद भराई के लिए परतदार पटसन बोरे— IS : 7406—1974 | ,, ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 181. सी एम/एल-4843 1975-11-26 | सिंह एलाय एण्ड स्टील लि०, कलकत्ता | इमारती इस्पात में दबाव सेल्डन के लिए कार्बन इस्पात के ढले बिलेट इंगट (साधारण किस्म)— IS : 6915—1973 | एस ओ 1147 1977-04-16 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 182. सी एम/एल-4849 1975-11-27 | ओकारो स्टील प्लांट ओकारो शहर | अल्प दाब सिलिंडर के निर्माण के लिए गर्म वेल्डित इस्पात की पट्टी (6 मि मी तक) IS : 6241—1976 | ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 183 सी एम/एल-4869 1975-12-04 | भारत लेमिनेटिड कं० कलकत्ता | खाद की भराई के लिए परतदार पटसन के बोरे— IS : 7406—1974 | एस ओ 3083 1977-10-98 | 1978-11 30 के बाद स्थगित |
| 184. सी एम/एल-4873 1975-12-04 | कान्त लेमिनेटिड इंडस्ट्रीज कलकत्ता | खाद की भराई के लिए परतदार पटसन के बोरे— IS : 7406—1974 | एस ओ 3083 1977-10-08 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 185. सी एम/एल-4875 1975-12-04 | इंडियन लेमिनेशन इंडस्ट्रीज प्रा० लि० कलकत्ता | खाद की भराई के लिए परतदार पटसन के बोरे— IS : 7406—1974 | ,, ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 186. सी एम/एल-4883 1975-12-12 | आन्ध्र स्टील कारपो० लि० बंगलौर | लकड़ी के पेचों के निर्माण के लिए इस्पात तार के उत्पादन के इंगट और बिलेट— IS : 8053—1976 | ,, ,, | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 187. सी एम/एल-4896 1975-12-12 | ,, ,, | मशीनपेंच के निर्माण के लिए तार छड़ के उत्पादन को इस्पात के इंगट बिलेट (शीत सिर बनाने की क्रिया द्वारा)— IS : 8057—1969 | एस ओ 3083 1977-10-08 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 188. सी एम/एल-4904 1975-12-17 | शिवालिक ऐग्रो केमिकल्स मोहाली | डी डी टी पायसनीय सान्द्र— IS : 633—1975 | ,, ,, | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 189. सी एम/एल-4905 1975-12-17 | शिवालिक एग्रो केमिकल मोहाली | ऐनडोसलफेन पायसनीय सान्द्र— IS : 4323—1967 | एस ओ 3083 1977-10-08 | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 190. सी एम/एल-5119 1976-04-19 | अलविटास इलेक्ट्रिक प्रा० लि० मद्रास | शिरोपरि पावर प्रेषण के लिए इस्पात की कोर वाले सख्त खिंचे लड़दार एलुमिनियम चालक— IS : 398—1976 | एस ओ 314 1979-01-27 | 1978-03-31 के बाद स्थगित |
| 191. सी एम/एल-5302 1976-06-05 | स्टार स्टील प्रा० लि० बंगलौर | गढ़ाइयों के लिए कार्बन इस्पात की बिलेट ब्लूम सिल्ली और छड़ें— IS : 1875—1971 | ,, ,, | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 192. सी एम/एल-5323 1976-06-15 | कृषि रसायन डाकघर रानीताल | मालाथियान पायसनीय सान्द्र— IS : 2567—1973 | ,, ,, | 1978-06-30 के बाद स्थगित |
| 193. सी एम/एल-5382 1976-08-02 | ओरियंट वायर रोप्स इन्दौर | सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात के तार की रस्सी— IS : 2266—1970 | एस ओ 3548 1978-10-20 | 1978-07-31 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 194. | सी एम/एल-5406 1976-08-02 | बंगाल सीमेन्ट रिसर्च लेबोरेटरी कलकत्ता | पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेन्ट— IS : 1489—1967 | एस० ओ 3548 1978-10-20 | 1978-07-15 के बाद स्थगित |
| 195. | सी एम/एल-5479 1976-09-06 | एसीबीन स्टील प्रा० लि० यमुनानगर | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226—1975 | एस ओ 359 1979-10-20 | 1978-08-31 के बाद स्थगित |
| 196 | सी एम/एल-5508 1976-09-20 | किसान केमिकल्स रजि० चंडीगढ़ | मालाथियान सान्द्र— IS . 2567—1973 | एस ओ 3549 1979-10-20 | 1978-09-15 के बाद स्थगित |
| 197. | सी एम/एल-5509 1976-09-20 | मोहता एण्ड हेकल लि० बम्बई | शिरोपरि पावर प्रेषण के लिए इस्पात की कोर वाले सख्त खिंचे लदवार एलुमिनियम चालक— IS : 398—1976 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 198. | सी एम/एल-5519 1976-09-21 | राधा इंजीनियरी इंडस्ट्रीज कोयम्बतूर | तीन फेज वाली प्रेरण मोटरें— IS : 325—1970 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 199. | सीएम/एल-5532 1976-09-24 | अशोक स्टील इंडस्ट्रीज हावड़ा | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 200. | सीएम/एल-5533 1976-09-24 | " " | इमारती इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1975 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 201. | सीएम/एल-5543 1976-10-04 | प्रकाश ट्रेडिंग कं० कोयम्बटूर | चाय की पेटियों की धातु की फिटिंग— IS : 10 (भाग 4) 1971 | एस ओ 3550 1979-10-20 | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 202 | सीएम/एल-5550 1976-10-04 | फार्मर्स पैस्टीसाइडस प्रोडक्टूर | डीडीटी धूलन पाउडर— IS:564-1975 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 203. | सीएम/एल-5558 1976-10-04 | हिन्दुस्तान बोबिन इंडस्ट्रीज कलकत्ता | पटसन के चौड़े करघों के लाल— IS : 2910-1971 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 204 | सीएम/एल-5563 1976-10-12 | श्री निवास प्लांट प्रोटे. इंड गुंटूर | बी एच सी (एचसीएच) धूलन पाउडर— IS : 561—1972 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 205. | सीएम/एल-5572 1976-10-12 | शाह मेडिकल एण्ड सर्जिकल कं. लि. बड़ौदा | निर्देश प्रकार का रक्त दाब मापी— IS : 7652—1975 | " " | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 206. | सीएम/एल-5576 1976-10-25 | बी के पेस्टीसाइड स प्रा. लि. ठाणे | इन्डोसलफेन पायसीय सान्द्र- IS : 4323—1976 | " " | 1987-10-31 के बाद स्थगित |
| 207. | सीएम/एल-5599 1976-10-29 | जवाने एण्ड पातीन प्रा० लि० निरज (महाराष्ट्र) | पानी के काम के लिए स्लूस वाल्व— IS : 780—1969 | " " | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 208. | सीएम/एल-5606 1976-10-29 | किसान पेस्टीसाइड्स एण्ड कैमिकल, बंगलौर | बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर IS : 561—1972 | " " | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 209. | सीएम/एल-5613 1976-11-02 | जय केमिकल्स फरीदाबाद | बीएचसी (एचसीएच) जल परिक्षेपी सान्द्र- IS : 562—1972 | एस ओ 3761 1979-11-17 | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 210. | सीएम/एल-5614 1976-11-02 | जय कैमिकल फरीदाबाद | डीडीटी जलपरिक्षेपी सान्द्र पाउडर— IS : 565—1972 | " " | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 211 | सीएम/एल-5616 1976-11-05 | राईटएड्स (बम्बई) प्रा० लि० बम्बई-400060 | रंजकों से बनी फाउंटेनपेन की स्याही (नीली हरी, बैंगनी काली और लाल)- IS : 1221—1971 | " " | 1978-11-15 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 212. | सीएम/एल-5637 1976-11-17 | सुशीला इंडस्ट्रीज पो. ओ. राजगंगपुर | शौच गृह व मूत्रालय की फ्लश की टंकियां (साइफन वाला) वाल्व रहित—IS : | एस ओ 3761 1978-11-17 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 213. | सीएम/एल-5639 1976-11-17 | सुपर इंडिया मेटल कं. प्रा. लि. सिलचर | चाय के पेटियों के प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10 (भाग 2)—1976 | | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 214. | सीएम/एल-5646 1976-11-17 | संत क्लास मेटल वर्क्स जालन्धर | जल सेवा के लिए तांबा मिश्र धातु की ढलाई वाली पेंचदार टोंटियां और स्टाप वाल्व— IS : 781—1967 | " " | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 215. | सीएम/एल-5652 1976-11-17 | दीपक वेजिटेबल आयल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मानवदुर | 18-लिटर वर्गाकार डिब्बे — IS : 916-1975 | " " | 1978-11-15 के बाद स्थगित |
| 216. | सीएम/एल-5665 1926-11-30 | फार्मर पेस्ट कन्ट्रोल प्रा० लि० गुंटूर | बीएचसी (एचसीएच) जल परिक्षेपी तेज चूर्ण— IS : 562-1972 | " " | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 217. | सीएम/एल-5692 1976-12-10 | अशोक स्टील कास्टिंग (यू० पी०) | शौच व गृहमूत्रालय की फ्लश की टंकियां—(वाल्व सहित साइफन वाली)— IS : 774-1971 | एस ओ 3762 1979-11-17 | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 218. | सीएम/एल-5700 1976-12-10 | हैदराबाद एलुमिनियम इंडस्ट्रीज, हैदराबाद | पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात की प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398-1961 | " " | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 219. | सीएम/एल-5734 1976-12-24 | पंजाब आयरन स्टील क० प्रा० लि०, जालन्धर कैंट | गढ़ाइयों के लिए कार्बन इस्पात बिलेट ब्लूम सिल्ली व छड़ें— IS : 875-1971 | | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 220. | सीएम/एल-5862 1977-02-03 | श्री गणेश स्टील रोलिंग मिल्स मद्रास | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | " " | 1978-01-15 के बाद स्थगित |
| 221. | सीएम/एल-5939 1977-03-04 | बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लि०, राची | इमारती इस्पात में दुबारा वेल्डन के लिए कार्बन इस्पात के ढले बिलेट इंगट (मानक किस्म) IS : 6914-1973 | " " | 1978-09-30 को स्थगित |
| 222. | सीएम/एल-6064 1971-04-25 | असम ट्यूब क० लि० गुवाहाटी | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | | 1978-04-30 के बाद स्थगित |
| 223. | सीएम/एल-6385 1977-08-31 | जे डी जोंस एंड क० (बिहार) लि०, जमशेदपुर | बीएचसी (एचसीएच) धूलन पाउडर— IS : 561-1972 | | 1978-03-31 के बाद स्थगित |
| 224. | सीएम/एल-6407 1977-09-15 | श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बतूर | कृषि उपयोग के लिए अपकेन्द्री पंपों के स्क्विरेल फेज प्रेरण मोटर— IS : 7538-1975 | | 1978-09-15 के बाद स्थगित |
| 225 | सीएम/एल-6414 1977-09-21 | भारतीय इस्पात उद्योग प्रा० लि०, पटना | इमारती इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1975 | | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 226. | सीएम/एल-6415 1977-09-21 | " " | इमारती इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1975 | | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 227. | सीएम/एल-6429 1977-09-26 | एसीबीन स्टील प्रा० लि०, यमुना नगर | ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की सरिया— IS : 1786-1966 | " " | 1978-09-30 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 228. | सीएम/एल-6445 1977-10-07 | भारतीय मेटल स्मेलटिंग एंड रिफाईनिंग कारपोरेशन मद्रास | बरोजा कोर वाली टांका लगाने के तार-उत्प्रेरित व अनुप्रेरित (अंग न लगने वाली) IS : 1921-1975 | एस ओ 3762 1979-11-17 | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 229. | सीएम/एल-6449 1977-10-10 | ट्रेक्टो आटो इंडस्ट्रीज कानपुर | 18-लिटर वर्गाकार टिन— IS : 916-1975 | — | 1978-09-30 के बाद स्थगित |
| 230. | सीएम/एल-6451 1977-10-12 | बीके पेस्टीसाइड्स प्रा० लि० ठाणे | अल्ड्रीन ईसी— IS : 1307-1973 | — | 1978-10-15 के बाद स्थगित |
| 231. | सीएम/एल-6461 1977-10-19 | मारफन (इंडिया) इंडस्ट्रीज बम्बई | कोलतार की खाद्य रंग मिश्रितियां— IS : 5346-1975 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 232. | सीएम/एल-6464 1977-10-19 | पोद्दार प्रोजेक्ट लि० हैदराबाद | इमारती इस्पात—(मानक किस्म)— IS : 226-1975 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 233. | सीएम/एल-6469 1977-10-19 | शाम टिम्बर प्रोडक्ट, असम | चाय की पेटियों के प्लाईवुड के तख्ते— IS : 10 (भाग 2)-1976 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 234. | सीएम/एल-6471 1977-10-19 | मेहरा इलेक्ट्रिक कं. अग्रपाड़ी | शिरोपरि पावर प्रेषण के लिए सख्त खिंचे लड़दार एलुमिनियम की कोर वाले एलुमिनियम चालक- IS : 398-1976 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 235. | सीएम/एल-6472 1977-10-19 | वेस्टोवेल इंडिया लि. कलकत्ता | विद्युत उपकरणों के ज्वाला-सह खोल IS : 2148-1968 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 236. | सीएम/एल-6480 1977-10-20 | निर्मल कुमार रूंगटा एण्ड कं. ठाणे | साफ कटाई तेल— IS : 3065-1970 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 237. | सीएम/एल-6485 1977-10-28 | फोर्ट विलियम कं. लि. कलकत्ता | शीत खिंचे प्रतिबल रहित तार— IS : 1785 (भाग 1)-1966 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 238. | सीएम/एल-6486 1977-10-28 | प्रकाश उद्योग पटना | स्कूटर व मोटर साइकिल चालकों के लिए रक्षा हेलमेट— IS : 4151-1976 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 239. | सीएम/एल-6491 1977-10-31 | नाहन फाउंडरी लि. नाहन (हि. प्र.) | कृषि उपयोग के लिए अपकेन्द्री पम्पों के लिए तीन फेज वाली स्क्विरेल फेज प्रेरण मोटर— IS : 7538-1975 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 240. | सीएम/एल-6498 1977-10-31 | प्रीमियर एन्टरप्राइजिज हावड़ा | चाय की पेटियों के धातु के फिटिंग— IS : 10 (भाग 4)-1976 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 241. | सीएम/एल-6499 1977-10-31 | ई एम सी एंटर प्राइजिज कलकत्ता | कृषि उपयोग के लिए साफ ठंडा ताजा पानी के पम्प— IS : 6595-1972 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 242. | सीएम/एल-6501 1977-10-31 | उत्कल पेस्टीस इंडस एण्ड केमिकल्स, बहरामपुर | एन्डो सलफान पायसमीय सान्द्र— IS : 4323-1967 | — | 1978-10-31 के बाद स्थगित |
| 243. | सीएम/एल-6542 1977-11-23 | जिंक मैटल एण्ड इंडस्ट्रीज कलकत्ता | नरम टांके— IS : 193-1966 | — | 1978-11-30 के बाद स्थगित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 244. | सीएम/एल-6553<br>1977-11-24 | नेशनल टार प्रोडक्टस कलकत्ता | लकड़ी परिरक्षकों की तरह उपयोग के लिए क्रिमोट व एस्थ्रासीम तेल—<br>IS : 218—1961 | -- | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 245. | सीएम/एल-6557<br>1977-11-24 | बीके पेस्टीसाइड्स प्रा लि ठाणे | मालाथियाने पायसनीय सान्द्र—<br>IS 2567—1973 | — | 1978-11-30 क बाद स्थगित |
| 246. | सीएम/एल-6566<br>1977-11-24 | यूनाइटेड टोप्स रूरकेला | टाइप राइटर रिबन—<br>IS · 1171—1967 | | 1978-11-30 के बाद स्थगित |
| 247. | सीएम/एल-6572<br>1977-12-08 | ऐक्रोपाइम इंडिया इलाहाबाद | औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट—<br>IS : 2925—1975 | -- | 1978-12-15 के बाद स्थगित |
| 248 | सीएम/एल-6618<br>1977-12-30 | यूनिवर्सल पेट्रो केमिकल्स लि. कलकत्ता | घुलनशील कटाई तेल—<br>IS : 1115—1973 | -- | 1978-12-31 के बाद स्थगित |

[सं० सी एम डी/13 14]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 30th Septemer, 1983

**S.O. 3944**.—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Certification Marks licences, details of which are mentioned in the following Schedule, have lapsed or their renewals deferred effective from the dates shown in Column 6 :

SCHEDULE

| Sl.No. | Licence No. | Licensee | Product & IS:No. | S.O. Number and Date of the Gazette Notifying Grant of Licence | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | LICENCES LAPSED | | | | |
| 1. | CM/L-41<br>1957-12-10 | Carew & Co. Ltd., Narsamuda Asansol (W.B.) | Rectified spirit grade 1-<br>IS: 323-1959 | S.O. 52 dated 1958-01-04 | Lapsed after 1978-12-15 |
| 2. | CM/L-200<br>1960-06-15 | Bharat Pulverising Mills Pvt Ltd., Madras | DDT DP—<br>IS : 564-1975 | S.O. 1632 dated 1960-07-02 | Renewal was deferred after 1977-09-30 the licence now stands lapsed after that date |
| 3. | CM/L-201<br>1960-06-15 | -do- | DDT WDPC—<br>IS : 565-1975 | S.O. 1632 dated 1960-07-02 | Renewal was deferred after 1977-09-30; the licence now stands lapsed after that dated |
| 4. | CM/L-202,<br>1960-06-15 | do-<br>Pvt. Ltd., Madras | HC (HCH) DP—<br>IS : 561-1972 | S.O. 1632 dated 1960-07-02 | Renewal was deferred after 1977-09-30 the licence now stands lapsed after that date |
| 5. | CM/L-363<br>1961-11-30 | Nielcon Pvt. Ltd., Bombay-400059 | Three phase induction motors—<br>IS : 325-1970 | S.O. 2940 dated 1961-12-16 | Renewal was deferred after 1977-12-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 6. | CM/L-474L<br>1962-11-23 | Indian Mineral Industries Ltd., Calcutta | BHC (HCH) DP—<br>IS : 561-1972 | .. | Renewal was deffered after 1970-04-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 7. | CM/L-617<br>1964-01-10 | Bhor Industries, Baroda | Vinyl coated fabrics (leather cloth) —<br>IS:1259-1962 | S.O. 608 dated 1964-02-22 | Renewal was deferred after 1967-02-15 the licence now stands lapsed after that date |
| 8. | CM/L-730<br>1964-06-29 | Nav Bharat Steel Rolling Mills, Bombay-400078 | Structural steel(standard quality)—<br>IS:226-1975 | S.O. 2590 dated 1964-08-01 | Renewal was deferred after 1978-01-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 9. | CM/L-731<br>1964-06-29 | -do- | Structural steel (ordinary quality)—<br>IS:1977-1975 | -do- | -do- |
| 10. | CM/L-861<br>1964-11-28 | Kinnison Jute Mills Co. Ltd., Calcutta-700001 | Indian hessian—<br>IS :2818(Part II)—1971 Hessian bags'—<br>IS:3790-1971 | S.O. 79 dated 1965-01-02 | Lapsed after 1978-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | CM/L-862 1964-11-28 | Kinnison jute Mills Co. Ltd. Calcutta-70000 | A-Twill jute bags — IS.1943-1964, Heavy cee jute bags— IS.2574-1964 & B-Twill jute bags - IS.2566-1965 | S O 79 dated 1965-01-02 | Lapsed after 1973-11-30 |
| 12. | CM/L-1242 1966-04-14 | Plava Chemicals Madras-600019 | Endrin EC— IS:1310-1974 | S.O. 1551 dated 1966-05-28 | Lapsed after 1978-11-30 |
| 13. | CM/L-1381 1966-12-30 | J.B. Metal Industries. Bombay | Rolled brass plate sheet, strip and foil— IS:410-1967 | S.O. 243 dated 1967-01-21 | Renewal was deferred after 1969-01-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 14. | CM/L-1470 1967-07-07 | Fort Gloster Industries Ltd. Calcutta-700016 | PVC insultated and PVC sheathed cables— IS:3035 (Part I)—1965 | S.O. 2949 dated 1967-08-26 | Lapsed after 1978-12-31 |
| 15. | CM/L-1546 1967-10-13 | Ajit Saria Industries, Gauhati (Assam) | Tea-chest metal fittings— IS:10 (Part IV)—1976 | S.O. 4258 dated 1967-12-09 | Renewal was deferred after 1977-08-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 16. | CM/L-1571 1967-11-23 | Cachar Plywood Ltd., Calcutta | Tea-chest plywood Panels— IS:10(PartII)—1970 | S.O. 4568 dated 1967-12-23 | Renewal was deferred after 1972-12-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 17. | CM/L-1811 1968-10-14 | Albion Plywood, Calcutta | Wooden flush door shutters (solid core type), with plywood face panels— IS:2202(Part I)—1973 | S.O. 4257 dated 1968-11-30 | Renewal was deferred after 1972-10-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 18. | CM/L-1824 1968-10-31 | Him Pine Industries, Harrawala, Distt. Dehra Dun | Tea-chest battens— IS:10(Part III)-1974 | -do- | Renewal was deferred after 1977-10-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 19. | CM/L-1956 1969-04-23 | Sudershan Steel Rolling Mills, Delhi | Structural steel (ordinary quality)— IS:1977-1975 | S.O. 2238 dated 1969-06-07 | Renewal was deferred after 1977-04-30; the licence now stands lapsed after that date |
| 20. | CM/L-2010 1969-07-08 | Shaw Wallace & Co. Bangolore | Compounded feeds for cattle— IS:2052-1968 | S.O. 3585 dated 1969-09-06 | Renewal was deferred after 1973-07-31 the licence now stands lapsed after that date |
| 21. | CM/L-2035 1969-07-28 | Shriee Vishnu Rolling Mills, Calcutta | Structural steel (standard quality)— IS : 226-1975 | S.O. 3585 dated 1969-09-06 | Renewal was deferred after 1972-01-31 the licence now stands lapsed after that date |
| 22. | CM/L-2036 1969-07-28 | -do- | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977-1975 | S.O. 3585 dated 1969-09-06 | Renewal was deferred after 1972-01-31 the licence now stands lapsed after that date |
| 23. | CM/L-2074 1969-09-18 | Gurka Industries, Amritsar | Water meters, wet dial inferential type A, 15 mm size— IS : 779-1968 | S.O. 4310 dated 1969-10-25 | Renewal was deferred after 1971-07-31 the licence now stands lapsed after that date |
| 24. | CM/L-2111 1969-10-16 | South India Aluminium Co., Madras-600020 | Wrought aluminium and aluminium alloy for utensils— IS : 21-1975 | S.O. 4849 dated 1969-12-06 | Lapsed after 1978-10-31 |
| 25. | CM/L-2211 1970-01-13 | West Bengal Iron & Steel Manufacturing Works, Calcutta-12 | Tea-chest metal fittings— IS : 10 (Part IV)—1976 | S.O. 771 dated 1970-02-28 | Lapsed after 1978-04-30 |
| 26. | CM/L-2236 1970-02-09 | Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd., Madras-600019 | BHC (HCH) EC— IS : 632-1972 | S.O. 1235 dated 1970-04-04 | Renewal was deferred after 1977-09-30; the licence now stands lasped after that date |
| 27. | CM/L-2415 1970-09-28 | Premchand Jute Mills, Calcutta | B-Twill jute bags— IS : 2566—1965 | S.O. 561 dated 1971-01-30 | Lapsed after 1977-09-30 |
| 28. | CM/L-2421 1970-10-06 | Multiplex Agro Industries Pvt. Ltd., Ahmedabad-2 | Endrin EC— IS : 1310—1974 | S.O. 561 dated 1971-01-30 | Lapsed after 1978-09-30. |
| 29. | CM/L—2429 1970-10-19 | Bharat Pulversing Mills Pvt. Ltd , Madras-600019 | Fenitrothion EC— IS : 5281—1969 | S.O. 561 dated 1971-01-30 | Renewal was deferred after 1977-09-30; the licence now stands lapsed after that date |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | CM/L—2432 1970-10-21 | Bharat Plywood & Timber Products P. Ltd., Baliapatam. | Wooden flush door shutter (solid core type), with plywood face panels— (IS : 2202 (Part I)— 1973. | S.O. 561 dated 1971-01-30 | Renewal was deferred after 1971-10-31: the licence now stands lapsed after that date. |
| 31. | CM/L—2502 1971-01-04 | Nirmal Trading Co., Howrah. | Tea-chest metal fittings— IS : 10 (Part IV)— 1976 | S.O. 5028 dated 1971-11-06 | Renewal was deferred after 1973-12-31 the licence now stands lapsed after that date. |
| 32. | CM/L-2530 1971-02-02 | Bharat Carbon & Ribbon Mfg. Co., Faridabad | Ink, duplicating, for twin cylinder rotary machines IS : 1222—1969 | S.O. 5037 dated 1971-11-06 | Renewal was deferred after 1974-06-15 the licence now stands lapsed after that date. |
| 33. | CM/L-2549 1971-02-18 | Kinnison Jute Mills Co. Ltd., Titagarh, 24 Parganas (WB) | Jute carpet backing fabric IS : 4900 —1969 | S.O. 5037 dated 1971-11-06 | Lapsed after 1978-11-30 |
| 34. | CM/L-2609 1971-03-29 | Probhat Iron Foundary Metal Industries, Rourkela | Flushing cisterns water closets and urinals— IS : 774—1971 | S.O. 2405 dated 1971-06-19 | Renewal as deferred after 1973-03-31: The licence now stands after that date. |
| 35. | CM/L-2676 1971-05-06 | Bangalore Pesticides Ltd. Bangalore. | Endrin EC— IS : 1310—1974 | S.O. 5027 dated 1971-11-06 | Renewal was deferred after 1978-03-31, the licence now satands lapsed after that date |
| 36. | CM/L-2758 1971-09-27 | Multiplex Agro Industries P. Ltd. Ahmedabad-2 | Aldrin DP— IS : 1208—1974 | S.O. 2403 dated 1972.09-02 | Lapsed after 1978-09-30 |
| 37. | CM/L-2916 1972-02-16 | Hind Enamel Co., , Howrah | Tea-chest metal fittings— IS : 10 (Part IV)—1976 | S.O.2801 dated 1972-10-14 | Renewal was deferred after 1974-02-15; the licence noew stands lapsed after that date |
| 38. | CM/L-2936 1972-02-24 | Modinagar Galvanizing Works, Modinagar. | Mild steel wire for general engineering purposes— IS : 280—1972 | S.O. 2801 dated 1972-10-14 | Renewal was deferred after 1974-08-31 the licence now stands lapsed after that date. |
| 39. | CM/L-3057 1972-04-28 | Cable Corporation of India Ltd , Bombay-400066 | (i) Single core, 250/440, volts 650/1100 volts grade with aluminium conductors; and (ii) Twincore, flat, 250/ 440 volts and 650/ 1100 volts grade with aluminium conductor IS: 3055 (Part I)— 1965 | S.O. 815 dated 1973-03-17 | Renewal was deferred after 1978-10-31 the licence now stands lapsed after that date. |
| 40. | CM/L-3137 1972-08-23 | Chemicals (India) Calcutta-700053 | Nickel Salts for electro-plating— IS : 1809—1968 | S.O. 3471 dated 1973-12-15 | Renewal was deferred after 1978-01-15 the licence now stands lapsed after that date. |
| 41. | CM/L-3187 1972-10-19 | Menco Electricals, Palghat | Normal duty air-break switches and composite units of air-break switches and fuses— IS : 4064—1967 | S.O. 846 dated 1974-03-30 | Renewal was deferred after 1974-10-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 42. | CM/L-3700 1974-02-06 | Kilpest P. Ltd., Bhopal | DDT DP— IS: 564—1975 | S.O. 2082 dated 1975-07-05 | Renewal was deferred after 1978-01-31; the licence now stands lapsed after that date. |
| 43. | CM/L 3941 1974-09-02 | Ajanta Iron & Steel Co. Pvt. Ltd.,Delhi-Shahdara | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | S.O. 1762 dated 1976-05-29 | Renewal was deferred after 1977-08-31; the licence now stands lapsed after that date. |
| 44. | CM/L-4047 1974-11-07 | DriplessFaucets (India), Mew Delhi 110020 | Brass ball valves (horizontal plunger type) IS : 1703—1977 | S.O. 2022 dated 1976-06-19 | Lapsed after 1978-10-31 |
| 45. | CM/L-4064 1974-11-25 | J.K. Satoh, Agrl. Machines Ltd., Kanpur. | Diesel engines— IS : 1601—1960 | S.O. 2022 dated 1976-06-19 | Renewal was deferred after 1977-11-30; the licence now stands lapsed after that date. |
| 46. | CM/L-4078 1974-11-28 | Cema Ltd., Baroda 390002 (Gujarat) | Ther no plastic insulated weather proof cables— IS : 3035 (Part I)—1965 & IS : 3035 (Part III)—1967 | S.O. 2022 dated 1976-06-19 | Lapsed after 1978-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. | CM/L-4253 1975-03-07 | Krishna Water Meter Industries, New Delhi. | Brass ball valves (horizontal Plugner type) 15 mm size— IS : 1703—1968 | — | Renewal was deferred after 1976-03-15; the licence now stands lapsed after that date. |
| 48. | CM/L-4294 1975-04-03 | Utkal Pesticides & Chemicals, Distt. Ganjam (Orissa) | BHC (HCH) EC— IS : 632—1972 | S.O. 3550 dated 1976-10-09 | Renewal was deferred after 1978-04-15 the licence now stands lapsed after that date. |
| 49. | CM/L-4382 1975-05-15 | Chemical Organics, Cuttack-752010 (Orissa) | 2, 4 D Sodium, technical IS : 1488—1969 | S.O. 3623 dated 1976-10-16 | Renewal was deferred after 1976-05-15 the licence now stands lapsed after that date. |
| 50. | CM/L-4426 1975-06-12 | Kilpest P. Ltd., Bhopal 462001 (M.P.) | Aldrin EC— IS : 1307—1973 | S.O. 3073 dated 1975-09-13 | Renewal was deferred after 1978-06-15; the licence now stands lapse after that date. |
| 51. | CM/L-4517 1975-07-28 | Romer & Co. (India). Lucknow. | Sealing wax— IS : 868—1956 | S.O. 3914 dated 1976-10-30 | Renewal was deferred after 1978-03-31; the licence now stands lapsed after that date. |
| 52. | CM/L-4565 1975-08-11 | National Insulation Co. of India Ltd., Calcutta. | Short firing cables— IS : 5950—1971 | S.O. 428 dated 1977-02-05 | Lapsed after 1977-08-15 |
| 53. | CM/L-4628 1975-09-12 | Pradyumna Steels Ltd., Calcutta-700007. | Carbon steel cast billet inogts for reolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1973 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Lapsed after 1978-09-15 |
| 54. | CM/L-4629 1975-09-12 | -do- | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1973 | -do- | Lapsed after 1978-09-15 |
| 55. | CM/L-4630 1975-09-12 | -do- | Steel ingots and billets for the production of volute, helical and laminated for automotive suspension— IS : 8051—1976 | -do- | Lapsed after 1978-09-15 |
| 56. | CM/L-4631 1975-09-12 | -do- | Steel ingots and billets for the production of volute and helical springs (for railway rolling stock)— IS : 8052—1976 | -do- | Lapsed after 1978-09-15 |
| 57. | CM/L-4632 1975-09-12 | Pradyumna Ltd., National Highway No. 2, Distt. Hooghly (W.B.) | Steel ingots and billets for production of laminated springs railway rolling stock)— IS : 8054—1976 | -do- | Lapsed after 1978-09-15 |
| 58. | CM/L-4659 1975-09-22 | Premchand Jute Mills, Calcutta. | Jute fabric for fertilizer bags— IS : 7407—1974 | -do- | Lapsed after 1977-12-31 |
| 59. | CM/L-4723 1975-10-15 | Eldee Wire Ropes Ltd., Distt. Thana (Maharashtra). | Steel wire ropes for general engineering purposes— IS : 2266—1970 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Renewal was deferred after 1977-10-15; the licence now stands lapsed after that date. |
| 60. | CM/L-4724 1975-10-15 | Eldee Wire Ropes Ltd., Distt. Thana( Maharashtra. | Steel wire ropes for haulage purposes in mines— IS : 1856—1977 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Renewal was deferred after 1977-10-15 the licence now stands lapsed after that date. |
| 61. | CM/L-4751 1975-10-27 | Best & Cromption Engineering Ltd. Bangalore-560011 | Electric motors— IS : 1520—1972 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Lapsed after 1978-10-15 |
| 62. | CM/L-4793 1975-11-24 | SRC Industries, Madras. | Bright bars (standard quality)— IS : 7270—1970 | S.O. 1147 dated 1977-04-16 | Lapsed after 1978-11-15 |
| 63. | CM/L-4801 1975-11-24 | Gnambikai Mills Ltd., Coimbatore. | Grey cotton yarn— IS : 171—1973 | -do- | Renewal was deferred after 1976-11-30; the licence now stands lapsed after that date. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64. | CM/L-4992 1976-02-03 | Kilpest P. Ltd., Bhopal. | Carbaryl WDPC — IS : 7121 —1973 | S.O. 3441 dated 1978-12-02 | Renewal was deferred after 1978-02-15; & the licence now stands lapsed after that date. |
| 65. | CM/L-5037 1976-02-26 | -do- | Carbaryl DP— IS : 7122—1973 | -do- | Renewal was deferred after 1978-02-28 the licence now stands lapsed after that date. |
| 66. | CM/L-5126 1976-04-19 | Jaipal Udyog, New Delhi-110001 | Malathion DP— IS : 2568—1973 | S.O. 314 dated 1979-01-27 | Renewal was deferred after 1978-04-15; the licence now stands lapsed after that date. |
| 67. | CM/L-5129 1976-04-19 | Hindustan Copper Ltd., (A Govt. of India Enterprises) Distt. Singhbuhm (Bihar) | Lead brass sheets and strips for use in the manufacture of tubewell strainers— IS : 5494—1969 | -do- | Lapsed after 1978-09-30 |
| 68. | CM/L-5154 1976-04-28 | Dripless Faucets (India), New Delhi | Ferrules for water purposes— IS : 2692—1964 | S.O. 314 dated 1979-01-27 | Renewal was deferred after 1978-04-30; the licence now stands lapsed after that date |
| 69. | CM/L-5185 1976-05-07 | Tiger Locks Ltd. Gurgaon-122001 | Cast copper alloy screwdown in taps and stop valves for water services IS : 781—1977 | S.O. 954 dated 1979-03-17 | Renewal was deferred after 1977-05-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 70. | CM/L-5278 1976-06-07 | Dabri Wala Steel & Engg. Co. Ltd., Faridabad | Mild steel wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process)— IS : 2255—1969 | .. | Renewal was deferred after 1978-06-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 71. | CM/L-5381 1976-08-02 | National Pesticides, Vidisha-464001 (M.P.) | Endosulfan EC— IS : 4323—1967 | S.O. 3548 dated 1979-10-20 | Renewal was deferred after 1977-08-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 72. | CM/L-5413 1976-08-05 | Makewell Industries, Bhubaneshwar-751010 | Copper sulphate, technical- IS : 261—1966 | -do- | Lapsed after 1978-10-31 |
| 73. | CM/L-5465 1976-09-02 | Atul Glass Industries P. Ltd., Faridabad-3 | Protective helmets for scooters and motor cycle riders— IS : 4151—1968 | S.O. 3549 dated 1979-10-20 | Renewal was deferred after 1977-08-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 74. | CM/L-5478 1976-09-06 | Aceebeen Steel P. Ltd., Yamunanagar, Distt. Ambala (Haryana) | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | -do- | Renewals was deferred after 1978-08-31; the licence now stands lapsed after that date |
| 75. | CM/L-5503 1976-09-20 | Chemifibre, New Delhi | Protective helmets for scooter and motor cycle riders— IS : 4151—1968 | -do- | Renewal was deferred after 1977-09-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 76. | CM/L-5531 1976-09-24 | Arun Steel Industries, Calcutta-700043 | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. 3549 dated 1979-10-20 | Lapsed after 1978-09-30 |
| 77. | CM/L-5538 1976-09-24 | Geo Industries & Insecticides (I) P. Ltd., Madras-600019 | DDT EC— IS : 633—1975 | -do- | Lapsed after 1978-09-30 |
| 78. | CM/L-5565 1976-10-12 | Andhra Industrial Works, Cuddapah (A.P.) | P. V.C. insulated and PVC sheathed cables, aluminimum conductor, single core, 250/440 volts— IS : 694(Part II)—1964 | S.O. 3550 dated 1979-10-20 | Lapsed after 1978-10-15 |
| 79. | CM/L-5604 1976-10-29 | Krishichemin Pvt. Ltd., Bangalore-560011 | Carbaryl water dispersible powder concentrates— IS : 7121—1973 | -do- | Lapsed after 1978-10-31 |
| 80. | CM/L-5605 1976-10-29 | -do- | Carbaryl DP— IS : 7122—1973 | -do- | Lapsed after 1978-10-31 |
| 81. | CM/L-5611 1976-10-29 | Bharat Heel Tip Works, Kanpur | Protected steel toe caps for footwear— IS : 5852—1970 | -do- | Renewal was deferred after 1970-10-31; the licence now stands lapsed after that date |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82. | CM/L-5653 1976-11-18 | Govan Industrial Corporation, New Delhi-110005 | PVC insulated & PVC sheathed cables, 250/440 volts— IS : 3035(Part I)—1965 | S.O. 3761 dated 1979-11-17 | Lapsed after 1978-11-30 |
| 83. | CM/L-6157 1977-06-10 | Somani Ferro Alloys Ltd., Kalyani-741235 | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1973 | .. | Lapsed after 1978-06-15 |
| 84. | CM/L-6158 1977-06-10 | Somani Ferro Alloys Ltd., Kalyani-741235 | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1973 | .. | Lapsed after 1978-06-15 |
| 85. | CM/L-6270 1977-07-25 | Agarwal Industries, Agra-282006 | BHC(HCH)DP— IS : 561—1972 | .. | Renewal was deferred after 1978-07-15; the licence now stands lapsed after that date |
| 86. | CM/L-6386 1977-08-31 | Rolta Industries Pvt., Ltd., Dewas (M.P.) | Cold twisted steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966 | .. | Lapsed after 1978-08-31 |
| 87. | CM/L-6432 1977-09-30 | Steel Sales India Pvt. Ltd., Chandigarh | Cold twisted steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966 | .. | Lapsed after 1978-09-30 |
| 88. | CM/L-6448 1977-10-10 | Oswal Electricals, Faridabad (Haryana) | Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application— IS : 7538—1975 | .. | Lapsed after 1978-10-15 |
| 89. | CM/L-6456 1977-10-12 | Hindustan Motors Ltd., (Steel Foundry Div.), P.O. Hindmotor-712233, Distt. Hooghly | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1973 | .. | Lapsed after 1978-10-15 |
| 90. | CM/L-6457 1977-10-12 | -do- | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1973 | .. | Lapsed after 1978-10-15 |
| 91. | CM/L-6474 1977-10-24 | Vetista Timber Co., Yamunanagar-1 | Tea-chest battens— IS : 10(Part III)-1974 | .. | Lapsed after 1978-10-15 |
| 92. | CM/L-6487 1977-10-28 | Hindustan Motors Ltd., (Steel Foundary Division), P.O. Hindmotor-712233 Distt. Hooghly | Steel ingots and billets for production of laminated springs (railway rolling stock)- IS : 8054—1976 | .. | Lapsed after 1978-10-31 |
| 93. | CM/L-6488 1977-10-28 | -do- | Steel ingots and billets for the production of volute and helical springs (for railway rolling stock)— IS : 8052—1976 | .. | Lapsed after 1978-10-31 |
| 94. | CM/L-6495 1977-10-31 | Chowgule Agro Industries, Bijapur-586101 (Karnataka) | Cast iron fittings for pressure, pipes for water, gas and sewage— IS : 1538 (PART X)—1976 | .. | Lapsed after 1978-10-15 |
| 95. | CM/L-6564 1977-11-24 | Prabhu Steel Industries Pvt. Ltd., Hyderabad | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | .. | Lapsed after 1978-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | LICENCES DEFERRED | | | | |
| 96. | CM/L-64 1958-02-27 | Assam Forest Products Pvt. Ltd., Assam | Tea-chest plywood panels— IS : 10(Part II)—1976 | S.O. 136 dated 1958-03-01 | Deferred after 1978-12-31 |
| 97. | CM/L-100 1958-09-18 | Central Trading Co. Pvt. Ltd., Calcutta | Tea-chest plywood panels— IS : 10(Part II)—1976 | S.O. 2005 dated 1958-10-04 | Deferred after 1978-12-31 |
| 98. | CM/L-204 1960-06-28 | Jaipur Metals & Electricals Ltd., Jaipur | Copper rods for boiler stay bolts and rivets— IS : 288—1960 | S.O. 1815 dated 1960-07-23 | Deferred after 1978-10-15 |
| 99. | CM/L-207 1960-07-20 | Renown Biscuits Co., Bombay | Biscuits IS : 1011—1968 | S.O. 1991 dated 1960-08-13 | Deferred after 1978-09-30 |
| 100. | CM/L-225 1960-09-16 | Veneer Mills P. Ltd., Tinsukia | Tea-chest plywood panels— IS : 10(Part II)—1976 | S.O. 2495 dated 1960-10-15 | Deferred after 1978-11-30 |
| 101. | CM/L-450 1962-10-30 | Coimbatore Premier Corpn., P. Ltd., Coimbatore | Single phase small ac and universal electric motors— IS : 996—1964 | S.O. 2845 dated 1962-09-15 | Deferred after 1978-03-15 |
| 102. | CM/L-467 1962-10-30 | Shalimar Tar Products (1935) Ltd., Bombay | Bitumen felts for water proofing and damp proofing— IS : 1322—1970 | S.O. 3518 dated 1962-11-24 | Deferred after 1978-11-30 |
| 103. | CM/L-481 1962-11-29 | Govt. Central Lock Factory, Howrah | Padlocks— IS : 275—1961 & M type brass padlocks— IS : 1018—1961 | .. | Deferred after 1978-11-15 |
| 104. | CM/L-546 1963-06-05 | Varat Timber Assam P. Ltd., Assam | Plywood-tea-chests-panels— IS : 10—1977 | S.O. 2036 dated 1963-07-20 | Deferred after 1978-10-31 |
| 105. | CM/L-794 1964-09-30 | National Steel Works Ltd., Bombay | Structural steel (ord. quality)— IS : 1977—1975 | S.O. 3762 dated 1964-10-31 | Deferred after 1978-09-30 |
| 106. | CM/L-831 1964-11-02 | Aggarwal Hardware Works, P. Ltd., Calcutta | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. 79 dated 1965-01-02 | Deferred after 1965-01-02 |
| 107. | CM/L-943 1964-11-28 | New Central Jute Mills Co. Ltd., Calcutta | Indian hessian general— IS : 2818—1971 and IS : 3790—1971 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 108. | CM/L-975 1964-11-30 | Devidayal Aluminium Industries, Ghaziabad | Wrought aluminium and aluminium alloy for utensils— IS : 21—1967 | -do- | Deferred after 1978-12-15 |
| 109. | CM/L-1456 1967-06-14 | Basant Pran & Co., Calcutta | Carriers and bases used in rewireable type electric fuses upto 650 volts— IS : 2086—1963 | S.O. 2650 dated 1967-08-05 | Deferred after 1978-11-30 |
| 110. | CM/L-1481 1967-07-24 | Kissan Chemicals, Chandigarh | Aldrin EC— IS : 1307—1973 | S.O. 2949 dated 1967-08-26 | Deferred after 1978-12-15 |
| 111. | CM/L-1526 1967-09-15 | Insecticides & Allied Chemicals, Madras. | BHC (HCH) DP— IS : 561—1972 | S.O. 3733 dated 1967-10-21 | Deferred after 1978-10-31 |
| 112. | CM/L-1556 1967-11-07 | Sehgal Sanitary Fittings P. Ltd., Jullundur. | Sand cast brass screw down bib taps and stop taps for water services— IS : 781—1967 | S.O. 4568 dated 1967-12-23 | Deferred after 1978-11-15 |
| 113. | CM/L-1622 1968-01-12 | Pesticides India, Udaipur | Malathion EC— IS : 2567—1973 | S.O. 684 dated 1968-02-24 | Deferred after 1978-07-31 |
| 114. | CM/L-1955 1969-04-23 | Sudarshan Steel Rolling Mills, Delhi-110032. | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1969 | S.O. 2238 dated 1969-06-07 | Deferred after 1978-07-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115. | CM/L-2052 1969-08-18 | Hulkoti Coop. Cattle Feed Processing Soc. Ltd., Dharwar. | Inland packaging of cotton cloth and yarn— IS : 1374—1968 | S.O. 3930 dated 1969-09-27 | Deferred after 1978-09-30 |
| 116. | CM/L-2072 1969-09-10 | Sarbamangala Mfg. Co., Calcutta. | Asbestos cement building pipes, gutters and fittings (spigot and socket types)— IS: 1626—1968 | S.O. 4310 dated 1969-10-25 | Deferred after 1978-09-30 |
| 117. | CM/L-2198 1970-01-07 | Kumardhubi Engg. Works Ltd., Kumardhubi (Bihar). | Austenitic manganese steel castings— IS : 276—1969 | S.O. 771 dated 1970-02-28 | Deferred after 1978-10-15 |
| 118. | CM/L-2361 1970-07-13 | Timber Traders, Yamunanagar. | Tea-chest buttens— IS: 10 (Part III)—1974 | S.O. 2109 dated 1971-05-29 | Deferred after 1978-11-30 |
| 119. | CM/L-2427 1970-10-19 | Unique Industries, Ahmedabad. | Ploythylene insulated & PVC sheathed cables upto and including 1100 V— IS : 1596—1962 | S.O. 561 dated 1971-01-30 | Deferred after 1978-12-15 |
| 120. | CM/L-2453 1970-11-06 | S.K. Abed Ali, Calcutta. | Tea-chest metal fittings— IS : 10 (Part IV) –1976 | S.O. 3593 dated 1971-10-02 | Deferred after 1978-11-15 |
| 121. | CM/L-2509 1971-01-15 | Unique Industries, Ahmedabad | PVC insulated and PVC sheathed cables— IS : 3035 (Part I)—1965 | S.O. 5028 dated 1971-11-06 | Deferred after 1978-12-15 |
| 122. | CM/L-2537 1971-02-08 | Vankos & Co., Patna | Portable jacks for automobiles, mechanical and hydraulic— IS : 4552—1968 | S.O. 5037 dated 1971-11-06 | Deferred after 1978-11-30 |
| 123. | CM/L-2951 1972-02-28 | Rainbow surgical Dressing Mfg. Co., Ahmedabad. | Handloom cotton bandage cloth— IS : 863—1969 | S.O. 2801 dated 1972-10-14 | Deferred after 1978-09-30 |
| 124. | CM/L-3081 1972-06-01 | Basant Pran & Co., Calcutta. | Enclosed distribution fuse boards and cutouts for voltages not exceeding 1000 V— IS : 1675—1966 | S.O. 1552 dated 1973-06-02 | Deferred after 1978-11-30 |
| 125. | CM/L-3216 1972-11-10 | Hiron Small Scale Industries, Calcutta | Safety boots and shoes for mines and heavy metal industries— IS : 1989—1973 | S.O. 1700 dated 1973-06-16 | Deferred after 1978-11-15 |
| 126. | CM/L-3227 1972-11-28 | Sindichem Ltd., Wardha | Endrin EC— IS : 1310—1974 | S.O. 1700 dated 1973-06-16 | Deferred after 1978-11-30 |
| 127. | CM/L-3228 1972-11-28 | P.N.M. Co., Erode | BHC (HCH) DP— IS : 561—1972 | S.O. 1700 dated 1973-06-16 | Deferred ater 1978-10-31 |
| 128. | CM/L-3229 1972-11-28 | P.N.M. Company, Erode | DDT DP— IS : 564—1961 | S.O. 1700 dated 1973-06-16 | Deferred after 1978-06-30 |
| 129. | CM/L-3244 1972-12-07 | Everest Plywood Industries, Darjeeling | Tea-chest plywood panels— IS : 10(Part II)—1976 | S.O. 1797 dated 1974-07-20 | Deferred after 1978-12-15 |
| 130. | CM/L-3358 1973-03-12 | Jessor Comb Industry Co., Calcutta | Low density polyethylene pipes for potable water supplies— IS : 3076—1968 | S.O. 955 dated 1975-03-29 | Deferred after 1978-09-15 |
| 131. | CM/L-3361 1973-03-14 | Arun Engg. Industries P. Ltd., Bombay | Single phase small ac and universal electric motors— IS : 996—1964 | S.O. 955 dated 1975-03-29 | Deferred after 1978-10-31 |
| 132. | CM/L-3502 1973-08-02 | Ramer & Co., Lucknow | Ink, drawing, waterproof black— IS : 789—1971 | S.O. 1388 dated 1975-05-03 | Deferred after 1978-05-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 133. | CM/L-3533 1973-09-05 | Andhra Steel Corpn., Bangalore | Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1973 | S.O. 1389 dated 1975-05-03 | Deferred after 1978-11-30 |
| 134. | CM/L-3546 1973-09-19 | Rainbow Surgical Dressing Mfg. Co., Ahmedabad | Handloom cotton gauze, absorbent— IS : 758—1969 | S.O. 1389 dated 1975-05-03 | Deferred after 1978-09-30 |
| 135. | CM/L-3806 1974-04-16 | Plastic. Moulders Ltd., Calcutta | High density polythelene pipes for potable water supplies— IS : 4984—1972 | S.O. 4695 dated 1975-11-01 | Deferred after 1978-05-31 |
| 136. | CM/L-341 1974-05-16 | Union Pesticides, Vidisha | Malathion EC— IS : 2567—1973 | S.O. 4695 dated 1975-11-01 | Deferred after 1978-08-15 |
| 137. | CM/L-3853 1974-06-14 | Kumar Iron & Steel P. Ltd., Gauhati-5 | Structural steel (Standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. 4703 dated 1975-11-01 | Deferred after 1978-09-30 |
| 138. | CM/L-3854 1974-06-14 | -do- | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | S.O. 4703 dated 1975-11-01 | Deferred after 1978-09-30 |
| 139. | CM/L-3961 1974-09-23 | Motilal Pesticides (India), Mathura | Malathion EC— IS : 2567—1973 | S.O. 1762 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-09-30 |
| 140. | CM/L-3989 1974-10-14 | Kumardhubi Engg. Works Ltd., Kumardhubi (Bihar) | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. 1763 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-10-15 |
| 141. | CM/L-3990 1974-10-14 | -do- | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | S.O. 1763 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-10-15 |
| 142. | CM/L-3991 1974-10-14 | -do- | Carbon steel cast billet ingots for re-rolling into structural steel (standard quality)— IS : 6914—1973 | S.O. 1763 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-10-15 |
| 143. | CM/L-3992 1974-10-14 | -do- | Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1975 | S.O. 1763 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-10-15 |
| 144. | CM/L-4011 1974-10-29 | Arun Engg. Industries P. Ltd., Bombay | Flameproof enclosure of electrical apparatus— IS : 2148—1968 | S.O. 1763 dated 1976-05-29 | Deferred after 1978-10-31 |
| 145. | CM/L-4073 1974-11-28 | Kohinoor Paints P. Ltd., Amritsar | Putty for use on window window frames— IS : 419—1967 | S.O. 2022 dated 1976-06-19 | Deferred after 1978-11-15 |
| 146. | CM/L-4147 1975-01-14 | Kumardhubi Engg. Works Ltd., Kumardhubi (Bihar) | Steel ingots and billets for production of steel wire for the manufacture of wood screws— IS : 8053—1976 | S.O. 2465 dated 1976-07-10 | Deferred after 1978-10-15 |
| 147. | CM/L-4148 1975-01-14 | -do- | Steel ingots and billets for the production of wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process)— IS : 8057—1776 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 148. | CM/L-4149 1975-01-14 | -do- | Steel ingots and billets for the production of hard drawn steel wire for upholstery springs— IS : 8056—1976 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 149. | CM/L-4369 1975-05-09 | Maharashtra Brass & Metal Products, Bombay | Cast copper alloy screw-down bib taps and stop valves for water | S.O. 3523 dated 1976-10-16 | Deferred after 1978-11-15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | services—<br>IS : 781—1957 | | |
| 150. | CM/L-4381<br>1975-05-15 | Gansons P. Ltd., Bombay | Domestic gas stoves for use with liquified petroleum gases—<br>IS : 4246—1972 | S.O. 3623 dated 1976-10-16 | Deferred after 1978-11-15 |
| 151. | CM/L-4387<br>1975-05-15 | Maharashtra Brass & Metal Products, Bombay | Ball valves (horizontal plunger type) including floats for water supply purposes—<br>IS : 1703—1968 | S.O. 3623 dated 1976-10-16 | Deferred after 1978-11-15 |
| 152. | CM/L-4399<br>1975-05-29 | Kumardhubi Engg. Works Ltd., Kumardhubi (Bihar) | Steel ingots and billtets for the production of volute and helical springs (for railway rolling stock)—<br>IS : 8052—1976 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 153. | CM/L-4400<br>1975-05-29 | -do- | Steel ingots and billets for the procuction of volute, helical and laminated springs for automotic Suspension<br>IS : 8051—1976 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 154. | CM/L-4401<br>1975-05-29 | -do- | Steel ingots and billets for the manufacture of lam inated springs (Railway rolling stock)<br>IS : 8054—1976 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 155. | CM/L-4402<br>1975-05-29 | -do- | Steel ingots and billets for the product ion of spring washers—<br>IS : 8055—1976 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 156. | CM/L-4556<br>1975-08-11 | Northern Minerals P. Ltd., Gurgaon | Malathion EC—<br>IS : 2567—1973 | S.O. 428 dated 1977-02-25 | Deferred after 1978-08-15 |
| 157. | CM/L-4642<br>1975-09-12 | Velumani Engg. Industry Coimbatore | Grey iron castings—<br>IS : 210—1970 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Deferred after 1978-09-15 |
| 158. | CM/L-4643<br>1975-09-12 | Kohinoor Rubber Works, Calcutta | Safety rubber canvas boots for miners—<br>IS : 3976—1967 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Deferred after 1978-09-15 |
| 159. | CM/L-4677<br>1975-09-29 | Kilpest P. Ltd., Bhopal | Endosulfan EC—<br>IS : 4323—1967 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Deferred after 1978-09-30 |
| 160. | CM/L-4691<br>1975-09-29 | Maharashtra Brass & Metal Products, Bombay | Pillataps—<br>IS : 1795—1974 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Deferred after1978-11-15 |
| 161. | CM/L-4692<br>1975-09-29 | Oriental Engg. Works P. Ltd., Yamunanagar | Sluice valves for water works purposes—<br>IS : 780—1969 | S.O. 832 dated 1977-03-19 | Deferred after 1978-10-15 |
| 162. | CM/L-4718<br>1975-10-15 | Luz Electricals P. Ltd., Calcutta | Surgical urubber gloves—<br>IS : 4148—1968 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-10-15 |
| 163. | CM/L-4720<br>1975-10-15 | Star Steel P. Ltd., Bangalore | Steel ingots and billets for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock)—<br>IS : 8054—1976 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 164. | CM/L-4721<br>1975-10-15 | -do- | Steel ingots and billets for production of steel wire for the manufacture of wood screws—<br>IS : 8053—1976 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 165. | CM/L-4726<br>1975-10-15 | V.M. Industrial Corpn., Bombay | Flushing cisterns for water closets and urinals—<br>IS : 774—1971 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 166. | CM/L-4760 1975-10-29 | Dalima Biscuits Ltd., Rajpura | Wafers— IS : 2397—1972 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-09-30 |
| 167. | CM/L-4761 1975-10-29 | Spun Rubber Industries, Kanpur | Moulded solid rubber soles and heels— IS : 5676—1970 | -do- | Deferred after 1978-10-31 |
| 168. | CM/L-4762 1975-10-29 | Sri Ambica Metal Works, Calcutta, | Domestic gas stove for use with liquified petroleum gases— IS : 4246—1972 | -do- | Deferred after 1978-10-31 |
| 169. | CM/L-4765 1975-10-31 | United Fertilizers Industries, Thana. | DDT WDPC— IS : 565—1975 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-10-31 |
| 170. | CM/L-4766 1975-10-31 | -do- | Malathion EC— IS : 2567—1973 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-10-31 |
| 171. | CM/L-4778 1975-10-31 | Heman Oil Engines P. Ltd., Kolhapur. | Performance of constant speed internal combustion engine for general purpose— IS : 1601—1960 | S.O. 1148 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-10-31 |
| 172. | CM/L-4791 1975-11-24 | Electrical Equipment Factory, Ranchi. | Three phase inducation motors— IS : 325—1970 | S.O. 1147 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-11-15 |
| 173. | CM/L-4802 1975-11-24 | Coromandal Indag Products P. Ltd., Madras. | Carbaryl DP— IS : 7122—1973 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 174. | CM/L-4803 1975-11-24 | Bitumen Products (India) Calcutta. | Bitumen felts for waterproofing and damp proofing— IS : 1322—1970 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 175. | CM/L-4804 1975-11-24 | Andhra Steel Corpn. Ltd. Bangalore. | Steel for volute, helical and laminated springs for automotive suspension IS : 3431—1965 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 176. | CM/L 4805 1975-11-23 | do | Steel ingotts and billets for the production of laminated springs (railway rolling stock)— IS : 8054—1976 | do | Deferred after 1978-11-30 |
| 177. | CM/L-4806 1975-11-24 | Andhra Steel Corpn Ltd., Bangalore. | Steel ingots and billets for production of spring washers— IS : 8055—1976 | S.O. 1147 dated 1977-04-16 | Deferred after 1978-11-30 |
| 178. | CM/L-4807 1975-11-24 | -do- | Steel ingots and billets for the production of volute and helical springs (for railway rolling stock)— IS : 8052—1976 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 179. | CM/L-4826 1975-11-24 | Sehgal Sanitary Fittings P. Ltd., Jullundur. | Ferruels for water services— IS : 2692—1964 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 180. | CM/L-4836 1975-11-24 | Usha Paper Industries, Calcutta. | Laminated jute bags for packing fertilizers— IS : 7406—1974 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 181. | CM/L-4843 1975-11-26 | Singh Alloys & Steel Ltd., Calcutta. | Carbon steel cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1973 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 182. | CM/L-4849 1975-11-27 | Bokaro Steel Plant, Bokaro City. | Hot-rolled steel plate (upto 6 mm) for the manufacture of low pressure gas cylinders— IS : 6240—1976 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 183. | CM/L-4869 1975-12-04 | Bharat Laminating Corpn. Calcutta. | Laminated jute bags for packing fertilizers— IS : 7406—1974 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-11-30 |
| 184. | CM/L-4873 1975-12-04 | Kant Laminating Industries, Calcutta. | Laminated Jute bags for packing fertilizers— IS : 7406—1974 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 185. | CM/L-4875 1975-12-04 | Indian Lamination Indus. P. Ltd., Calcutta. | Laminated jute bags for packing fertilizers— IS : 7406—1974 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-11-30 |
| 186. | CM/L-4883 1975-12-12 | Andhra Steel Corpn. Ltd., Bangalore. | Steel ingots and billets for production of steel wire for the manufacture of wood screws— IS : 8053—1976 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-11-30 |
| 187. | CM/L-4896 1975-12-12 | -do- | Steel ingots and billets for the production of wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process)— IS : 8057—1969 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-11-30 |
| 188. | CM/L-4904 1975-12-17 | Shivalik Agro Chemicals, Mohali. | DDT EC— IS : 633—1975 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-12-15 |
| 189. | CM/L-4905 1975-12-17 | -do- | Endosulfan EC— IS : 4323—1967 | S.O. 3083 dated 1977-10-08 | Deferred after 1978-12-15 |
| 190. | CM/L-5119 1976-04-19 | Alvittas Elects. P. Ltd., Madras. | Hard-drawn stranded and steel cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS : 398—1961 | S.O. 314 dated 1979-01-27 | Deferred after 1978-03-31 |
| 191. | CM/L-5302 1976-06-05 | Star Steel P. Ltd., Bangalore. | Carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings— IS : 1875—1971 | — | Deferred after 1978-11-15 |
| 192. | CM/L-5323 1976-06-15 | Krishi Rasayan, P.O. Ranital. | Malathion EC— IS : 2567—1973 | — | Deferred after 1978-06-30 |
| 193. | CM/L-5382 1976-08-02 | Orient Wire Ropes, Indore. | Steel wire ropes for general engineering purposes IS : 2266—1970 | S.O. 3548 dated 1979-10-20 | Deferred after 1978-07-31 |
| 194. | CM/L-5406 1976-08-02 | Bengal Cement Research Laboratory, Calcutta. | Portland pozzolana cement— IS : 1489—1967 | -do- | Deferred after 1978-07-15 |
| 195. | CM/L-5479 1976-09-06 | Aceebeen Steel P. Ltd., Yamunanagar. | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. 359 dated 1979-01-20 | Deferred after 1978-08-31 |
| 196. | CM/L-5508 1976-09-20 | Kissan Chemical (Regd.) Chandigarh. | Malathion EC— IS : 2567—1973 | S.O. 3549 dated 1979-10-20 | Deferred after 1978-09-15 |
| 197. | CM/L-5509 1976-09-20 | Mohatta & Hackel Ltd., Bombay. | Hard-drawn stranded and steel cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS : 398—1976 | -do- | Deferred after 1978-09-30 |
| 198. | CM/L-5519 1976-09-24 | Radha Engg. Industry, Coimbatore. | Three phase induction motors— IS : 325—1970 | -do- | Deferred after 1978-09-30 |
| 199. | CM/L-5532 1976-09-24 | Ashoka Steel Industries, Howrah. | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | -do- | Deferred after 1978-09-30 |
| 200. | CM/L-5533 1976-09-24 | -do- | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | -do- | Deferred after 1978-09-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | CM/L-5543 1976-10-04 | Prakash Trading Co., Coimbatore. | Tea-chestmetal fittings— IS : 10 (Part IV)—1971 | S.O. 3550 dated 1979-10-20 | Deferred after 1978-09-30 |
| 202. | CM/L-5550 1976-10-04 | Farmers Pesticides, Proddatur (A.P.) | DDT DP— IS : 564—1975 | -do- | Deferred after 1978-09-30 |
| 203. | CM/L-5558 1976-10-04 | Hindustan Bobbin Industries, Calcutta. | Shuttles for jute broad-looms— IS : 2910—1971 | S.O. 3550 dated 1979-10-20 | Deferred after 1978-09-30 |
| 204. | CM/L-5563 1976-10-12 | Srinivasa Plant Protection Idus, Guntur. | BHC (HCH) DP— IS : 561—1972 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 205. | CM/L-5572 1976-10-12 | Shah Medical & Surgical Co. Ltd., Baroda. | Sphygmomanometer aneroid type— IS : 7652—1975 | -do- | Deferred after 1978-10-15 |
| 206. | CM/L-5576 1976-10-25 | Beekay Pesticides P. Ltd, Thana | Endosulfan EC— IS : 4323—1967 | -do- | Deferred after 1978-10-31 |
| 207. | CM/L-5599 1976-10-29 | Govane & Patin P. Ltd., Miraj (Maharashtra) | Sluice valves for water works purposes— IS : 780—1969 | -do- | Deferred after 1978-10-31 |
| 208. | CM/L-5606 1976-10-29 | Kissan Pesticides & Chemicals, Bangalore. | BHC (HCH) DP— IS : 561—1972 | -do- | Deferred after 1978-10-31 |
| 209. | CM/L-5613 1976-11-02 | Jai Chemicals, Faridabad | BHC (HCH) WDPC— IS : 562—1972 | S.O. 3761 dated 1979-11-17 | Deferred after 1978-11-15 |
| 210. | CM/L-5614 1976-11-02 | -do- | DDT WDPC— IS : 565—1972 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 211. | CM/L-5616 1976-11-05 | Rightaids (Bombay) P. Ltd., Bombay-400060 | Dye-based fountain pen inks blue, green, violet, black and red— IS : 1221—1971 | -do- | Deferred after 1978-11-15 |
| 212. | CM/L-5637 1976-11-17 | Sushila Industries, P.O. P.O. Rajgangpur. | Flushing cisterns for water closets and urinals (valveless spihonic type) IS : 774—1971 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 213. | CM/L-5639 1976-11-17 | Super India Metal Co., (P) Ltd., Silchar | Tea chest plywood penals- IS : 10 (Part II)—1976 | S.O. 3761 dated 1179-11-17 | Deferred after 1978-11-30 |
| 214. | CM/L-5646 1976-11-17 | Sant Brass Metal Works, Jullundur | Sand cast brass screw—down bib taps and stop taps for water services— IS : 781—1967 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 215. | CM/L-5652 1976-11-17 | Dipak Vegetable oil Industry P. Ltd., Manavadur | 18-Litre square tins— IS : 916—1975 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 216. | CM/L-5665 1976-11-30 | Farmers Pest Control P. Ltd., Guntur | BHC(HCH) WDPC— IS : 562—1972 | -do- | Deferred after 1978-11-30 |
| 217. | CM/L-5692 1976-12-10 | Ashok Steel Castings, UNNAO (U.P.) | Flushing cisterns for water closets and urinals (valveness siphonic type)— IS : 774—1971 | S.O. 3762 dated 1979-11-17 | Deferred after 1978-11-30 |
| 218. | CM/L-5700 1976-12-10 | Hydcrabad Alm. Industries, Hydelabad. | All aluminium conductors and ACSR conductors— IS : 398—1961 | -do- | Deferred 1978-12-15 |
| 219. | CM/L-5734 1976-12-24 | Punjab Iron & Steel Co. P. Ltd. Jullundur Cantt. | Carbon steel billets, blooms slabs and bars for forgings— IS : 875—1971 | -do- | Deferred 1978-12-15 |
| 220. | CM/L-5862 1977-02-03 | Shree Ganesh Steel Rolling Mills, Madras | Structural steel (standard (quality)— IS : 226—1975 | — | Deferred after 1978-01-15 |
| 221. | CM/L-5939 1977-03-04 | Bihar Foundry & Castings Ltd., Ranchi | Carbon steel cast billet ingots for rerolling into structural steel (standard quality) IS : 6914—1973 | — | Deferred after 1978-09-30 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 222. | CM/L-6064 1977-04-25 | Assam Tube Co. Ltd., Gauhati | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | S.O. — | Deferred after 1978-04-30 |
| 223. | CM/L-6385 1977-08-31 | J.D. Jones & Co. Ltd., Jamshedpur (Bihar) | BHC (HCH) DP— IS : 561—1972 | — | Deferred after 1978-08-31 |
| 224. | CM/L-6407 1977-09-15 | Sri Ramkrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore | Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural applications— IS : 7538—1975 | — | Deferred after 1978-09-15 |
| 225. | CM/L-6414 1977-09-21 | Bhartiaya Ispat Udyog P. Ltd., Patna | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | — | Deferred after 1978-09-30 |
| 226. | CM/L-6415 1977-09-21 | -do- | Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 | — | Deferred after 1978-09-30 |
| 227. | CM/L-6429 1977-09-26 | Accebeen Steel P. Ltd., Yamunanagar | Cold twisted steel bars for concrete reinforcement IS : 1786—1966 | — | Deferred after 1978-09-30 |
| 228. | CM/L-6445 1977-10-07 | Bhartiya Metal Smelting & Refining Corporation, Madras | Rosin-cored solder wire activated and non-activated (non-corrosive)— IS : 1921—1975 | — | Deferred after 1978-10-15 |
| 229. | CM/L-6449 1977-10-10 | Tracto Auto industries, Kanpur | 18 Litre square tins— IS : 916—1975 | — | Deferred after 1978-09-30 |
| 230. | CM/L-6451 1977-10-12 | Beekay Pesticides P. Ltd., Thana | Aldrin EC— IS : 1307—1973 | — | Deferred after 1978-10-15 |
| 231. | CM/L-6461 1977-10-19 | Marson (India) Industries, Bombay | Cold tar food colour preparations— IS : 5346—1975 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 232. | CM/L-6464 1977-10-19 | Poddar Projects Ltd., Hyderabad | Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 233. | CM/L-6469 1977-10-19 | Shyam Timber Products, Assam | Teachest plywood panels— IS : 10 (Part II)—1976 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 234. | CM/L-6471 1977-10-19 | Mehra Electric Co., Agarpara | Hand-drawn stranded aluminium cored aluminium conductors for overhead power, transmission purposes— IS : 398—1976 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 235. | CM/L-6472 1977-10-19 | Bestobell India Ltd., Calcutta | Flameproof enclosures of electrical apparatus— IS : 2148—1968 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 236. | CM/L-6480 1977-10-26 | Nirmal Kumar Rungta & Co., Thana | Cutting oil, neat— IS : 3065—1970 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 237. | CM/L-6485 1977-10-28 | Fort William Co. Ltd., Calcutta | Cold drawn stress— relieved wire— IS : 1785 (Part I)— 1966 | — | Defferred after 1978-10-31 |
| 238. | CM/L-6486 1977-10-28 | Prakash Udyog, Patna | Protective helmets for scooter and motor cycle riders— IS : 4151—1976 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 239. | CM/L-6491 1977-10-31 | Nahan Foundry Ltd., Nahan (H.P.) | Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application— IS : 7538—1975 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 240. | CM/L-6498 1977-10-31 | Premier Enterprises, Howarh | Tea chest metal fittings— IS : 10 (Part IV)—1976 | — | Deferred after 1978-10-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241. | CM/L-6499 1977-10-31 | EMC Enterprises, Calcutta | Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes— IS : 6595—1972 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 242. | CM/L-6501 1977-10-31 | Utkal Pesticides & Chemicals, Behrampur | Endosulfan EC— IS : 4323—1967 | — | Deferred after 1978-10-31 |
| 243. | CM/L-6542 1977-11-23 | Zink Metal & Industries, Calcutta | Soft solder— IS : 193—1966 | — | Deferred after 1978-11-30 |
| 244. | CM/L-6553 1977-11-24 | National Tar Products, Calcutta | Cresote and anthracene oil for use as wood preservatives— IS : 218—1961 | — | Deferred after 1978-11-30 |
| 245. | CM/L-6557 1977-11-24 | Beekay Pesticides P. Ltd., Thana | Malathion EC— IS : 2567—1973 | — | Deferred after 1978-11-30 |
| 246. | CM/L-6566 1977-11-24 | United Tapes, Rourkela | Typewriter ribbons— IS : 4174—1967 | — | Deferred after 1978-11-30 |
| 247. | CM/L-6572 1977-12-08 | Acripods India, Allahabad | Industrial safety helmets— IS : 2925—1975 | — | Deferred after 1978-12-15 |
| 248. | CM/L-6618 1977-12-30 | Universal Petro-chemicals Ltd., Calcutta | Cutting oil, soluble— IS : 1115—1973 | — | Deferred after 1978-12-31 |

[No. CMD/13 : 14]

A. P. BANERJI, Additional Director General

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1983

क.० आ.० 3945 —व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिसे व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए जाने का प्रस्ताव है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 20 दिसम्बर, 1983 को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो विनिर्दिष्ट तारीख से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप संशोधन

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह (संशोधन) नियम, 1983 है ।

2. व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8-(1) उपनियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण या अन्य दस्तावेजों या कोई फीस, जोकि अधिनियम या इन नियमों द्वारा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री में, तामील किए जाने, उसमें छोड़ दिए जाने या भेजे जाने या दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में तामील की जाएंगी या छोड़ी जाएंगी या उसको भेजी जाएंगी या दी जाएंगी ।"

(2) दस्तावेजों या कोई फीस, जोकि अधिनियम या इन नियमों द्वारा भेजे जाने या दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय या प्रधान कार्यालय में निम्नलिखित मामलों में भेजी जा सकेंगी या दी जा सकेंगी,

(क) व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किए गए आवेदन के संबंध में संसूचनाएं,

(ख) व्यापार चिन्ह पत्रिका में विज्ञापन के लिए अधिक स्थान फीस ; और

(ग) प्ररूप व्या० चि० 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 50, 54, 55, 58 और 59 में आवेदन पत्र या प्रमाण-पत्र ।

3 उक्त नियमों के नियम 9 में "जहां कि कोई आवेदन" शब्दों के स्थान पर "नियम 8 के उपबंधों के अधीन जहां कि कोई आवेदन" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) में "उस सूरत में जिसमें कि वह बात वस्तु की बाबत है " शब्दों का लोप किया जाएगा ।

5 उक्त नियमों के नियम 47 में, —

(क) "जैसा कि नियम 46 में वर्णित है" शब्दों के पश्चात् "अधिक स्थान के लिए यदि कोई है, विहित फीस देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "परन्तुक" का लोप किया जाएगा ।

6 उक्त नियमों के नियम 62 के उपनियम (1) में "और प्ररूप व्या० चिन्ह-11 पर विहित फीस दे दी जाने पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 104 में "उस संबंध में रजिस्ट्रार" शब्दों के पश्चात् "अधिक स्थान के लिए यदि कोई है, आवेदक से फीस सहित" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 138 और नियम, 139 का लोप किया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 140 में, —

(क) उपनियम (1) में "व्या० चि०-53", अक्षरों और अंकों के स्थान पर "व्या० चि०-1, "अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) उपनियम (3) में, "प्रारूप व्या० चि०-53", शब्द अक्षरों और अंकों के स्थान पर "या" शब्द रखा जाएगा ।

10 उक्त नियमो के नियम 141, 142 और 143 का लोप किया जाएगा ।

11. उक्त नियमो की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्रथम अनुसूची

(नियम 11 देखिए)

फीस

| प्रविष्टि सं० | किस पर देय | रकम रु० पै० | तत्संबंधी प्रारूप सं० |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर जिनको अन्यथा प्रभारित नही किया जाता है । (धारा 18) | 200.00 | व्या०चि० 1 |
| 2. | किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह से भिन्न, वस्तु चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे आवेदन पर जिसमें आत्यंतिक रूप से नियम 140 के अधीन पांचवी अनुसूची की एक मद में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए संख्याएं या अक्षर या उसका कोई समुच्चय है। | 200.00 | व्या० चि० 1 |
| 3. | एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए धारा 15 के अधीन व्यापार चिन्हो की आवलिका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किए गए आवेदनों पर। | 200.00 | व्या० चि० 1 |
| 4. | एक ही वर्ग मे सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए धारा 47 के अधीन (प्रति रक्षात्मक व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किए गए आवेदनों पर । | 500.00 | व्या० चि० 3 |
| 5. | एक ही वर्ग में सम्मिलित माल के विनिर्देश के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 62 के अधीन किए गए आवेदनों पर। | 250.00 | व्या० चि० 4 |
| 6. | विनिश्चय के आधारो का उल्लेख करने के लिए नियम 41 (1) के अधीन किए गए अनुरोध पर । | 50.00 | व्या० चि० 15 |
| 7. | ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है धारा 21 (1) के अधीन विरोध की सूचना पर । | 250.00 | व्या० चि० 5 |
| 8. | धारा 21 (1) के अधीन विरोध की सूचना फाइल करने के लिए समय बढ़ाए जाने के लिए किए गए आवेदन पर । | 20.00 | व्या० चि० 14 |
| 9. | ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है । धारा 21 के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में या प्रत्येक व्यापार चिन्ह की बाबत धारा 46, 47 (4) और 56 में से किसी के अधीन किसी आवेदन के उत्तर में अथवा प्रत्येक आवेदन या सपरिवर्तन के लिए जिसका विरोध किया गया है, धारा 58 या नियम 105 के अधीन विरोध की सूचना के उत्तर में किए गए किसी प्रतिकथन पर । | 30.00 | व्या० चि० 6 |
| 10. | सम्बद्ध कार्यवाहियो के प्रत्येक पक्षकार द्वारा धारा 21, 46 या (4) 56 और 58 में से किसी के अधीन अथवा नियम 105 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना दिए जाने पर । | 30.00 | व्या० चि० 7 |
| 11. | ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है धारा 64(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष विरोध की सूचना पर । | 250.00 | व्या० चि० 8 |
| 12. | ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है धारा 64 (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष विरोध की सूचना के उत्तर में किसी प्रतिकथन पर । | 50.00 | व्या० चि० 9 |
| 13. | क्रमशः आवेदक और विरोधी पक्षकार द्वारा धारा 64 (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष विरोध की प्रत्येक सुनवाई में हाजिर होने के आशय की सूचना दिए जाने पर। | 30.00 | व्या० चि० 10 |
| 14. | रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हो के बीच संगम का विघटन करने के लिए धारा 16 (4) के अधीन किए गए आवेदन पर । | 20.00 | व्या० चि० 14 |
| 15. | अन्तिम रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान पर व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 25 के अधीन नवीकरण के लिए जिसको अन्यथा प्रभारित नही किया जाता है । | 200.00 | व्या० चि० 12 |
| 16 | अन्तिम रजिस्ट्रीकरण के पर्यवसान पर व्यापार चिन्हो की आवलि के रजिस्ट्रीकरण के धारा 25 के अधीन नवीकरण के लिए— | 200.00 | व्या० चि० 12 |
| | पहली आवलि में के प्रथम दो चिन्हो के लिए । | 200.00 | व्या० चि० 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | आवलि में के प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 50 00 | |
| 17 | धारा 25 के अधीन प्रत्येक वर्ग में के सबध में एक से अधिक वर्ग में माल के लिए एक ही तारीख सहित एक ही प्रमाणत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए | 200 00 | व्या० चि० 12 |
| 18 | रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिन्ह को प्रत्यावर्तित करने के लिए धारा 25 (4) के अधीन किए गए आवेदन पर | 100 00 (प्रविष्टि स० 15, 16 और 17 में से किसी में विहित रूप में नवीकरण फीस हेतु) | व्या० चि० 13 |
| 19. | धारा 39 (2) के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर | 100.00 | व्या० चि० 17 |
| | समनुदेशिक किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रथम चिन्ह के लिए | | |
| | उस समनुदेशन में सम्मिलित उसी स्वत्वधारी के प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 20.00 | |
| 20 | धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए आवेदन पर — प्रथम चिन्ह के लिए | 100.00 | व्या० चि० 19 |
| | एक ही अन्तरण में सम्मिलित एक ही स्वत्वधारी के प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 20 00 | |
| 21 | उपयोग में के व्यापार चिन्ह की गुडविल के बिना समनुदेशन के विज्ञापन के लिए रजिस्ट्रार के निदेशार्थ धारा 41 के अधीन आवेदन पर—समनुदेशित प्रथम चिन्ह के लिए — | 60 00 | व्या० चि० 20 |
| | हक के उसी न्यागमन के मामले में समनुदेशित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 20 00 | |
| 22 | हक के न्यागमन की बाबत उपयोग में के व्यापार चिन्ह की गुडविल के बिना समनुदेशन के विज्ञापन के लिए धारा 41 के अधीन निर्देशार्थ आवेदन करने हेतु समय बढ़ाए जाने के लिए किए गए आवेदन पर— | | |
| | जो एक मास से अधिक नहीं है | 50 00 | व्या० चि० 21 |
| | जो दो मास से अधिक नहीं है | 100 00 | |
| | जो तीन मास से अधिक नहीं है | 150 00 | |
| 23. | किसी प्रमाणन व्यापार चिन्ह के समनुदेशन या पारेषण के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति के लिए धारा 42 के अधीन किए गए आवेदन पर | 100 00 | व्या० चि० 22 |
| 24. | एकल व्यापार चिन्ह के समनुदेशन या पारेषण की दशा में किसी पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 44 के अधीन आवेदन पर — यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर किया जाए— | 100.00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| | यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात् किन्तु 12 मास के पूर्व किया जाता है | 150.00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| | यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से 12 मास के भीतर किया जाता है। | 250 00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| 25. | एक ही नाम में रजिस्ट्रीकृत एक व्यापार चिन्ह से अधिक के किसी पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 44 के अधीन किए गए आवेदन पर जहां हक का न्यागमन प्रत्येक मामले में एक ही है — | | |
| | यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से 6 मास के भीतर किया जाता है वहां प्रथम चिन्ह के लिए | 100 00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| | प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए— | 20 00 | |
| | यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात किन्तु 12 मास के पूर्व किया जाता है वहां — | 150.00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | | |
| | प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए— | 30 00 | |
| | यदि वह स्वत्वधारिता के अर्जन की तारीख से 12 मास के अवसान के पश्चात् किया जाता है वहां— | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए— | 250 00 | व्या० चि० 23 या व्या० चि० 24 |
| | प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 50 00 | |
| 26 | एक समनुदेशन पर व्यापार चिन्ह के किसी पश्चात्वर्ती स्वत्वधारी के रूप में किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय बढ़ाए जाने हेतु धारा 45 (3) के अधीन किए गए आवेदन पर— | | |
| | जो 2 मास से अधिक नहीं है— | 10 00 | व्या० चि० 25 |
| | जो 4 मास से अधिक नहीं है— | 60.00 | |
| | जो 6 मास से अधिक नहीं है— | 90 00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | रजिस्टर के परिशोधन के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह के हटाए जाने के लिए धारा 46, 47(4) और धारा 56 में से किसी के अधीन किए गए आवेदन पर | 250.00 | व्या० चि० 26 |
| 28. | रजिस्टर के परिशोधन के लिए या रजिस्टर से व्यापार चिन्ह के हटाए जाने के लिए धारा 46, धारा 47 (4) और धारा 56 में किसी के अधीन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने की इजाजत के लिए नियम 96 के अधीन आवेदन पर | 100.00 | व्या० चि० 27 |
| 29. | ऐसे माल की बाबत रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जो उसके विनिर्देश के अन्तर्गत है, धारा 49 के अधीन आवेदन पर | 750.00 | व्या०चि० 28 |
| 30. | एक ही रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का वही रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जहां सभी व्यापार चिन्ह, माल की बाबत उसके सम्बन्धित विनिर्देश के अधीन एक ही रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के करार के अन्तर्गत आते है और जो प्रत्येक मामले मे एक जैसी शर्तों और निबंधनों के अधीन है, आवेदन पर—प्रथम चिन्ह के लिए | 750.00 | व्या० चि० 28 |
| | आवेदन में सम्मिलित स्वत्वधारी के प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए, और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के करार में — | 500.00 | |
| 31. | एक ही व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि में फेरफार करने के लिए धारा 52 (1) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन पर | 500.00 | व्या० चि० 29 |
| | जहां व्यापार चिन्ह एक ही रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के करार के अन्तर्गत आते है और वही रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता उनमें से प्रत्येक के संबंध में रजिस्ट्रीकृत है वहा — | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | 500.00 | |
| | आवेदन मे सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 250.00 | |
| 32. | एक व्यापार चिन्ह के किसी रजिस्ट्रीकृत उपभोगकर्ता की प्रविष्टि को रद्द करने के लिए धारा 52 (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन पर— | 50.00 | व्या० चि० 30 |
| | जहा आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह है वहा— | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | 50.00 | |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए— | 20.00 | |
| 33. | एक व्यापार चिन्ह के किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि को रद्द करने के लिए धारा 52 (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन आवेदन पर जहां आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह हैं, वहां— | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए— | 50.00 | |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए— | 20.00 | |
| 34. | किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टियों के फेरफार या रद्दकरण की किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के आशय की नियम 92 (2) के अधीन सूचना पर— | 100.00 | व्या० चि० 32 |
| 35. | किसी व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के नाम या वर्णन में वहां परिवर्तन करने के लिए जहा रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की स्वत्वधारिता में या पहचान मे कोई परिवर्तन नही हुआ है (वहा के सिवाय जहा कि आवेदन किसी लोक प्राधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है) धारा 57 के अधीन आवेदन पर | 50.00 | व्या० चि० 33 |
| | जहा आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह है, वहा | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | 50.00 | |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 20.00 | |
| 36. | किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह उपयोगकर्ता के पते की प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए धारा 57 के अधीन आवेदन पर जब तक कि वह नियम 98 (3) के अधीन फीस से छूट प्राप्त न हो— | 50.00 | व्या० चि० 34 |
| | जहां आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह है वहां— | | |
| | और जहां प्रत्येक मामले में पता एक ही है और वह एक ही रीति में परिवर्तित किया जाता है, वहा— | | |
| | प्रथम प्रविष्टि के लिए | 50.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए | 20.00 | |
| 37. | व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्व-धारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की भारत में सेवाओं के लिए पते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन पर—जहां आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह और प्रविष्टि की जाने वाली सेवाओं के लिए पता प्रत्येक मामले में एक ही है वहां— | 50.00 | व्या० चि० 50 |
| | प्रथम प्रविष्टि के लिए | 50.00 | व्या० चि० 50 |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए | 20.00 | |
| 38. | रजिस्टर में भारत में की सेवाओं के लिए पते की प्रविष्टि में परिवर्तन करने या उसके स्थान पर दूसरी प्रविष्टि रखने के लिए आवेदन पर जब तक कि वह नियम 98(3) के अधीन फीस से छूट प्राप्त न हो— | 50.00 | व्या०चि० 50 |
| | जहां आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह हैं और प्रत्येक मामले में पता एक ही है और उसमें एक ही रीति में परिवर्तन या उस प्रति-स्थापित किया गया है, | | |
| | वहां प्रथम प्रविष्टि के लिए— | 50.00 | |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य प्रति के लिए | 20.00 | |
| 39. | रजिस्टर में किसी व्यापार चिन्ह की प्रविष्टि या उसके किसी भाग को रद्द करने के लिए या कोई दावा छोड़ या त्यागने की प्रविष्टि करने के लिए धारा 57(1) के खण्ड (ग), (घ) या (ङ) के अधीन आवेदन पर— | 20.00 | व्या०चि० 35 या व्या०चि० 36 या व्या०चि० 37 |
| 40. | किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए धारा 58 के अधीन आवेदन पर (वहां के सिवाय जहां कि आवेदन किसी लोक प्राधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है— | 200.00 | व्या०चि० 38 |
| | जहां आवेदन के अन्तर्गत एक से अधिक व्यापार चिन्ह हैं और प्रत्येक मामले में किए जाने वाले परिवर्धन या परिवर्तन एक ही है वहां— | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | 200.00 | |
| | आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अन्य चिन्ह के लिए | 200.00 | |
| 41. | ऐसे प्रत्येक आवेदन के लिए जिसका विरोध किया गया है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह में परिवर्धन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन के लिए धारा 58(2) के अधीन विरोध की रचना पर— | 150.00 | व्या०चि० 39 |
| 42. | विनिर्देश के समय परिवर्तन के लिए धारा 59 के लिए आवेदन पर— | 100.00 | व्या०चि० 40 |
| 43. | रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के विनिर्देश या विनिर्देशों के संपरिवर्तन के लिए धारा 59(2) के अधीन विरोध की सूचना पर— | 150.00 | व्या०चि० 41 |
| | जहां चिन्हों को रजिस्टर में सहयुक्त व्यापार चिन्ह के रूप में प्रविष्ट किया जाता है और उनका एक ही विनिर्देश है वहां— | | |
| | प्रथम चिन्ह के लिए | 150.00 | |
| | विरोध की सूचना में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए | 20.00 | |
| 44. | किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के जमा किए गए विनियमन के परिवर्तन के लिए धारा 65 के अधीन आवेदन पर | 100.00 | व्या०चि० 42 |
| | जहां चिन्हों को रजिस्टर में सहयुक्त व्यापार चिन्ह के रूप में प्रविष्ट किया जाता है, वहां— | | |
| | एक रजिस्ट्रीकरण के विनियमों के लिए— | 100.00 | |
| | प्रत्येक अतिरिक्त प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के एक या सारतः एक ही विनियमों के लिए जिसका एक ही रीति में परिवर्तन किया गया है और जो एक ही आवेदन में सम्मिलित है— | 20.00 | व्या०चि०— |
| 45. | किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के जमा किए गए विनियमों में या एक ही रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के प्रमाणीकरण व्यापार चिन्हों में जहां जहां विनियम सारतः एक जैसे हैं, फेरफार करने के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण को हटाने या उसमें परिवर्तन करने के लिए धारा 69 के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन पर— | 100.00 | व्या०चि० 43 |
| 46. | एक ही वर्ग की बाबत नियम 24(1) के अधीन तलाशी के लिए | 50.00 | व्या०चि० 54 |
| 47. | एक ही वर्ग की बाबत व्यापार चिन्ह के लिए धारा 103 के अधीन रजिस्ट्रार की प्रारंभिक सलाह के लिए अनुरोध पर— | 50.00 | व्या०चि० 55 |
| 48. | धारा 115 के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध पर (धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र से भिन्न)— | 20.00 | व्या०चि० 46 |
| 49. | धारा 15 के अधीन व्यापार चिन्हों की आवलि के रजिस्ट्रीकरण के (धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र से भिन्न रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर— | 40.00 | व्या०चि० 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 50. | धारा 125(2) के अधीन रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की या किसी दस्तावेज की किसी प्रमाणित प्रति के लिए— | 20.00* *जमा टंकण शुल्क प्रविष्टि सं० 58 में यथा विहित । | व्या०चि० 46 |
| | दस्तावेज की प्रविष्टि के टंकण प्रभारों के लिए अनुरोध पर— | | |
| 51. | एक ही व्यापार चिन्ह की बाबत नियम 123 के अधीन विधिमान्यता प्रमाण-पत्र के टिप्पण को रजिस्टर में प्रविष्ट करने और उसका विज्ञापन करने के अनुरोध पर | 20.00 | व्या०चि० 47 |
| 52. | लिपिकीय त्रुटि को सही करने के लिए या संशोधन के लिए अनुरोध पर जहां के सिवाय जहां कि ऐसा अनुरोध किसी लोक प्राधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है जिस पर अन्यथा कोई प्रभार नहीं लिया जाता है — | 20.00 | ,, ,, 16 |
| 53. | धारा 101 के अधीन समय के बढ़ाए जाने के लिए आवेदन पर (जो ऐसा समय नहीं है जिसका अभिव्यक्त अधिनियम में उपबन्ध किया गया हो या जो नियम 81 या नियम 82(4) द्वारा विहित किया गया हो) | 20.00 | ,, ,, 46 |
| 54. | धारा 97(ग) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर— | 100.00 | ,, ,, 57 |
| 55. | किसी प्रतिवादित कार्यवाही में के किसी अन्तर्वर्ती मामले में रजिस्ट्रार के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए पिटीशन पर जिन पर अन्यथा प्रभार नहीं लिया जाता है । | 50.00 | |
| 56. | नियम 50 के अधीन चिन्ह के विज्ञापन की विशिष्टियों के लिए रजिस्ट्रार को किए गए अनुरोध पर— | 20.00 | ,, ,, 58 |
| 57. | प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए धारा 25(1) में वर्णित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए | 20 00 | |
| 58. | एक पृष्ठ से अधिक प्रत्येक पृष्ठ या उसके भाग के लिए दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए— | 1 00 रु० प्रति पृष्ठ (न्यूनतम राशि 5 00 रु०) | |
| | व्या० चि० 40 के लिए | | |
| | दस्तावेजों की फोटो प्रति या टंकित प्रति के लिए | | |
| 59. | प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति या और प्रति के लिए अनुरोध पर— | 50.00 | व्या०चि० 1 |
| 60 | ऐसे मामलों में जहां व्यापार चिन्ह के लिए मुद्रण ब्लाक 5 सेंटीमीटर से चौड़ा या गहरा है वहां विज्ञापन के लिए पत्रिका में अतिरिक्त स्थान के लिए— | | |
| | चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर से अधिक 10 सेंटीमीटर या उसके भाग तक के लिए | 50.00 | |
| | गहराई में पांच सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर या उसके भाग के लिए— | 50.00 | |
| 61. | नियम 151 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर— | 50.00 | व्या०चि० 1 |
| 62 | नियम 153 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए | 100.00 | |
| 63. | नियम 154 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रथम अप्रैल को प्रत्येक वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष को छोड़कर) किए जाने वाले संदाय— | 100.00 | व्या०चि० |
| | ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसको एक अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत किया गया है, रजिस्ट्रीकरण की फीस के साथ प्रथम वर्ष के लिए किए जाने वाला संदाय | 100.00 | |
| | विशेष टिप्पण : इस प्रयोजन के लिए वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होगा और वह आगामी मार्च के 31वें दिन को समाप्त होगा | | |
| 64. | नियम 156 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को प्रत्यावर्तित करने के लिए आवेदन— | 100.00 प्रविष्टि संख्या 63 के अधीन जारी रखने की फीस सहित । | व्या०चि० 2 |
| 65. | नियम 157 के अधीन व्यापार चिन्ह अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर— | 20.00 | व्या०चि० 3 |

12. उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची में :

(क) प्ररूपों की सूची में

(1) प्ररूप व्या०चि० 1 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "1 और 2" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 से लेकर 3" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(2) प्ररूप व्या०चि० 2 का लोप किया जाएगा ।

(3) प्ररूप व्या०चि० 3 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "3" अंक के स्थान पर "4" अंक रखा जाएगा ।

(4) प्ररूप व्या०चि० 4 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "4 और 5" अंक और शब्दों के स्थान पर "5" अंक रखा जाएगा ।

(5) प्ररूप व्या०चि० से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "10" अंक के स्थान पर "7" अंक रखा जाएगा ।

(6) प्ररूप व्या०चि० 6 में संबन्धित चौथे स्तम्भ में "12" अंक के स्थान पर "9" अंक रखा जाएगा।

(7) प्ररूप व्या०चि० 7 में सबन्धित चौथे स्तम्भ में "13" अंक के स्थान पर "10" अंक रखा जाएगा।

(8) प्ररूप व्या०चि० 8 में सबन्धित चौथे स्तम्भ में "14" अंक के स्थान पर "11" अंक रखा जाएगा।

(9) प्ररूप व्या०चि० 9 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "15" अंक के स्थान पर "12" अंक रखा जाएगा।

(10) प्ररूप व्या०चि० 10 में सबन्धित चौथे स्तम्भ में "16" अंक के स्थान पर "13" अंक रखा जाएगा।

(11) प्ररूप व्या०चि० 11 से संबन्धित प्रविष्टियों के स्तम्भ 1 से लेकर 4 का लोप किया जाएगा।

(12) प्ररूप व्या०चि० 12 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "27" से लेकर "29" अंकों और शब्द के स्थान पर "15" से लेकर "17" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(13) प्ररूप व्या०चि० 13 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "30" अंक के स्थान पर "18" अंक रखा जाएगा।

(14) प्ररूप व्या०चि० 14 से संबन्धित चौथे मामले में "26" अंक के स्थान पर "14" अंक रखा जाएगा।

(15) प्ररूप व्या० चि० 15 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "9" "अंक" के स्थान पर "6" अंक रखा जाएगा।

(16) प्ररूप व्या०चि० 16 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "64" अंक के स्थान पर "52" अंक रखा जाएगा।

(17) प्ररूप व्या०चि० 17 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "31" अंक के स्थान पर "19" अंक रखा जाएगा।

(18) प्ररूप व्या०चि० 19 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "32" अंक के स्थान पर "20" अंक रखा जाएगा।

(19) प्ररूप व्या०चि० 20 से सबन्धित चौथे में स्तम्भ में "33" अंक के स्थान पर "21" अंक रखा जाएगा।

(20) प्ररूप व्या०चि० 21 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में 34 अंक के स्थान पर "22" अंक रखा जाएगा।

(21) प्ररूप व्या०चि० 22 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "35" अंक के स्थान पर "23" अंक रखा जाएगा।

(22) प्ररूप व्या०चि० 23 से संबन्धित चौथे स्तम्भ "36""37" अंकों के स्थान पर "24""25" अंक रखे जाएंगे।

(23) प्ररूप व्या०चि० 24 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "36" "37" अंकों के स्थान पर "24","25" अंक रखे जाएंगे

(24) प्ररूप व्या०चि० 25 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "38" अंक के स्थान पर "26" अंक रखा जाएगा।

(25) प्ररूप व्या० चि० 26 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "39" अंक के स्थान पर "27" अंक रखा जाएगा।

(26) प्ररूप व्या०चि० 27 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "40" अंक के स्थान पर "29" अंक रखा जाएगा।

(27) प्ररूप व्या०चि० 28 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "41, 42" अंकों के स्थान पर "29, 30 अंक रखे जाएंगे।

(28) प्ररूप व्या०चि० 29 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "43" अंक के स्थान पर "31" अंक रखा जाएगा।

(29) प्ररूप व्या०चि० 30 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "44" अंक के स्थान पर "32" अंक रखा जाएगा।

(30) प्ररूप व्या०चि० 31 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "45" अंक के स्थान पर "33" अंक रखा जाएगा।

(31) प्ररूप व्या०चि० 32 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में अंक "46" के स्थान पर "34" अंक रखा जाएगा।

(32) प्ररूप व्या०चि० 33 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "47" अंक के स्थान पर "35" अंक रखा जाएगा।

(33) प्ररूप व्या०चि० 34 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "48" अंक के स्थान पर "36" अंक रखा जाएगा।

(34) प्ररूप व्या०चि० 35 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "51" अंक के स्थान पर "39" रखा जाएगा।

(35) प्ररूप व्या०चि० 36 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "51" अंक के स्थान पर "39" अंक रखा जाएगा।

(36) प्ररूप व्या०चि० 37 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "52" अंक के स्थान पर "39" अंक रखा जाएगा।

(37) प्ररूप व्या०चि० 38 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "52" अंक के स्थान पर "40" अंक रखा जाएगा।

(38) प्ररूप व्या०चि० 39 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "53" अंक के स्थान पर "41" अंक रखा जाएगा।

(39) प्ररूप व्या०चि० 40 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "54" अंक के स्थान पर "42" अंक रखा जाएगा।

(40) प्ररूप व्या०चि० 41 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "55" अंक के स्थान पर "43" अंक रखा जाएगा।

(41) प्ररूप व्या०चि० 42 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "56" अंक के स्थान पर "44" अंक रखा जाएगा।

(42) प्ररूप व्या०चि० 43 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "57" अंक के स्थान पर "45" रखा जाएगा।

(43) प्ररूप व्या०चि० 44 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "11" अंक के स्थान पर "8" अंक रखा जाएगा।

(44) प्ररूप व्या०चि० 46 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "60, 61, 62" अंकों के स्थान पर "48, 49, 50" अंक रखे जाएंगे।

(45) प्ररूप व्या०चि० 47 से सबन्धित चौथे मामले में "63" अंक के स्थान पर "51" अंक रखा जाएगा।

(46) प्ररूप व्या०चि० 50 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "19, 50" के स्थान पर "37, 38" अंक रखे जाएंगे।

(47) प्ररूप व्या०चि० 51, 52, 53 का लोप किया जाएगा।

(48) प्ररूप व्या०चि० 54 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "58" अंक के स्थान पर "46" अंक रखा जाएगा।

(49) प्ररूप व्या०चि० 55 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "59" अंक के स्थान पर "47" अंक रखा जाएगा।

(50) प्ररूप व्या०चि० 56 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "65" अंक के स्थान पर "53" अंक रखा जाएगा।

(51) प्ररूप व्या०चि० 57 से सबन्धित "66" अंक के स्थान पर "51" अंक रखा जाएगा।

(52) प्ररूप व्या०चि० 58 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "68" अंक के स्थान पर "56" अंक रखा जाएगा।

(53) प्ररूप व्या०चि० 59 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में ("72" अंक के स्थान पर "59" रखा जाएगा।

(54) प्ररूप व्या०चि० 1 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "75" अंक के स्थान पर "61" अंक रखा जाएगा।

(55) प्ररूप व्या०चि० 2 से संबन्धित चौथे स्तम्भ में "78" अंक के स्थान पर "64" अंक रखा जाएगा।

(56) प्ररूप व्या०चि० 3 से सबन्धित चौथे स्तम्भ में "79" अंक के स्थान पर "69" अंक रखा जाएगा।

(ख) प्ररूपों में—

(1) प्ररूप व्या०चि० 1 में (क) "फीस 40 रुपये प्रथम अनुसूची की प्रविष्टियां सं० 1 और 2 देखिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर फीस 200 रु० प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 1, 2 और 3 देखिए" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) पाद टिप्पण 2 में "ऐसे चिन्हों की दशा में जिन में सूती वस्त्र माल से सम्बन्धित अक्षर या संख्याएं या उनका कोई समुच्चय है पांचवी अनसूची की मद सं० का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि माल उक्त अनसूची की किसी मद के अन्तर्गत आता है नियम 14 देखिए", अंत में जोड़ा जाएगा।

(2) प्ररूप व्या०चि० 2 का लोप किया जाएगा।

(3) प्ररूप व्या०चि० 3 में "40" रुपये" पद के स्थान पर "500 रुपये" रखा जाएगा।

(4) प्ररूप व्या० चि० 4 में फीस: प्रथम अनसूची की प्रविष्टि सं० 4 और 5 देखिए, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर फीस "250.00 रु० अक्षर और अंक" रखे जाएंगे।

(5) प्ररूप व्या०चि० 5 में "50 रु०" पद के स्थान पर "250 रु०" पद रखा जाएगा।

(6) प्ररूप व्या०चि० 8 में "80 रुपये" पद के स्थान पर "250 रुपये" पद रखा जाएगा।

(7) प्ररूप व्या०चि० 9 में "40 रुपये "पद के स्थान पर "50 रुपये" पद रखा जाएगा।

(8) प्ररूप व्या०चि० 11 का लोप किया जायेगा।

(9) प्ररूप व्या०चि० 12 में "प्रथम अनसूची की प्रविष्टि सं० 27 से 29 देखे" शब्दों और अक्षरों और अंकों के स्थान पर फीस: प्रथम अनसूची का प्रथम सं० 15 से 17 देखें, शब्द, अक्षर और अंक रखा जाएगा।

(10) प्ररूप व्या०चि० 13 में "फीस: "30 रू०" तथा प्रथम अनसूची का प्रविष्टि सं० 27 से 29 में से किसी में विहित नवीनीकरण फीस सहित" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस 100 रु० तथा प्रथम अनसूची की प्रविष्टि सं. 15 से 17 में से किसी में विहित नवीनीकरण फीस सहित" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

(11) प्ररूप व्या०चि० 15 में "20 रु० पद" के स्थान पर "50 रु० पद" रखा जाएगा।

(12) प्ररूप व्या० चि० 16 में "10 रु०" पद के स्थान पर "20 रु०" पद रखा जाएगा।

(13) प्ररूप व्या०चि० 17 में "60 रु०" पद के स्थान पर "10 रु०" "100 रु०" और "20 रु०" पद क्रमशः रखा जाएगा।

(14) प्ररूप व्या० चि० 19 में "40 रु०" और "10 रु०" पद के स्थान पर "100 रू०" और "20 रु०" पद क्रमशः रखे जाएंगे।

(15) प्ररूप व्या०चि० 20 में "30 रु०" और "10 रु०" पदों के स्थान पर "60 रु०" और "20 रु०" पद क्रमश. रखे जाएंगे।

(16) प्ररूप व्या०चि० 21 में "20, 40 या 60 रु०" पदों के स्थान पर 50 रु०, 100 रुपये या "150 रु०" पद रखे जाएंगे।

(17) प्ररूप व्या०चि० 22 में "40 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०' पद रखा जाएगा।

(18) प्ररूप व्या०चि० 23 और व्या०चि० 24 में "फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 36 और 37 देखिए,, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस: प्रथम अनसूची की प्रविष्टि सं० 24 और 25 देखिए" शब्द, अक्षर, और अंक रखे जाएंगे।

(19) प्ररूप व्या०चि० 25 में "20, 40 और 60 रु०" पद के स्थान पर "40, 60 और 90 रु०" पद क्रमश. रखे जाएंगे।

(20) प्ररूप व्या०चि० 26 में "60 रु०" पद के स्थान पर "250 रु०" पद रखा जाएगा

(21) प्ररूप व्या० चि० 28 में "30 रु०" पद के स्थान पर "100 रुपए' पद रखा जाएगा।

(22) प्ररूप व्या० चि० 28 में "फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 31 और 42 देखिए" शब्दों, अक्षरो और अंको के स्थान पर फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 29 और 30 देखिए, शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे।

(23) प्ररूप व्या० चि० 29 में "फीस: प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि मे 13 देखिए" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर "फीस प्रविष्टि सं० 31 देखिए" शब्द अक्षर और अंक रखा जाएगा।

(24) प्ररूप व्या० चि० 30 में "फीस प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 33 देखिए "शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 32 देखिए,, शब्द, अक्षर और अंक रखा जाएगा।

(25) प्ररू० व्या० चि० 31 में "फीस. प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 45 देखिए" शब्द अक्षरो और अंकों के स्थान पर "फीस प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 33 देखिए, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(26) प्ररूप व्या० चि० 32 में "30 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०" पद रखा जाएगा।

(27) प्ररूप व्या० चि० 33 मे प्रविष्टि सं० "47", पद के स्थान पर "प्रविष्टि सं० 35" पद रखा जाएगा।

(28) प्ररूप व्या० चि० 34 में (i) "फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 48 और नीचे दिए गए गए पद टिप्पण को देखिए" शब्द" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 36 और नीचे दिए गए पद टिप्पण को देखिए" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे। (ii) पाद टिप्पण में "20 रु०" और "10 रु०" पद के स्थान पर "50 रु० और 20 रु० "पद रखा जाएगा।

(29) प्ररूप व्या० चि० 35, 36 और 37 में "10 रु०" पद के स्थान पर "20 रु० "पद रखा जाएगा।

(30) प्ररूप व्या० चि० 38 में, :—

(1) "फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 52 और नीचे दिए गए टिप्पण देखिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस: प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 40 और नीचे दिए गए पद टिप्पण देखिए", शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे।

(2) पद टिप्पण में :—

(क) "100 रु०" पद के स्थान पर जिन दोनों स्थानों पर यह आता है, "200 रु०" पद रखा जाएगा।

(ख) "50 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०" पद रखा जाएगा।

(31) प्ररूप व्या० चि० 39 में "50 रु०" के स्थान पर "150 रु०" पद रखा जाएगा।

(32) प्ररूप व्या० चि० 40 में "20 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०" पद रखा जाएगा।

(33) प्ररूप व्या० चि० 41 में "फीस. प्रथम अनुसूची प्रविष्टि सं० 55 देखिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस. प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 43 देखिए" शब्द, अक्षर और अंक रखा जाएगा।

(34) प्ररूप व्या० चि० 42 में : "फीस : प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 56 देखिए" शब्द, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस : प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 41 देखिए" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(35) प्ररूप व्या० चि० 43 में "60 रुपये" पद के स्थान पर "100 रुपये" पद रखा जाएगा।

(36) प्ररूप व्या० चि० 46 में "फीस : प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 60, 61 और 62 देखिए" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "फीस : प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 43, 44 और 45 देखिए" शब्दों, अक्षरों और अंक रखे जाएंगे।

(37) प्ररूप व्या० चि० 47 में "10 रु०" पद के स्थान पर "20 रु०" पद रखा जाएगा।

(38) प्ररूप व्या० चि० 50 में "प्रविष्टि सं० 49 और 50 देखिए" पद के स्थान पर "प्रविष्टि सं० 37 और 38 देखिए" पद रखा जाएगा।

(39) प्ररूप व्या० चि० 51, 52 और 53 का लोप किया जाएगा।

(40) प्ररूप व्या० चि० 54 में "10 रु०" पद के स्थान पर "50 रु०" पद रखा जाएगा।

(41) प्ररूप व्या० चि० 55 में "10 रु०" पद के स्थान पर "50 रु०" पद रखा जाएगा।

(42) प्ररूप व्या० चि० 56 में "10 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०" प्रतिमास पद रखा जाएगा।

(43) प्ररूप व्या० चि० 57 में "30 रु०" पद के स्थान पर "100 रु०" पद रखा जाएगा।

(44) प्ररूप व्या० चि० 58 में "10 रु०" पद के स्थान पर "20 रु०" पद रखा जाएगा।

(45) प्ररूप व्या० चि० 59 में "10 रु०" पद के स्थान पर "50 रुपये" पद रखा जाएगा।

(46) प्ररूप व्या० चि० 1 में "20 रु०" पद के स्थान पर "50 रुपए" पद रखा जाएगा।

(47) प्ररूप व्या० चि० 2 में "फीस : 20 रु० और प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि सं० 77 में विनिर्देश जारी रखने की फीस" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "फीस : 100 रु० और प्रथम, अनुसूची की प्रविष्टि सं० 53 में जारी रखने की फीस : शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे, और

(48) प्ररूप व्या० चि० 3 में "10 रुपए" पद के स्थान पर "20 रुपए" पद रखा जाएगा।

13. उक्त नियमों में, छठी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी : 1

"छठी अनुसूची"

रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

(नियम 114)

| प्रविष्टि संख्या | वह मामला जिसके संबंध में खर्च दिया जाना है | राशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | एक दिन की ऐसी सुनवाई के लिए जिसमें साक्षियों की परीक्षा की जानी हो। | 100.00 रु० |
| 2 | जहां साक्षियों की कोई परीक्षा नहीं की जानी हो, वहां एक दिन की सुनवाई के लिए। | 50.00 रु० |
| 3 | किसी पक्षकार के पिटाशन पर सुनवाई का स्थगन मंजूर करने के लिए | 20.00 रु० और अन्य पक्षकारों के जिन साक्षियों को उस दिन परीक्षा की जाना है, उन्हें पुनः समन करने के लिए खर्च। |
| 4 | शपथपत्र से कलंकास्पद मामले को हटाने के लिए | 10.00 रु० |
| 5 | साक्षियों की हाजरी के लिए निर्वाह भत्ता | 50.00 रु० (निम्न टिप्पण देखिए) |

यात्रा भत्ता : प्रत्येक मार्ग का प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का रेल या स्टीमर का किराया और यदि कोई रेल या स्टीमर वहां न चलता हो तो साक्षियों के रैंक और प्रास्थिति के अनुसार 0.50 नए पैसे या 0.25 नए पैसे प्रति किलोमीटर

टिप्पण : साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता और यात्रा भत्ते की दर उपरोक्त अधिकतम विहित के अधीन रहते हुए साक्षियों की प्रास्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी।

[मिसिल संख्या 26/4/आई० टी० /टी० एम०/ 82]

डी० के० सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 7th October, 1983

S.O. 3945.—The following draft of certain further amendments to the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 133 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), is published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration on o. after the 20th December, 1983.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft before the date specified will be considered by the Central Government.

DRAFT AMENDMENTS

1. These rules may be called the Trade and Merchandise Marks (Amendments) Rules, 1983.

2. In the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 (hereinafter referred to as the said rules) for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), all applications, notices, statements or other documents or any fees authorised or required by the Act or these rules to be made, served, left or sent or paid at or to the Trade Marks Registry in relation to a trade mark on the Register of Trade Marks on the notified date or for which an application for registration is pending on, or is made on or after the notified date, shall be made, served, left or sent or paid to the appropriate office of the Trade Marks Registry.

(2) Documents or fees authorised or required by the Act or these rules to be sent or paid may be sent or paid at or to either the appropriate office or the head office of the Registry in the following matters :

(a) Communication in relation to an application filed for registration of a trade mark;

(b) Excess space fee for advertisement in the Trade Marks Journal; and

(c) Applications or request on Forms TM-12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; 32; 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 50; 54; 55; 58 and 59.

3. In rule 9 of the said rules, for the words "Where any application", the words "Subject to the provisions of rule 8, where any application" shall be substituted.

4. In rule 25 of the said rules, in sub-rule (2) the words "if in respect of non-textile goods" shall be omitted.

5. In rule 47 of the said rules—

(a) after the words "the applicant shall pay", the words "for excess space, if any", shall be inserted;

(b) the proviso shall be omitted.

6. In rule 62 of the said rules, in sub-rule (1), the words, letters and figures "and upon payment of the prescribed fee on Form TM-11" shall be omitted.

7. In rule 104 of the said rules, after the words "prescribed fee", the words "for excess space, if any", shall be inserted.

8. Rules 138 and 139 of the said rules shall be committed.

9. In rule 140 of the said rules—

(a) in sub-rule (1), for the letters and figures "TM-53", the letters and figure "TM-1" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the word, letters and figure "Form TM-53", the word "or" shall be substituted.

10. Rules 141, 142 and 143 of the said rules shall be omitted.

11. In the said rules for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :

"THE FIRST SCHEDULE

(See Rule 11)

| No. of entry | On what payable | Fees Amount Rs. p. | Fees Corresponding form number |
|---|---|---|---|
| | (2) | (3) | (4) |
| 1. | On application not otherwise charged to register a trade mark for a specification of goods included in in one class (Sec. 18) | 200.00 | TM-1 |
| 2. | On application to register a textile mark, other than a certification trade mark, consisting exclusively of numerals or letters of any combination thereof for a specification of goods included in one item of the Fifth Schedule under Rule 140 | 200.00 | TM-1 |
| 3. | On application to register a series of trade marks under section 15 for a specification of goods included in one class | 200.00 | TM-1 |
| 4. | On application to register a defensive trade mark under section 47 for a specification of goods included in one class | 500 00 | TM-3 |
| 5. | On application under Section 62 to register a certification trade mark for a specification of goods included in one class | 250 00 | TM-4 |
| 6. | On a request under Rule 41(1) to to state grounds of decision | 50.00 | TM-51 |
| 7. | On a notice of opposition under Section 21(1) for each application opposed | 250.00 | TM-5 |
| 8. | On application for extension of time for filing notice of opposition under Section 21(1) | 20.00 | TM-44 |
| 9. | On a counter-statement in answer to to a notice of opposition under Section 21, for each application opposed, or in answerto an application under any of the Sections 46, 47(4) and 56 in respect of each trade mark, or in answer to a notice of opposition under Section 58 or Rule 105 for each application or conversion opposed | 30.00 | TM-6 |
| 10. | On notice of intention to attend hearing under any of the Sections 21, 46, 47(4), 56 and 58 or under Rule 105 by each party to the proceeding concerned | 30.00 | TM-7 |
| 11. | On notice of opposition before the Central Government under Section 64(3) for each application opposed | 250.00 | TM-8 |
| 12. | On a counter-statement in answer to a notice of opposition before the Central Government under Sec. 64(3) for each application opposed | 50.00 | TM-9 |
| 13. | On notice of intention to attend hearing of each opposition before the Central Government under Sec. 64(3) by applicant and by the opponent respectively | 30.00 | TM-10 |
| 14. | On application under Section 16(4) to dissolve the association between registered trade marks | 20.00 | TM-14 |
| 15. | For renewal under Section 25 of the registration of a trade-mark at the expiration of the last registration not otherwise charged | 200.00 | TM-12 |
| 16. | For renewal under Section 25 of the registration of a series of trade marks at the expiration of the last registration— | | |
| | For the first two marks of the series | 200.00 | TM-12 |
| | For every additional mark of the series | 50.00 | |
| 17. | For renewal under Section 25 of the registration of the same certification trade mark with the same date for goods in more than one class —in respect of every class | 200.00 | TM-12 |
| 18. | On application under Section 25(4) for restoration of a trade mark removed from the Register | 100.00 (plus renewal fee as prescribed in any of the entries Nos. 15, 16 &17) | TM-13 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 9 | On application for certificate of the Registrar under Section 39(2) For the first mark prosposed to be be assigned | 100.00 | TM-17 |
| | For every additional mark of the the same proprietor included in that assignment, | 20.00 | |
| 20. | On application for approval of the Registrar under Section 40— | | |
| | For the first mark | 100.00 | TM-19 |
| | For every additional mark of the same proprietor included in the same transfer..... | 20.00 | |
| 21. | On application under Section 41 for directions of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of trade marks in use— | | |
| | For the first mark assigned .. | 60 00 | TM-20 |
| | For every additional mark assigned with the same devolution of title. | 20.00 | |
| 22. | On application for extension of time for applying for directions under Section 41 for advertisement of assignment without goodwill of trade mark in use in respect of devolution of title— | | |
| | not exceeding one month . . | 50.00 | TM-21 |
| | not exceeding two months . . | 100.00 | |
| | not exceeding three months . . | 150.00 | |
| 23. | On application under Sec. 42 for consent of the Central Government to the assignment or transmission of a certification trade mark. | 100.00 | TM-22 |
| 24. | On application under Section 44 to register a subsequent proprietor in a case of assignment for transmission of a single trade mark— | | |
| | if made within six months from the date of acquisition of proprietorship | 100.00 | TM-23or TM-24 |
| | if made after expiration of six months but before 12 months from the da te of acquisition of proprietorship | 150.00 | TM-23 or TM-24 |
| | if made after 12 months from the date of acquisition of proprietorship. | 250.00 | TM-23 or TM-24 |
| 25. | On application under Section 44 to register a subsequent proprietor of more than one trademark registered in the same name, the devolution of title being the same in each case— if made within six months from the date of acquisition of proprietorship— | | |
| | For the first mark . . . . | 100.00 | TM-23 or TM-24 |
| | For every additional mark . | 20.00 | |
| | If made after expiration of six months but before 12 months from the date of acquisition of proprietorship— | | |
| | For the first mark . . | 150.00 | TM-23 or TM-24 |
| | For every additional mark . . | 30.00 | |
| | If made after expiration of 12 months from the date of acquisition of proprietorship— | | |
| | For the first mark . . | 250.00 | TM-23 or TM-24 |
| | For every additional mark . . | 50.00 | |
| 26. | On application under Section 45(3) for extension of time for registering a company as subsequent proprietor of trade marks on one assignment— | | |
| | not exceeding two months . . | 40 00 | TM-25 |
| | not exceeding four months . . | 60 00 | |
| | not exceeding six months . . | 90.00 | |
| 27. | On application under any of the Sections 46, 47(4) and 56 for rectification of the register or removal of trade mark from the register. | 250 00 | TM-26 |
| 28. | On application under Rule 96 for leave to intervene in proceedings under any of the Sections 46, 47(4) and 56 for rectification of the register or removal of trade mark from the register. | 100.00 | TM-27 |
| 29. | On application under Section 49 to register a registered user of a registered trade mark in respect of goods within the specification thereof. | 750.00 | TM-28 |
| 30. | On application under Section 49 to register the same registered user of more than one registered trade mark of the same registered proprietor, where all the trade marks are covered by the same registered user agreement in respect of goods within the respective specification thereof and subject to the same conditions and restrictions in each case— | | |
| | For the first mark . . . | 750.00 | TM-28 |
| | For every additional mark of the proprietor included in the application, and in the registered under agreement. | 500.00 | |
| 31. | On application under clause (a) of Section 52(1) to vary the entry of a registered user of one trade mark where the trade marks are covered by the same registered user agreement and the same registered user is registered in respect of each of them— | 500.00 | TM-29 |
| | For the first mark . . . | 500 00 | |
| | For every additional mark included in the application . . . | 250 00 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 32. | On application under clause (b) of Section 52(1) for cancellation of the entry of a registered user of one trade mark<br>where the application includes more than one trade mark—<br>For the first mark<br>For every additional mark included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-30 |
| 33. | On application under clause (c) or (d) of Section 52(1) to cancel the entry of a registered user of one trade mark<br>where the application includes more than one trade mark—<br>For the first mark<br>For every additional mark included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-31 |
| 34. | On notice under Rule 92(2) of intention to intervene in one proceeding for the variation or cancellation of entries of a registered user of a trade mark. | 100.00 | TM-32 |
| 35. | On application under Section 57 to change the name or description of a registered proprietor or a registered user of a trade mark where there has been no change in the proprietorship or in the identity of the registered user (except where the application is made as a result of an order of a public authority or in consequence of a statutory requirement)<br>—where the application includes more than one trade mark—<br>For the first mark<br>For every additional mark included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-33 |
| 36. | On application under Section 57 to alter an entry of the address of a registered proprietor or a registered user of a trade mark unless exempted from fee under rule 98(3)<br>where the application includes more than one trade mark—and where the address in each case is the same and is altered in the same way—<br>For the first entry<br>For every other entry included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-34 |
| 37. | On application to make an entry of an address for service in India of a registered proprietor for a registered user of a trade mark<br>where the application includes more than one trade mark and the address for service to be entered is the same in each case—<br>For the first entry<br>For every other entry included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-50 |
| 38. | On application to alter or substitute an entry of an address for service in India in the register (less exempted from fee under rule 98(3)<br>—where the application includes more than one trade mark and the address in each case is the same and is altered or substituted in the same way —<br>For the first entry<br>For every other entry included in the application | 50.00<br>50.00<br>20.00 | TM-50 |
| 39. | On application under clause (c), (d) or (e) of Section 57(1) for cancelling the entry or part of the entry of a trade mark or for entry of disclaimer or memorandum upon the register. | 20.00 | TM-35 or TM-36 or TM-37 |
| 40. | On application under Section 58 for leave to add to or alter a registered trade mark (except where the application is made as a result of an order of a public authority or in consequence of a statutory requirement)<br>—where the application includes more than one trade mark and the addition or alteration to be made in each case being the same—<br>For the first mark<br>For every other mark included in the application | 200.00<br>200.00<br>100.00 | TM-38 |
| 41. | On notice of opposition under Section 58(2) to an application for leave to add to or alter a registered trade mark for each application opposed. | 150.00 | TM-39 |
| 42. | On application under Section 59 for conversion of specification. | 100.00 | TM-40 |
| 43. | On notice of opposition under Section 59(2) to a conversion of the specification or specifications of a registered trade mark<br>—where the marks are entered in the register as associated trade marks and have the same specification—<br>For the fitst mark<br>For every additional mark included in the notice of opposition | 150.00<br>150.00<br>20.00 | TM-41 |
| 44. | On application under Section 65 for alteration of the deposited regulations of a certification trade mark<br>—where the marks are entered in the register as associated trade marks—<br>For the regulations of one registration<br>For the same or substantially same regulations of each additional registration proposed to be altered in the same way and included in the same application. | 100.00<br>100.00<br>20.00 | TM-42 |
| 45. | On application to the Central Government under Section 69 to expunge or vary the registration of certification trade mark to vary | 100.00 | TM-43 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| | the deposited regulations of a certification trade mark or certification trade marks of the same registered proprietor where the regulations are substantially the same. | | |
| 46. | For a search under Rule 24(1) in respect of one class | 50 00 | TM-54 |
| 47. | On request for the Registrar's preliminary advice under Section 103 for a trade mark in respect of one class. | 50.00 | TM-55 |
| 48. | On request for certificate of the Registrar under Section 115 [other than certificate under Section 23(2)] | 20.00 | TM-46 |
| 49. | On request for certificate of registrar [other than certificate under Section 23(2) of the Registration of a series of the trade marks under Section 15] | 40.00 | TM-46 |
| 50. | On request for a certified copy of any entry in the register or of any document under Section 125(2). | 20.00 (plus typing charges as prescribed in entry No. 58 | TM-46 |
| 51. | On request to enter in the register and advertise a note of certificate of validity, under rule 123 in respect of one mark. | 20.00 | TM-47 |
| 52. | On request, not otherwise charged for correction of clerical error or for amendment, except where the request is made as a result of an order of a public authority or in consequent of a statutory requirement. | 20.00 | TM-16 |
| 53. | On application for extension of time under Section 101 [not being a time expressly provided in the Act or prescribed by rule 81 or by rule 82(4)]. | 20.00 | TM-56 |
| 54. | On application for review of Registrar's decision under Section 97(c). | 100.00 | TM-57 |
| 55. | On petitions (not otherwise charged) for obtaining Registrar's orders on any interlocutory matter in a contested proceeding. | 50.00 | |
| 56. | On request to Registrar for particulars of advertisement of a mark under rule 50. | 20.00 | TM-58 |
| 57. | For inspecting the documents mentioned in Section 125(1) for every hour or part thereof. | 20.00 | |
| 58. | For copying documents, for every page or part thereof in excess of of one page<br>For TM-46<br>For photocopy or typed copy of documents. | 1.00 per page<br>(subject to a minimum of Rs. 5.00) | |
| 59. | On a request for a duplicate or further copy of certificate. | 50.00 | TM-59 |
| 60. | For extra space in the journal for advertisement or re-advertisement in cases where the printing block for the trade mark exceeds 5 centimetres in breadth or depth or in breadth and depth<br>For upto 10 centimetres or part thereof over 5 centimetres in breadth<br>For upto 10 centimetres or part thereof over 5 centimetres in depth | <br>50.00<br>50 00 | |
| 61. | On application for registration as a trade marks agent under rule 151 | 50 00 | TMA-1 |
| 62. | For registration of a person as a trade marks Agent under rule 153. | 100.00 | |
| 63. | For continuance of the name of a person in the Register of Trade Marks Agents under Rule 154—<br>For every year (excluding the first year) to be paid on the 1st April, in each year<br>For the first year to be paid along with the fee for registration, in the case of a person registered at any time between the 1st April, and 30th September<br>N.B. : A year for this purpose will commence on the 1st day of April and end on the 31st day of March following. | <br>100.00<br>100.00 | |
| 64. | On application for restoration of the name of a person to the Register of Trade Marks Agents under rule 156 | 100.00 Plus continuance fee under entry No. 63 | TMA-2 |
| 65. | On application for an alteration of any entry in the Register of Trade Marks Agents under rule 157 | 20 00 | TMA-3 |

12 In the Second Schedule to the said rules :

(a) In the list of forms—

(1) in the fourth column relating to Form TM-1 for the figures "1 and 2" the figures and word "1 to 3" shall be substituted.

(2) Form TM-2 shall be omitted.

(3) in the fourth column relating to Form TM-3, for the figure "3", the figure "4" shall be substituted.

(4) in the fourth column relating to Form TM-4 for the figures "4 and 5" the figure "5" shall be substituted.

(5) in the fourth column relating to Form TM-5 for the figure "10" the figure "7" shall be substituted.

(6) in the fourth column relating to Form TM-6 for the figure "12" the figure "9" shall be substituted.

(7) in the fourth column relating to Form TM-7 for the figure "13" the figure "10" shall be substituted.

(8) in the fourth column relating to Form TM-8 for the figure "14" the figure "11" shall be substituted.

(9) in the fourth column relating to Form TM-9 for the figure "15" the figure "12" shall be substituted.

(10) in the fourth column relating to Form TM-10 for the figure "16" the figure "13" shall be substituted.

(11) Columns 1 to 4 of entries relating to Form TM-11 shall be omitted.

(12) in the fourth column relating to Form TM-12 for the figures and word "27 to 29" the figures and word "15 to 17" shall be substituted.

(13) in the fourth column relating to Form TM-13 for the figure "30" the figure "18" shall be substituted.

(14) in the fourth column relating to Form TM-14 for the figure "26", the figure "14" shall be substituted.

(15) in the fourth column relating to Form TM-15 for the figure "9", the figure "6" shall be substituted.

(16) in the fourth column relating to Form TM-16 for the figure "64" the figure "52" shall be substituted.

(17) in the fourth column relating to Form TM-17 for the figure "31" the figure "19" shall be substituted.

(18) in the fourth column relating to Form TM-19 for the figure "32" the figure "20" shall be substituted.

(19) in the fourth column relating to Form TM-20 for the figure "33" the figure "21" shall be substituted.

(20) in the fourth column relating to Form TM-21 for the figure "34" the figure "22" shall be substituted.

(21) in the fourth column relating to Form TM-22 for the figure "35" the figure "23" shall be substituted.

(22) In the fourth column relating to Form TM-23 for the figures "36, 37" the figures "24, 25" shall be substituted.

(23) in the fourth column relating to Form TM-24 for the figures "36, 37" the figures "24, 25" shall be substituted.

(24) in the fourth column relating to Form TM-25 for the figure "38" the figure "26" shall be substituted.

(25) in the fourth column relating to Form TM-26 for the figure "39" the figure "27" shall be substituted.

(26) in the fourth column relating to Form TM-27 for the figure "40" the figure "28" shall be substituted.

(27) in the fourth column relating to Form TM-28 for the figures "41, 42", the figures "29, 30" shall be substituted.

(28) in the fourth column relating to Form TM-29 for the figure "43" the figure "31" shall be substituted

(29) in the fourth column relating to Form TM-30 for the figure "44" the figure "32" shall be substituted.

(30) in the fourth column relating to Form TM-31 for the figure "45" the figure "33" shall be substituted.

(31) in the fourth column relating to Form TM-32 for the figure "46" the figure "34" shall be substituted.

(32) in the fourth column relating to Form TM-33 for the figure "47" the figure "35" shall be substituted.

(33) in the fourth column relating to Form TM-34 for the figure "48" the figure "36" shall be substituted.

(34) in the fourth column relating to Form TM-35 for the figure "51" the figure "39" shall be substituted.

(35) in the fourth column relating to Form TM-36 for the figure "51" the figure "39" shall be substituted.

(36) in the fourth column relating to Form TM-37 for the figure "51" the figure "39" shall be substituted.

(37) in the fourth column relating to Form TM-38 for the figure "52" the figure "40" shall be substituted.

(38) in the fourth column relating to Form TM-39 for the figure "53" the figure "41" shall be substituted.

(39) in the fourth column relating to Form TM-40 for the figure "54" the figure "42" shall be substituted.

(40) in the fourth column relating to Form TM-41 for the figure "55" the figure "43" shall be substituted.

(41) in the fourth column relating to Form TM-42 for the figure "56" the figure "44" shall be substituted.

(42) in the fourth column relating to Form TM-43 for the figure "57" the figure "45" shall be substituted.

(43) in the fourth column relating to Form TM-44 for the fifure "11" the figure "8" shall be substituted.

(44) in the fourth column relating to Form TM-46 for the figures "60, 61, 62" the figures "48, 49, 50" shall be substituted.

(45) in the fourth column relating to Form TM-47 for the figure "63" the figure "51" shall be substituted.

(46) in the fourth column relating to Form TM-50 for the figure "49, 50" the "37, 38" shall be substituted

(47) Forms TM-51; 52; 53 shall be omitted.

(48) in the fourth column relating to Form TM-54 for the figure "58" the figure "46" shall be substituted.

(49) in the fourth column relating to Form TM-55 for the figure "59" the figure "47" shall be substituted.

(50) in the fourth column relating to Form TM-56 for the figure "65" the figure "53" shall be substituted.

(51) in the fourth column relating to Form TM-57 for the figure "66" the figure "54" shall be substituted.

(52) in the fourth column relating to Form TM-58 for the figure "68" the figure "56" shall be substituted.

(53) in the fourth column relating to Form TM-59 for the figure "72" the figure "59" shall be substituted

(54) in the fourth column relating to Form TM-1 for the figure "75" the figure "61" shall be substituted.

(55) in the fourth column relating to Form TMA-2 for the figure "78" the figure "64" shall be substituted.

(56) in the fourth column relating to Form TMA-3 for the figure "79" the figure "65" shall be substituted.

(b) in the Forms—

(1) In form TM-1 (a) for the words, letters and figures "Fee Rs. 40 see entries Nos. 1 and 2 of First Schedule", the words, letters and figure "Fee : 200/- see entries Nos. 1, 2 and 3 of First Schedule" shall be substituted.

(b) In foot note 2, the words and figures "In the case of marks consisting of letters or numbers or any combination thereof relating to textile goods, the item number of the Fifth Schedule should be stated if the goods fall in any of the items of the said Schedule. See Rule 14" shall be added at the end

(2) Form TM-2 shall be omitted.

(3) In Form TM-3 for the expression "Rs. 40" the expression "Rs.500.00" shall be substituted.

(4) In Form TM-4 for the words, letters and figures "Fee : See entries Nos. 4 and 5 of the First Schedule", the words, letters and figures "Fee :Rs.250.00" shall be substituted.

(5) In Form TM-5 for the expression "Rs.50" the expression "Rs.250" shall be substituted.

(6) In Form TM-8 for the expression "Rs. 80" the expression "Rs.250" shall be substituted.

(7) In Form TM-9 for the expression "Rs.40" the expression "Rs.50" shall be substituted.

(8) Form TM-11 shall be omitted.

(9) In Form TM-12 for the words, letters and figure "See entries Nos. 27 to 29 of the First Schedule" the words, letters and figures "Fee; See entries Nos. 15 to 17 of the First Schedule" shall be substituted.

(10) In Form TM-13, for the words, letters and figures "Fee :Rs. 30 plus renewal fee prescribed in any of the entries Nos. 27 to 29 of the First Schedule", the words, letters and figures "Fee :Rs.100 plus renewal fee prescribed in any of the entries Nos. 15 to 17 of the First Schedule" shall be substituted.

(11) In Form TM-15, for the expression "Rs.20", the expression "Rs. 50", shall be substituted.

(12) In Form TM-16 for the expression "Rs.10" the expression "Rs.20" shall be substituted.

(13) In Form TM-17, for the epression "Rs. 60" and "Rs. 10" the expression "Rs. 100 and "Rs. 20" shall respectively be substituted.

(14) In Form TM-19 for the expression "Rs. 40" and "Rs. 10", the expression "Rs. 100" and Rs. 20 shall be substituted respectively.

(15) In Form TM-20, for the expressions "Rs.30" and "Rs.10", the expressions "Rs.60" and 'Rs.20' shall respectively be substituted.

(16) In Form TM-21, for the expression "Rs. 20, 40 or 60" the expression "Rs.50, 100 or 150" shall be substituted.

(17) In Form TM-22, for the expression "Rs.40", the expression "Rs. 100" shall be substituted.

(18) In Forms TM-23 and TM-24, for the words, letters and figures, "Fee : See entries Nos. 36 and 37 of the First Schedule", the words, letters and figures "Fee : See entries Nos. 24 and 25 of the First Schedule", shall be substituted.

(19) In Form TM-25, for the expression "Rs.20, 40 and 60", the expression "Rs.40, 60 and 90" shall respectively be substituted.

(20) In Form TM-26, for the expression "Rs. 60", the expression "Rs. 250" shall be substituted.

(21) In Form TM-27, for the expression "Rs.30", the expression "Rs. 100" shall be substitute.

(22) In Form TM-28, for the words, letters and figures, "Fee : See entries Nos. 41 and 42 of the First Schedule" the words, letters and figures "Fee : See entries Nos. 29 and 30 of the First Schedule shall be substituted.

(23) In Form TM-29, for the words, letters and figures, "Fee : See entry No. 43 of the First Schedule", the words, letters and figures "Fee : See entry No. 31 of the First Schedulue shall be substituted.

(24) In Form TM-30, for the words, letters and figures "Fee : See entry No. 44 of the First Schedule", the words, letters and figures "Fee : See entry No. 32 of the First Schedule" shall be substituted.

(25) In Form TM-31, for the words, letters and figures "Fee : See entry No.45 of the First Schedule", the words, letters and figure "Fee :See entry No.33 of the First Schedule" shall be substituted.

(26) In Form TM-32 for the expression "Rs. 30" the expression "Rs.100" shall be substituted.

(27) In Form TM-33 for the expression "entry No.47", the expression "entry No.35" shall be substituted.

(28) In Form TM-34, (i) for the words, letters and figures "Fee : See entry No. 48 of the First Schedule and footnote below", the words, letters and figures "Fee : See entry No. 36 of the First Schedule and footnote below" shall be substituted. (ii) in the footnote, for the expression "Rs. 20" and "Rs.10" the expressions "Rs.50" and Rs.20 be substituted.

(29) In Forms TM-35, 36 and 37 for the expression "Rs.10", the expression "Rs.20" shall be substituted.

(30) In Form TM-38,

(i) for the words letters and figure, "Fee : See entry No. 52 of the First Schedule and the footnote below" the words, letters and figure "Fee : See entry No. 40 of the First Schedule and footnote below" shall be substituted.

(ii) in the footnote—

(a) for the expression "Rs.100" in both the places where they occur, the expression 'Rs.200" shall be substituted.

(b) for the expression "Rs. 50" the expression "Rs. 100" shall be substituted.

(31) In Form TM-39, for the expression "Rs.50", the expression 'Rs.150" shall be substituted.

(32) In Form TM-40, for the expression "Rs.20", the expression "Rs.100" shall be substituted.

(33) In Form TM-41, for the words, letters and figures "Fee : :See entry No.55 of the First Schedule", "Fee : See entry No. 55 of the First Schedule", 43 of the First Schedule" shall be substituted.

(34) In Form TM-42, for the words, letters and figures "Fee : See entry No 56 of the First Schedule" the words, letters and figures "Fee : See entry No. 44 of the First Schedule" shall be substituted.

(35) In Form TM-43, for the expression Rs. "60", the expression "Rs.100" shall be substituted.

(36) In Form TM-46, for the words, letters and figures "Fee : See entries No. 60, 61 and 62 of the First Schedule" the words, letters and figures "Fee : See entries Nos. 48, 49 and 50 of the First Schedule" shall be substituted.

(37) In Form TM-47, for the expression "Rs.10" the expression "Rs.20" shall be substituted.

(38) In Form TM-50, for the expression "See entries Nos. 49 and 50", the expression "See entries Nos. 37 and 38" shall be substituted.

(39) Forms TM-51, 52 and 53 shall be omitted.

(40) In Form TM-54 for the expression "Rs.10" the expression "Rs.50" shall be substituted.

(41) In Form TM-55, for the expression "Rs. 10" the expression "Rs50" shall be substituted.

(42) In Form TM-56, for the expression "Rs.10", the expression "Rs.20" per month shall be substituted.

(43) In Form TM-57, for the expression "Rs. 30", the expression "Rs.100" shall be substituted.

(44) In Form TM-58, for the expression "Rs 10" the expression "Rs. 20" shall be substituted.

(45) In Form TM-59, for the expression "Rs10" the expression "Rs.50" shall be substituted.

(46) In Form TM-A-1, for the expression "Rs.20" the expression "Rs. 50" shall be substituted.

(47) In Form TMA-2, for the words, letters and figures "Fee : Rs.20 plus continuance fee specifed in entry No. 77 of the First Schedule", the words, letters and figures 'Fee : Rs.100 plus continuance fee specified in entry No. 63 of the First Schedule" shall be substituted; and

(48) In Form TMA-3, for the expression "Rs. 10", the expression "Rs.20" shall be substituted.

13. In the said Rules, for the Sxth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SIXTH SCHEDULE"

Scale of costs allowable in Rule m114 proceedings before the Registrar

| Entry No. | Matter in respect of which costs to be awarded | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | For one days's hearing involving examination of witnesses | Rs. 100 |
| 2. | For one day's hearing when there is no examination of witnesses | Rs. 50 |
| 3. | For adjournment of hearing granted on the petition of any party | Rs. 20 plus cost for resummoning the other parties witnesses who were due to be examine on the day. |
| 4. | For striking out scandalous matter from an affidavit | Rs. 10 |
| 5. | For attendance of winesses— Subsistence allowance... | Rs. 50 (*Vide* note below) |
| 1 | | |
| | Travelling allowance. | The fare by rail or steamer for the first class or the second class each way and in there is no rail or steamer communication 0.50 np. or p.25 np. per kim. depending upon the rank and status of the witness. |

Note : The rates of subsistance allowance and travelling allowance for witnesses shall vary according to the status of the witnesses subject to the maximum prescribed above.

[File No. 26/4/IT/TM/82]

D.K. SINGH, Jt. Secy.

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 3946.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy, Department of Petroleum No. 12016/49/82-Prod. dated 4th December, 1983, published under S.O. No. 4005 in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) at page No. 4171 to 4173 under village Jambhul at serial No. 48 as shown in the Schedule, following S. No 242 should be read against S. No. 342 in English version appended to the above Notification.

SCHEDULE

| Read | For |
|---|---|
| S. No. 342 | S. No. 242 |

[No. O-12016/49/82-Prod.]

RAJENDRA SINGH, Director

## ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1983

का० आ० 3947.—कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 20 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री ए० आर० मंडल को श्री एम० एन० तिवारी के स्थान पर 7 जून, 1982 (पूर्वाह्न) अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने श्री एम० एन० तिवारी से कार्यभार लिया था, से 25 जुलाई, 1983 (पूर्वाह्न) अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने श्री एस० आर० भार्गव को कार्यभार सौंपा, तक के लिए भुगतान आयुक्त नियुक्त किया था।

एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 20 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री एस० आर० भार्गव को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 25 जुलाई, 1983 (पूर्वाह्न) से भुगतान आयुक्त नियुक्त किया है।

[सं० 11023(3)/82-सी०ए०]

टी०सी०ए० श्रीनिवासन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Coal)

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 3947.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government had appointed Shri A. R. Mandal, Commissioner of Payments in place of Shri M. N. Tiwary with effect from the 7th June, 1982 (Forenoon) on which date he took over charge of the office from Shri M. N. Tiwary to the 25th July, 1983, (Forenoon) on which date, he handed over charge of the office to Shri S. R. Bhargava.

It is also hereby notified that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, (36 of 1972), the Central Government has appointed Shri S. R. Bhargava as the Commissioner of Payments for the purpose of the said Act with effect from the 25th July, 1983 (Forenoon).

[No. 11023(3)/82-CA]
T. C. A. SRINIVASAN, Director

**पेट्रोलियम विभाग**

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1983

का० आ० 3948.—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० वालनेर-1 से मोटवान 1 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 14 जून 1983 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

वालनेर-1 से मोटवान-1 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | आ०का० संख्या | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा (पैट्रोलियम विभाग) | कलम | 3143 | 15-9-1979 | 14-6-83 |

[सं० 12016/5/79/प्रोड]

(Dept. of Petroleum)

New Delhi, the 5th October, 1983

S.O. 3947.—WHEREAS by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport petroleum from d.s. Walner-1 to Motwan-1 in Ankeleshawar oil field Gujarat State.

AND WHEREAS the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 14-6-83.

NOW THEREFORE under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user inland) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Walner-1 to Motwan-1

| Name of Ministry | Village | S.O. No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Energy (Deptt. of petroleum) | Kalam | 3143 | 15-9-79 | 14-6-83 |

[No. 12016/5/79-Prod.]

का०आ० 3949 यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० वालनेर-1 से मोटवान-1 तक पैट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 14 जून, 1983 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं :

**अनुसूची**

वालनेर-1 से मोटवान-1 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | का०आ०सं० | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा (पैट्रोलियम विभाग) | वालनेर | 3139 | 15-9-79 | 14-6-83 |

[सं० 12016/6/79/प्रोड]

S.O. 3949.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Walner-1 to Motwan-1 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And, whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 14-6-83.

Now, therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Rules, 1983, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. Walner-1 to Motwan-1.

| Name of Ministry | Villages | S.O.No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Energy (Deptt. of Petroleum) | Walner | 3139 | 15-9-79 | 14-6-83 |

[No. 12016/6/79-Prod.]

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1983

का०आ० 3950—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ सं० 2824 तारीख 23-6-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा से उत्वन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

| राज्य-गुजरात | जिला: सूरत | | तालुका-चोर्यासी | |
|---|---|---|---|---|
| गांव | सर्वे नं० | हेक्टेयर | एआरई | सेन्टीयर |
| भेसाण | 208/1 | 0 | 02 | 00 |
| | 209/1 | 0 | 38 | 22 |
| | 213/2 | 0 | 00 | 30 |
| | 213/3 | 0 | 05 | 88 |
| | 212 | 0 | 30 | 00 |
| | 211 | 0 | 18 | 80 |
| | 210/ए | 0 | 23 | 90 |
| | 210/बी | 0 | 00 | 25 |
| | 229/1/बी | 0 | 19 | 49 |
| | 229/1/ए | 0 | 16 | 80 |
| | 229/2 | 0 | 17 | 70 |
| | 230 | 0 | 30 | 15 |
| | 251 | 0 | 19 | 65 |
| | 247/1 | 0 | 29 | 40 |
| | 248/1 | 0 | 04 | 94 |
| | 248/2 | 0 | 22 | 51 |
| | 247/2 | 0 | 01 | 20 |
| | 246 | 0 | 43 | 42 |
| | 242/4 | 0 | 23 | 40 |
| | 17 | 0 | 09 | 85 |
| | 242/3 | 0 | 03 | 19 |
| | 18 | 0 | 01 | 50 |
| | 242/2 | 0 | 34 | 83 |
| | 19 | 0 | 24 | 45 |
| | 26 | 0 | 18 | 45 |
| | 25 | 0 | 45 | 00 |
| | 27/2 | 0 | 02 | 72 |
| | 27/3 | 0 | 47 | 28 |
| | 24/1 | 0 | 19 | 35 |
| | 28 | 0 | 25 | 10 |
| | 29 | 0 | 22 | 20 |

[सं० 12016/74/83-प्रो०]

राजेन्द्र सिंह, निदेशक

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 3950.—Whereas by a notificatiaon of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum), S.O. No. 2824 dated 23rd June, 1983 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its

intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of users in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Utran

State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyasi

| Village | Survey No. | Hectare | Are | Centiare |
|---|---|---|---|---|
| Bhesan | 208/1 | 0 | 02 | 00 |
| | 209/1 | 0 | 38 | 22 |
| | 213/2 | 0 | 00 | 30 |
| | 213/3 | 0 | 03 | 88 |
| | 212 | 0 | 30 | 00 |
| | 211 | 00 | 18 | 80 |
| | 210/A | 0 | 23 | 90 |
| | 210/B | 0 | 00 | 25 |
| | 229/1/B | 0 | 19 | 49 |
| | 229/1/A | 0 | 16 | 80 |
| | 229/2 | 0 | 17 | 70 |
| | 230 | 0 | 30 | 15 |
| | 251 | 0 | 19 | 65 |
| | 247/1 | 0 | 29 | 40 |
| | 248/1 | 0 | 04 | 94 |
| | 248/2 | 0 | 22 | 51 |
| | 247/2 | 0 | 01 | 20 |
| | 246 | 0 | 43 | 42 |
| | 242/4 | 0 | 23 | 40 |
| | 17 | 0 | 09 | 85 |
| | 242/3 | 0 | 03 | 19 |
| | 18 | 0 | 01 | 50 |
| | 242/2 | 0 | 34 | 83 |
| | 19 | 0 | 24 | 45 |
| | 26 | 0 | 18 | 45 |
| | 25 | 0 | 45 | 00 |
| | 27/2 | 0 | 02 | 72 |
| | 27/3 | 0 | 47 | 28 |
| | 24/1 | 0 | 19 | 35 |
| | 28 | 0 | 25 | 10 |
| | 29 | 0 | 22 | 20 |

[No. 12016/74/83-Prod.]

RAJENDRA SINGH, Director

## सिंचाई मंत्रालय

### (बाढ़ नियंत्रण अनुभाग)

नई दल्ली, 17 सितम्बर, 1983

का० आ० 3951.—केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (II), तारीख 12 फरवरी, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 461, तारीख 12 फरवरी, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग की निम्नलिखित प्रभागों के यथास्थिति, उप-निदेशकों या कार्यपालक इंजीनियरों को, समस्त देश में बाढ़ पूर्वसूचना केन्द्रों के लिए बेतार संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के संबंध में अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए या जल-वैज्ञानिक प्रेक्षणों के लिए, गेज बनाने के लिए या दोनों के लिए, कलक्टर को आदेश देने के लिए प्राधिकृत करती है :—

1. केन्द्रीय बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, हैदराबाद।
2. केन्द्रीय बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, अहमदाबाद।
3. पूर्वी गेज प्रभाग, भूवनेश्वर।
4. गोदावरी गेज प्रभाग, हैदराबाद।
5. कृष्णा गेज प्रभाग, हैदराबाद।
6. पुणे गेज प्रभाग, पुणे।
7. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० 1, पटना।
8. जल स्रोत बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० II, पटना।
9. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, नई दिल्ली।
10. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० 1, लखनऊ।
11. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० II, लखनऊ।
12. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, आगरा।
13. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० 1, गौहाटी।
14. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, जलपाईगुड़ी।
15. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, डिब्रूगढ़।
16. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० II, गौहाटी।
17. केन्द्रीय बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, आसनसोल।
18. बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, जोधपुर।
19. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० 1, वाराणसी।
20. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग, देहरादून।

21. जल स्रोत और बाढ़ पूर्वसूचना प्रभाग सं० II, वाराणसी।
22. जल स्रोत प्रभाग, बेहरमपुर।
23. जल स्रोत प्रभाग, जयपुर।

[सं० 44(19)/82-एफ०सी०]

सी० एस० हुकमानी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF IRRIGATION

(Flood Control Section)

New Delhi, the 17th September, 1983

S.O. 3951.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and in supersession of the notification No. S.O. 461 of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power dated the 12th February, 1972, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 12th February, 1972, except as respects things done or omitted to be done before supersession, the Central Government hereby authorises the Deputy Directors or Executive Engineers as the case may be, of the following Divisions of the Central Water Commission to direct the Collector to take order for the acquisition of land required in connection with the installation of wireless sets for Flood Forecasting Centres or for erecting sheds for Hydrological Observations or both, as the case may be, all over the country:—

1. Central Flood Forecasting Division, Hyderabad.
2. Central Flood Forecasting Division, Ahmedabad.
3. Eastern Gauging Division, Bhubneshwar.
4. Godavari Gauging Division, Hyderabad.
5. Krishna Gauging Division, Hyderabad.
6. Poona Gauging Division, Poona.
7. Water Resources and Flood Forecasting Division No. I, Patna.
8. Water Resources and Flood Forecasting Division No. II, Patna.
9. Water Resources and Flood Forecasting Division, New Delhi.
10. Water Resources and Flood Forecasting Division No. I, Lucknow.
11. Water Resources and Flood Forecasting Division No. II, Lucknow.
12. Water Resources and Flood Forecasting Division, No. Agra.
13. Water Resources and Flood Forecasting Division No. I, Gauhati.
14. Water Resources and Flood Forecasting Division, Jalpaiguri.
15. Water Resources and Flood Forecasting Division, Dibrugarh.
16. Water Resources and Flood Forecasting Division No. II, Gauhati.
17. Central Flood Forecasting Division, Asansol.
18. Flood Forecasting Division, Jodhpur.
19. Water Resources and Flood Forecasting Division No. I, Varanasi.
20. Water Resources and Flood Forecasting Division, Dehradun.
21. Water Resources and Flood Forecasting Division No. II, Varanasi.
22. Water Resources Division, Berhampur.
23. Water Resources Division, Jaipur.

[No. 44(19)/82-FC]

C. S. HUKMANI, Jt. Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1983

का० आ० 3952.—यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की बृहत योजना में यहां नीचे बताए गए क्षेत्रों के बारे में कतिपय संशोधन का प्रस्ताव है जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के अन्तर्गत 12 फरवरी, 1983 के नोटिस संख्या एफ०-10(7)/76-एम० पी० द्वारा उक्त नोटिस के 30 दिन के अन्तर्गत आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित किया गया था, जैसे कि उक्त अधिनियम की धारा 11-ए० की उपधारा (3) में अपेक्षित है ;

और यतः उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति या सुझाव हुए है ; अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जिन तिथि से यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा उस तिथि से दिल्ली की उक्त बृहत योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है ; नामतः—

संशोधन :"लगभग 1.73 हैक्ट (4,286 एकड़) का क्षेत्र जो क्षेत्र एफ० 11 (इंजीनियरिंग कालेज) में पड़ता है और जो "कुतुब होटल कामप्लेक्स" के नाम से प्रसिद्ध है तथा 30.48 मीटर (100 फुट) चौड़े मार्ग के दक्षिण में स्थित है, का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (सांस्थानिक) से बदल कर "व्यवसायिक (होटल)" में किया जाता है।

[संख्या के०-13011/9/77-डी० डी०-II (ए) (भाग)]

के० के० सक्सैना, डैस्क अधिकारी

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(DELHI DIVISION)

New Delhi, the 3rd October, 1983

S.O. 3952.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F. 10(7)/76-MP, dated the 12th February, 1983 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objection/suggestions as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice ;

And whereas, no objections/suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this modification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 1.73 hects. (4.286 acres) falling in Zone F-11 (Engineering College) known as 'Qutab Hotel Complex' and located in the south of 30.48 metres (100 ft. wide) road, is changed from (Public & Semi-Public Facilities) (Institutional) to 'Commercial (Hotel)".

[No. K-13011/9/77-DD-II-A(Pt.)]

K. K. SAXENA, Desk Officer

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 3953.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the Industrial Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-17 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to Sillewara Group of Collieries of Western Coalfields Limited, Post Office Sillewara Project, District Nagpur (Maharashtra State).

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. P. Sadasivan Nair, Advocate

For Maharashtra Pradesh Rashtriva Koyla Khadan Kamgar Sangh, Nagpur.—Mr. S. Tamizuddin, Representative.

INDUSTRY : Coal & Mines STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 30th August, 1983

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-18011(4)/80-D.IV(B) dated 1st September, 1981 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred to this Tribunal for adjudication an Industrial Disputes between the employers in relation to the management of Sillewara Group of Collieries of Western Coalfields Limited, Post Office Sillewara Project, District Nagpur (Maharashtra State) and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below:—

SCHEDULE

"(i) Whether Shri G. C. Bhakte was to be treated as Lower Division Clerk with effect from the 5th May, 1971? If so, to what consequential reliefs the workman is entitled and from what dates?

(ii) Whether the action of the management of Sub-Area Manager, Sillewara Group of Collieries of Western Coalfields Limited, Post Office Sillewara Project District Nagpur is justified in denying the enhanced rate of pay allowances to the Clerks and Supervisors who make payments and supervise the payments respectively, to the workers of Sillewara Group of Collieries? If not, to what benefit these payment Clerks and Supervisors are entitled?".

2. The schedule with the order of reference consists of two parts. The first part relates to the workman, G. C. Bhagte and the point referred to is whether he was to be treated as Lower Division Clerk (for short "LDC") with effect from 5th May, 1971 If so, to what consequential reliefs he is entitled to and from what date. The second part of the schedule is in respect of the point whether the management of Sub-Area Manager, Sillewara Group of Collieries (for short "S. G. Collieries") of Western Coalfields Limited, District Nagpur, is justified in denying the enhanced rate of pay allowances to the clerks who make the payments and supervisors who supervise the payments to the workmen of S. G. Collieries.

3. Bhakte was initially appointed as mining mazdoor on 10-2-1968. He was continued as M.T.K. (mining time keeper) up to 4-5-1971. With effect from 5-5-1971 he was temporarily promoted to the post of LDC in the Wage Board's scale of Rs. 205—325. These facts are not in dispute. It is the case of the management as pleaded in its written statement dated 22-12-1981 that Bhakte made a request to the management to permit him to work as MTK from 30-8-1972. According to the management there were more emoluments for the post of MTK than LDC and the nature of job was also convenient to Bhakte. The management accepted his request and permitted him to work as MTK. However, according to the management subsequently he made a request for being taken as LDC. This was also accepted. He worked as MTK only during the period he himself wanted. Promotional benefits in MTK were much quickest during that period when the mine was initially started and expanding quickly. The management further stated that during that period promotional avenue in clerical cadre were practically nil. Bhakte requested for change over to LDC when he found that promotional avenues in LDC category were reasonably good. The management stated that the change of designation and change of working was done at the request of the workman himself It was not forced on him. He was doing the work without any protest and without any objection. It is an admitted fact that from LDC promotion is as UDC. From MTK promotion is as HTK and CTK. The management stated that even though Bhakte was initially appointed as LDC on 5-5-1971 the period during which he worked as MTK should not be taken into account for the purpose of counting his seniority in the LDC cadre. According to the management an employee is entitled to get seniority in the cadre only for the period he works in that cadre continuously. The management, therefore, gave seniority to Bhakte as LDC only for the period he worked continuously as LDC. Bhakte was promoted as UDC with effect from March 1981. The management, therefore contended that the demand of the Maharashtra Pradesh Rashtriva Koyla Khadan Kamgar Sangh (hereinafter referred to as the "Sangh") for treating Bhakte as LDC with effect from 5-5-1971 continuously is totally unjustified and Bhakte is not entitled to any consequential relief based on any such claim.

4. The General Secretary of the Sangh filed the statement of claim dated 23-1-1982 pleading, inter alia, as follows. From 5-5-1971 after his promotion as LDC in clerical grade II Bhakte was mainly required to perform all the jobs of LDC and occasionally he was asked to perform the job of MTK at Walni Colliery which had just started as a new mine under the Sillewara Project. From 30-8-1972 the management arbitrarily re-designated him as MTK in the same scale and asked him to continue as MTK In the rejoinder filed by the Union dated 27-1-1982 to the written statement filed by the management the Sangh emphatically denied that Bhakte had requested the management to permit him to work as MTK from 30-8-1972. It was denied that there were more emoluments for the post of MTK than LDC and that the nature of job was also more convenient to Bhakte As per Wage Board Award for the Coal Mining Industry in India, both the designations have got the same clerical grade II and also other emoluments. According to the Sangh there were more and better prospects of promotion for LDC than MTK. The Sangh pleaded in its rejoinder that Bhakte opposed since beginning the move of the management to arbitrary change of his designation and made frequent representations. A copy of such representation dated 17-6-1974 was enclosed to this rejoinder. The Sangh pleaded that in fact Bhakte, after he was promoted as LDC, was performing all the jobs of LDC in MTK section. The work of MTK was being performed by other mining mazdoors of category I who were subsequently promoted as MTK. Bhakte continued to work as LDC and occasionally officiated as UDC with officiating allowance. As Bhakte actually performed the duties of LDC and as he made frequent representations against his re-designation as MTK the management vide their letter dated 12/14th February, 1976, superseded its own earlier arbitrary order dated 30-8-1972 and re-designated Bhakte as LDC with effect from 1-6-1972. This date of 1-6-1972 also was arbitrary. The Sangh further pleaded that in response to the representation of Bhakte the Personnel Manager of Nagpur area vide his letter dated 12/13th February, 1977 has also conceded that Bhakte will be treated as LDC with effect from 5-5-1971. The management sometime changed the designation of Bhakte as MTK "solely to save the management's scheme and to meet the statutory requirements only on paper". In substance the Sangh pleaded that for all pur-

poses Bhakte was LDC and was doing the work of LDC from 5-5-1971 and that, therefore, his seniority should be counted from 5-5-1971 and that his seniority should be fixed on that basis.

5. I shall first discuss the evidence adduced by the parties on this part of the schedule. The Sangh has filed documentary evidence on record. The management has not filed any documents. The Sangh has examined Bhakte. No oral evidence was adduced by the management on this part of the schedule. I shall first refer to the documents filed by the Sangh with the list dated 3-12-1982. All these documents are admitted by the management except the documents at Sr. Nos. 10 and 12. I have exhibited those documents also as they are referred to by Bhakte in his deposition and they are not specifically denied on behalf of the management even though reference is made to them in the pleadings of the Sangh. The order dated 5-5-1971 (exhibit W-1) states that Bhakte is temporarily promoted to the post of LDC in the scale of Rs. 205-325. This promotion was initially for a period of 12 months. This order states that Bhakte will continue to work in the MTK section as LDC. The next document is the office order of the management (exhibit W-2) dated 30-8-1972. That order is as follows :—

> "The following LDCs who are actually performing the duties of MTK in terms of Coal Mines Regulation are hereby re-designated as MTK in the scale of Rs. 205—5—325 with immediate effect.

This order is in respect of Bhakte and one more workman. Bhakte stated in his deposition that this change was brought about by the management without any reason. The change was not at his request. He protested against his designation as MTK orally and later on he protested in writing. He made a complaint in writing in December, 1972. He placed that complaint on record (exhibit W-10). In this letter addressed to the management Bhakte has stated that he was from the very beginning performing the duties of LDC; but suddenly the management changed his designation as MTK vide office order dated 30-8-1972 without taking his consent. He has further stated in this letter that it was not understood under what circumstances his designation was changed when he was performing the duties of LDC. He, therefore, requested that his designation be changed as LDC and he be treated as LDC from 5-5-1971. The deposition of Bhakte and this letter falsifies the stand of the management that Bhakte made a request sometime after he was appointed as LDC to permit him to work as MTK and that, therefore, the order dated 30-8-1972 was made. It is not the case of the management that his designation was changed for any other reason. It is an admitted fact that the pay scale of LDC and MTK was the same. The contention of the management that there were more emoluments for the post of MTK is not borne out by any material on record. It, therefore, appears that the stand of the management that Bhakte made a request to permit him to work as MTK is unacceptable. The management has not adduced any evidence, either documentary or oral, to show that Bhakte made such a request.

6. The next contention of the management is that Bhakte subsequently made a request for being taken back as LDC and that request also was accepted. Again there is no oral or documentary evidence to show that Bhakte made any request. The Sangh has filed on record the order of the management dated 12/14th February, 1976 (exhibit W-3). The text of the order is as follows :—

> "The following employees who are actually performing the duties of LDC though designated as M.T.K. are hereby re-designated as LDC with effect from the dates indicated against each individual. This will not involve any change of their pay scale and basic salary which are equivalent to that of M.T.K. and as such no financial benefits shall accrue out of this re-designation.
>
> 1. Sri G. C. Bhakte, M.T.K.—1-6-1972."

It is clear from this order that Bhakte and two other workmen mentioned in this order was actually performing the duties of LDC though designated as MTK. They were, therefore, re-designated as LDC. Bhakte was re-designated as LDC with effect from 1-6-1972. It is contended for the Sangh that this date also is arbitrary. He should have been re-designated as LDC from 5-5-1971. It is clear from the order dated 30-8-1972 (exhibit W 2) that till 30-8-1972 Bhakte was designated as LDC. By order at exhibit W-3 dated 12/14th Februray, 1976, Bhakte is sought to be re-designated as LDC from 1-6-1972. Both these orders read together show that Bhakte has to be treated as LDC from 5-5-1971. In his letter dated 17-6-1974 (exhibit W 9) Bhakte has complained that he was all along working as LDC since 5-5-1971. The change in his designation was effected by the management, according to Bhakte, to defer his claim for further promotion. The management has not stated when Bhakte made a request for being taken back as LDC. The management's order (exhibit W-3) does not show that that order was made on Bhakte's request. On the contrary that order was made in 1976 is given retrospective effect in the case of Bhakte from 1-6-1972.

7. There is one more letter produced on record by the Sangh and it is at exhibit W-4. It is issued by the Personnel Manager to Bhakte on 12/13th November, 1977. The text of the letter is as follows :—

> "We refer to your aforesaid application and have to inform you that though your seniority as LDC reckoned from the date you became LDC i.e. from 5-5-1971, we regret that in the event of change in cadre it is not possible to maintain your old seniority."

What is conveyed by this letter is that even though seniority of Bhakte was to be reckoned from 5-5-1971 there was change in his cadre sometime thereafter and that, therefore, it would not be possible "to maintain his old seniority". However, it appears from the oral evidence given by Bhakte and documentary evidence discussed above that the change in the cadre, for sometime, was only on paper. All along Bhakte continued to work as LDC. This is clear from the management's order, exhibit W-3, dated 12/14th February, 1976 that Bhakte was performing the duties of LDC though he was designated as MTK. There is no evidence adduced by the management to refute or counter the evidence adduced by the Sangh. I therefore find that Bhakte worked all along as LDC from 5-5-1971 and his seniority as LDC should be counted on that basis. Bhakte will therefore be entitled to his seniority reckoned from 5-5-1971 and he is entitled to have his promotion adjusted on that basis. He is promoted as UDC in March, 1981. The management will have to fix up his seniority on the basis that Bhakte continued to work as LDC from 5-5-1971. Bhakte will be entitled to difference in the pay and allowances for the period for which he was deprived of the promotion. The date of his promotion should be fixed by treating Bhakte as being in the cadre of LDC continuously from 5-5-1971. The other workmen who were wrongly promoted as UDC before Bhakte are not parties to this reference. Any order passed by me in this reference will not obviously affect them prejudicially Bhakte however will be entitled to the monetary benefits on the basis that he was a LDC continuously from 5-5-1971 ignoring the change of his designation as MTK. The date of his promotion and his pay and allowances as UDC will be fixed on the above basis and the difference in pay and allowance shall be paid to him.

8. It was contended by the management in the written statement that when the Sangh took up the claim with the Asstt Labour Commissioner there was no demand for treating him as LDC from 5-5-1971. The demand was only for promotion as UDC. Bhakte is promoted as UDC with effect from March, 1981, and that, therefore, no industrial dispute now survives. The management has not produced before me any documents or evidence showing what was the original demand of the Sangh. That contention, therefore, will have to be rejected.

9. The second part of the reference is whether the management of S. G. Collieries of Eastern Coalfields Limited are justified in denying the enhanced rate of pay and allowances to the Clerks who make the payments and Supervisors who supervise the payments respectively. These Collieries were in the Public Sector from the very beginning i.e. even before the nationalisation of the coal industry. Even before the nationalisation, the systemof making payment allowance to the Clerks

and Supervisors—other than cash and pay personnel engaged in disbursing payment, was introduced at S.G. Collieries which was formerly controlled by N.C.D.C. and now under W.C.L. from 16-2-1971. Under the circular dated 16-2-1971 (exhibit W-5) the payment allowance to the above staff was sanctioned at the following rates :—

"(i) For supervising payment in one counter for 300 workers—Rs. 5 per day.

(ii) For making payment in one counter for 300 workers—Rs. 4 per day."

The staff engaged in making payment or for supervising the payment was to be held responsible for any cash shortage or any wrong payment in course of disbursment.

10. In partial modification of the above circular, another circular dated 26-7-1972 (exhibit W-6) was issued. It was decided under this circular that the staff other than the cash and pay personnel engaged in disbursing unpaid wages and other payment to workers on days other than those fixed for payment of normal wages to the daily rated and piece rated workers was also to be paid allowance at the following rates :—

"(1) For supervising payments in one counter for not less than 200 workers—Rs. 5 per day.

(2) For making payment in one counter for not less than 200 workers—Rs. 4 per day."

11. According to the Sangh the above rates of Rs 5 and Rs 4 were fixed at that point of time in February 1971 and July 1972 when the market rates and other conditions and circumstances were for different from what they are today. The Sangh stated in the statement of claim that there is considerable increase in wages and other fringe benefits to the coal mines workmen after July 1972. The reason for paying payment allowance to the staff other than cash and pay personnel, according to the Sangh, was to compensate the extra strain and workload which is something abnormal to their routine work, and secondly to cover up the risk of short cash if any, for whatever reasons. It further stated that in 1971-72 when this allowance of Rs. 5 and Rs. 4 was given the staff deployed for making the payment to the workman were required to handle the amounts in thousands only whereas after the subsequent National Coal Wage Agreements of the year 1974 and 1979 the amount has increased many times and has turned out into lakhs. The staff making the payment are exposed to more risk of short cash as they are required to handle the enhanced amount due to increase in wages after National Coal Wage Agreements. The Sangh stated that even in 1971-72 the amount of Rs 5 and Rs. 4 given as payment allowance by the management was not commensurate to the extra work strain, responsibility and risk involved. Day-to-day payments are made, by cash and pay personnel. The staff other than cash and pay personnel are deployed only when there is bulk payment. This staff is not entitled to payment allowance at all if the number of workmen to be paid is a bit less than 200 or 300. Under the award of Mr. Bhave, who was appointed as the Arbitrator in respect of Kamptee and Inder Collieries, the staff in those Collieries are given much higher payment allowance. Those Collieries are just about 15 kms from S.G. Collieries. Similar condition of mode of payment prevails at both the group of Collieries. The management, however, refused to pay at higher rate the payment allowance to the workmen of S.G. Collieries. The Sangh prayed that the payment allowance be enhanced from 1-1-1978 i.e. the date on which the enhanced payment allowance was given to Kamptee and Inder Collieries or at any rate from 25-2-1980 i.e. the date of demand of the workmen in this reference.

12. The management resisted the claim of the Sangh and pleaded as follows. The pay and allowances of workmen working in the coal industry was the subject matter of recommendations by the Central Wage Board. Those recommendations were accepted by the Government and the parties and implemented in toto. All the demands of the workmen stand settled by the said recommendations. The wages are being paid according to the said recommendations. There is no provision for allowance as claimed in the said recommendations. What has not been recommended in the Coal Wage Board recommendations cannot be claimed now. After the Central Wage Board recommendations, negotiations were conducted between the management and all the unions functioning in the coal industry which resulted in National Coal Wage Agreement No. I in December, 1974. Subsequently, further negotiations took place and National Coal Wage Agreement No. II was arrived at. After these settlements there was no dispute whatsoever between the workmen and the mangement and all the disputes, stand settled by the said settlements. No dispute now survives which is capable of a reference.

13. The management further pleaded as follows. The reference involves questions of national importance and/or of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in and affected by such dispute. Therefore, such a dispute could only have been referred to a National Tribunal established under Section 7-B of the Industrial Disputes Act 1947. Making a reference in respect of S.G. Collieries alone is discriminatory and violative of principles of Article 14 of the Constitution. The coal industry and the unions functioning in the coal industry have mutually constituted a committee by name "Joint Binartite Committee in Coal Industry" (for short "JBCCI"). Through this Committee the management and the workmen's representatives at national level decided the disputes in connection with service conditions specially the wages and allowances, ignoring this Committee the Sangh has raised the present industrial dispute on the issue which is to be decided by the JBCCI. According to the management allowing individual dispute regarding wages and allowances will have repercussions throughout India in the various Collieries situated in various States. Conceding any allowance to the staff working in S.G. Collieries will open flood-gate and raise innumerable industrial disputes. The Union of India therefore, has acted without jurisdiction and without application of mind and the reference has been made mechanically. The management pays full amount of pay and allowances applicable to Clerks and Supervisors according to their job description and work. Making payment and supervising payment are minor and incidental part of their duties within the allotted working hours. However, if and when anyone works for more than 8 hours he is paid overtime wages according to the provisions of Mines Act. Therefore, there is no justification for making claim for any enhanced rate of pay and allowances to the Clerks/Supervisors.

14. The same pleas are reiterated in the rejoinders filed by the parties.

15. The first question that arises for my consideration on this part of the reference is whether the management of S.G. Collieries is justified in denying the enhanced rate of payment allowance to the Clerks and Supervisors who make the payments and supervise the payments to the workmen of S.G. Collieries. The Sangh has filed some documents on record. The management has not filed any documents. The Sangh has examined one witness by name Mohan Prasad Sharma a Clerk on payment duty on this point. The management has examined two witnesses, Mohammed Salimuddin, a Senior Personnel Officer, Silwere Project and Gurubachan Singh Kapur, Additional Chief Personnel Manager in the Industrial Relations Dept. of Western Coalfields Limited at Nagpur. One of the documents filed on behalf of the Sangh is an Arbitrator Award by Mr. S.G. Bhave, who was then the Regional Labour Commissioner, Bombay. This Award is dated 6th October, 1979. This is in respect of Kamptee and Inder Collieries. The coal industry was nationalised in 1973. Before nationalisation Kamptee and Inder Collieries were run in the Private Sector. S.G. Collieries were in the Public Sector from the very beginning. As is stated above, the system of making payment allowance to the Clerks and Supervisors was introduced in S.G. Collieries in 1971 and in 1972 under the two circulars. That system continued even after the Collieries were nationalised. That system was started in other nationalised Collieries also with effect from 18-2-1974 to ensure uniformity in the matter of payment allowance by adopting the system in the

erstwhile N.C.D.C. mines. The staff concerned in the Kamptee and Inder Collieries raised the demand for enhanced in the rate of allowance sometime in 1978. The matter was referred to the arbitration of Mr. Bhave. Mr. Bhave rendered an award on 6-10-1979. He fixed Rs. 15 for each day of payment for supervising the payments and Rs. 12 for each day of payment for making the payments.

16. The Sangh has placed on record a copy of the Arbitration Award of Mr. T.T. Tayade, who is described in the award as Ex. O.S.D. (IR) W.C.L, Nagpur. That award was in respect of the staff of Kurasia Colliery. It appears from that award that prior to emergency the Clerks listed for payment duty were being paid payment allowance of Rs. 5/- and Rs 4 per payment but during the emergency payment allowance was raised to Rs. 10/- and Rs. 8/- per payment Before the emergency the staff were paid some overtime wages. After emergency the overtime wages were discontinued. Instead of overtime wages some compensatory offs were given.

17. Now, the question is whether the demand of the staff concerned for enhancement of the payment allowance in S G. Collieries is justified. It is the case of the Sangh that the rates of Rs. 5/- and R. 4/- were fixed at that point of time in February 1971 and July 1972 when the market rates and other conditions and circumstances were far different from what they are today. According to the Sangh there is also considerable increase in the wages and other fringe benefits to the coal mines workmen after July, 1972. It is also submitted for the Sangh that in 1971 and 1972 the workmen were required to handle amounts in thousands whereas after the subsequent National Coal Wage Agreements in 1974 and 1979 the amount to be disbursed has increased many times and has turned into lakhs. The staff is now exposed to more risk of short cash. It is the case of the Sangh that the reason for introducing the system of making payment allowance to staff other than cash and pay personnel are firstly to compensate them for the extra strain and work-load (which is something abnormal to their routine work) and they are required to bear the risk of short cash, if any, for whatsoever reasons. The witness examined for the Sangh Mohan Prasad has stated that on payment day he has to make payment of about Rs. 1.5 and Rs. 2 lakhs at S.G. Sillewara Colliery and payment is required to be made to 250 to 300 workmen on each day of payment. He stated that before 1971 the amount to be paid was Rs. 40,000/- to Rs. 50,000/-.

18. Mohammad Salimuddin, Senior Personnel Officer, examined for the management admitted that the quantum of amount of wages of all the workmen in coal industry, including Clerks has increased as per National Coal Wage Agreement No. I & II. He admitted that Kaurasia Colliery is giving more payment allowance i.e. more than Rs. 4/- and Rs. 5/- to payment Clerks and Supervisors, respectively. He admitted in the cross-examination that there is no difference in the procedure of disbursement of wages in Kamptee Group of Collieries and S.G. Collieries.

19. I think the management is not justified in refusing to pay payment allowance to the Clerks and Supervisors at enhanced rates. One of the contentions of the management is that the dispute regarding allowances is settled by the recommendations of the Central Wage Board and the National Coal Wage Agreement No. I of 1974 and the National Coal Wage Agreement No. II of 1979. According to the management, after these settlements there is no dispute whatsoevr between the workmen and the management and all the disputes stand settled. This reference, therefore, is not competent. This contention of the management is, in my view, untenable. It is rightly argued for the Sangh that the payment allowance is paid to the Clerks and Supervisors not under the above agreements but under the circulars issued by the N.C.D.C. in 1971 and 1972. The recommendations of the Wage Board and the National Coal Wage Agreement are not filed on record by the management. A reference was made to them at the time of the arguments. It was not shown to me that this payment allowance was the subject matter either of the Wage Board recommendations or the National Coal Wage Agreements. It appears that some other allowances were granted to the workmen. As peyment allowance was not the subject matter of the said agreements it cannot be said that the staff concerned cannot make a demand for enhancement of the payment allowance already granted under the circulars referred to above. It is not shown to me from the said National Coal Wage Agreements that the staff concerned is precluded from making such a demand. It is then argued that the coal industry and the unions functioning in coal industry have mutually constituted a committee by name JBCCI in order to decide the dispute in connection with the service conditions especially the wages and allowances. It is not shown to me that the dispute regarding enhancement of payment allowance is covered by the functions of the JBCCI and that before making a demand it is obligatory on the staff concerned to get that dispute solved by JBCCI. It is admitted by the management's witness Mohammad Salimuddin that according to the award of Mr Bhave the staff concerned in Kamptee and Inder Collieries are getting the payment allowance of Rs. 12/- and Rs. 15/- respectively. It is well known that the market rates of essential commodities have considerably gone up and the value of rupee has considerably gone down since the rates of Rs. 4/- and Rs. 5/- respectively were fixed in the years 1971 and 1972. It also cannot be disputed that the wages and allowances of the staff have considerably increased under the subsequent agrements and settlements than those that existed in the years 1971 and 1972. It is also in evidence as stated by the Sangh's witness Mohan Prasad that the amount to be disbursed by way of payment has risen to Rs. 1.5 to Rs. 2 lakhs from the amount of Rs. 40,000/- to Rs. 50,000/-. The staff concerned; in addition to the strain that has to be undergone in disbursing this amount has to face the risk for short cash. They have to make good the amount in case they, by mistake give more amount to the workmen than the amount due at the time of payment. For all these reasons, I am of the view that the rate of payment allowance to the Clerks and Supervisors who make the payments and supervise the payments respectively should be enhanced. I would award Rs. 10/- for each day of payment for supervising the payments and Rs. 8/- for each day of pament for making the payments. This is irrespective of a number of workmen to whom the amounts has to be paid. It would appear from the evidence of witness UW-2, Mohan Prasad, that payment days are one or two in a month. The management is, therefore, not going to be subjected to some heavy expenditure on this account.

20. Mr. Nair, the learned counsel for the management, submitted that the Central Government should have referred such a dispute to a National Industrial Tribunal constituted under Section 7-B of the Industrial Disputes Act. He submitted that the question involved is one of national importance and is of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in such dispute; that conceding any allowance to the Clerks and Supervisors working in the S.G. Collieries will open flood-gate of innumberable industrial disputes from the workmen of other Collieries It is not known whether there were similar demands from the workman in other States before the Central Government. If there is same demand from the workmen of the industries in one State and if the appropriate Government is of opinion that an industrial dispute exists or is apprehended it is not, in my view, obligatory on the Central Government to refer the dispute to a National Tri-

bunal. When such a dispute is referred to an Industrial Tribunal constituted under Section 7-A of the Indstrial Disputes Act, what the Tribunal has to consider is whether the demand is justified. And if so, what relief should be given to the workmen concerned.

21. It was submitted on behalf of the management that the staff making this payment from the S.G. Collieries is paid overtime wages if they worked for more than the prescribed hours and that, therefore, payment allowance should not be enhanced. It is not in evidence that the staff was not paid overtime wages when the payment allowance was first paid to them. The payment allowance has, in my opinion, nothing to do with the overtime work done by the workmen. The payment allowance is paid mainly to compensate the workmen for the extra strain and risk involved in the work. While adjudicating upon the demand for enhanced rate of payment allowance what the Tribunal has to consider is whether the circumstances have changed since the amount was first paid. The contention of the management, therefore, that no payment allowance should be enhanced because the workmen are paid overtime wages for overtime work is untenable.

22. The next question is from what date the relief should be given to the staff concerned. It appears that the dispute was first raised by the Sangh before the management by their letter dated 25-2-1980 and before the Asstt. Labour Commissioner by their letter dated 8-7-1980 (see para 12 of the statement of claim). I think the aforesaid enhanced rates of payment should be given effect from 1-4-1980. The arrears payable in this regard be paid to the staff concerned within three months from the date of this award.

23. In view of the above discussion, I hold that the management should enhance the payment allowance with effect from 1-4-1980 as shown below :—

| | |
|---|---|
| (i) For supervising payments for each day of payment. | Rs. 10/- |
| (ii) For making payments for each day of payment. | Rs. 8/- |

The arrears payable on this account should be paid within three months from the date of publication of this award.

24. The above enhancement, I may observe, is quite modest. In view of the tremendous rise in the market prices and the substantial rise in the wages, if some Tribunal on the national level or otherwise finds that the enhancement should be still more, then this award should not prajudice the cause of the workmen.

25. My award accordingly. The parties shall bear their own costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

[No. L-18011(4)|80-D.IV(B)|D. III(B)]

S. S. BHALLA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd September, 1983

S.O. 3954.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya Khadya Nigam Mazdoor Sangh and their Workmen, which was received by the Central Government on 23-9-83.

BEFORE SHRI O.P. SINGLA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D.No. 66 of 1983

In the matter of disputes

BETWEEN

Shri Mohd. Amir
through
Bharatiya Khadya Nigam Mazdoor Sangh,
Abdul Aziz Road,
Lucknow.

AND

Food Corporation of India
5/7 Habibulla Estate, Hazratganj,
Lucknow.

PRESENT :—

Shri B.M. Roy for the Management
None for the workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-42012(/8),80-D. II(B) dated 22nd May, 1982 made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in not allowing Shri Mohad. Amir, Loader, Food Corporation of India Depot, Chandnari, Kanpur to perform his duties with effect from 15-3-75 is fair, just and legal ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. In his claim statement, the workman claimed that he joined the Management as casual worker,labour at F.C.I. Depot, Chandhari, Kanpur w.e.f. March 1971 to 12th June 1973 on daily rated basis Rs. 4/- per day and completed 240 days in a calendar year, but he was not continued and on account of trade union activities he was not given work by the Management and not taken on duty w.e.f. August 1975. He demanded reinstatement in service with back wages and stated that it was a case of violation of the provisions of the Industrial Dispute Act, 1947.

3. The Management contested the claim, inter alia, on the ground that he worked only for 31 days, i.e., in July, 1973-74 days, August, 1973—23 days, September, 1973—3 days and October, 1973—1 day and did not work for 240 days at all, with the Management. There was no question of any disciplinary action against the workman and none was initiated against him. Neither Shri Amir nor the petitioner in the present case did anything until 1980 and they seemed to have awaken to make a claim only in 1980 before the Assistant Labour Commissioner, Kanpur. The workman has been absent on 1-8-83 as well as today.

4. It seems that the stand of the management is correct in so far as the service of the workman with the Management is concerned that he worked with the Management only for 31 days during the period from July, 1973 to October, 1973 and it is for this reason that the workman has not appeared to substantiate his claim before this Tribunal. Accordingly, the submission made by the Management of Food Corporation of India made in the written statement are believed and the action of the Management is held to be justified and the workman is not entitled to any relief

5. The award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

September 7, 1983

O.P. SINGLA, Presiding Officer.

[No. L-42012(78)/80-D. II(B)]

New Delhi, the 7th October, 1983

S.O. 3955.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Arbitrater Shri M.G. Wanare Regional Labour Commissioner (Central), Asansol in the industrial dispute between the employers in relation to the Mallabhum Gramin Bank, Bankura and their workmen.

BEFORE THE ARBITRATOR UNDER SECTION 10-A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947.

Reference : Arbitration Agreement Dated 13-4-1983.

PRESENT:

Shri M.G. Wanare,

Arbitrator under Section 10A of Industrial Dispute Act, 1947 and Regional Labour Commissioner (Central), Asansol.

PARTIES:

Employers in relation to : Chairman, Mallabhum Gramin Bank, P.O. Bankura, West Bengal

AND

Their workman represented by : Mallabhum Gramin Bank Employees' Association, P.O. Bankura (Regd. No. 13,591). West Bengal.

APPEARANCES:—

For the employers : Shri Pradipta Bhattacharyya, Chairman, and subsequently Shri Bidhu Bhusan Sinha Babu, Mallabhum Gramin Bank then G.M., now Chairman, Mallabhum Gramin Bank.

For the Workman : Shri Ajit Kumar Ghosh, President, with Shri Mridul Kumar Roy, Secretary Mallabhum Gramin Bank Employees Association, Bankura, West Bengal with the concerned workman

Industry : Banking State : West Bengal.

AWARD

By an arbitration agreement dated 13-4-1983 under section 10-A of Industrial disputes Act, 1947 both the parties to the dispute referred the following dispute for my decision.

"Whether Shri Tarani Dhar Mahato, Clerk-cum-Cashier, Mallabhum Gramin Bank, Bagunkudar Branch in District of purulia is guilty of the charges levelled against him vide notice no MGB|HO|CH|1509|81 dated 17-3-1981 issued by the Bank particularly in the light of the enquiry held by the Bank management?

If not, what relief the workman concerned is entitled to?".

2. Briefly stated the facts giving rise to the this dispute are as under:

2.1. Shri Tarani Dhar Mahato, son of Motilal Mahato was appointed as clerk-cum-cashier and posted as such at Bagunkudar Branch of Mallabhum Gramin Bank in Purulia district, West Bengal and that on 17-3-1981 the said employee was charge-sheeted for wilful negligence of duty and lack of devotion to duty and disobedience and wilful violations of Bank's rules vide Exhibit -2 of the Bank and that he was placed under suspension and the enquiry was held to enquire into the charges and that Enquiry Officer of the Bank held the employee not guilty and that denove enuiry was ordered by the Bank and that the Mallabhum Gramin Bank Employees Association raised industrial dispute which is as state hereinabove has been referred to me for arbitrating the issues involved in the said dispute and pronouncing decision within 60 days from the date of the agreement dated 13-4-1983. The time of 60 days has been extended upto 15-7-1983 by mutual agreement on 21-6-1983. As required under law the arbitration agreement under Section 10A of the I.D. Act 47 was sent to the Government for further action at heir end.

3. After issue of due notices in advance to both the parties, this matter was scheduled for hearing on 22-4-83, 9-5-83,20-5-83, 1-6-83, 9-6-83 and finally for 21-6-83.

3.1. Both the parties initially on 27-1-83 agreed to refer this matter for obitration under the provisions of voluntary Instrument of Code of discipline is Industry to me but subsequently they decided to refer this matter for the arbitration under the statutory provisions of Sec. 10A of the Industrial disputes Act, 1947.

3.2 Both the parties submitted their statements|Counter statements in support of their say. I heard both the parties in person on various dated and finally on 21-6-83.

3.3 The President, Mallabhum Gramin Bank Employees' Association, hereinafter referred to as the "Association" and the Chairman, Mallabhum Gramin Bank, HO-Bankura shall be referred to as "the Bank" in these proceedings for the sake of brievity.

3.4. The Association presented their claim statement which is marked as Exhibit U.1 duly supported by copy of Enquiry proceedings. The Bank submitted their written statement marked as M-1. The Association filed their rejoinder marked as Ex. U.II and the Bank too furnished their additional say which is marked.

4. The Bank submitted that the preminary objections relating to jurisdication and maintainability of the terms of reference may be dealt with before merits of the case are examined. I have heard both the parties in this regard. I have examined the material placed before me. It is admitted by the Bank that the Bank's Chairman had signed an arbitration agreement under Section 10A of the I.D. Act and that I am chosen as an arbitrator by the Bank and the Association. It is sot understood how it could be said at this stage that the referenre to the learned arbitrator is beyond jurisdiction and not maintainable by law. The Bank is constituted under the Regional Rural Banks Act, 1971 (No. 21 of 1976) to which the provisions of Industrial disputes Act, 1948 are applicable the agreement between the parties under Section 10A of the said Act is vaild. Since arbitration is appointed under the valid agreement, the jurisdiction of the arbitrator is fully justifiably and legally attracted and the Arbitrator has jurisdiction within the statute. I over-ruled this objection of the Bank. The next point raised by the Bank was that the terms of reference bing vague and unspecific and is incapable of adiudication. I find both the parties coined the terms of reference to solve the dispute. The plainreading of the terms of reference does not indicate any vagueness and lack of specified matter. The Bank has

not even substantiated their objection under consideration. I hold that the terms of reference before me are not vogue and same are specific enough to adjudicate upon. This aspect of the Bank's objection is over-ruled.

5. Let me discuss merits of the case.

5.1. The case of the Association has been that Shri Tarani Dhar Manato, the employee involved in the dispute was appointed as Jr. clerk-cum-cashier on 1-2-1978 and posted at Bagunkodar Branch of the bank on 2-2-1978 and that the employee was chargesheeted on 17-3-81 for major misconduct-namely wilful negligence of duty, lack of devotion to duty and thereby causing monetary loss to the Bank and wilful violation of the Banks rules. The workman was suspended from 20-8-1980. The bank held domestic enquiry and it was alleged the employee was not found guilty and the management ordered denovo enquiry on the same issues. This is objected by the Association. Agitation was launched. The Association demanded implementation of enquiry Officer findings and reinstatement of the employee with back wages.

5.2. The Bank's contention has been that valuable like Gold, cash are to be kept in Iron safe with double lock, which is kept in the bank's branch and the bank manager and the clerk-cum-Cashier employee failed to do so and committed gross negligence of duty by allowing, keeping valuable in signature card index cabinet resulting theft of 1418.5 grammes of gold of the loanees. The bank found their enquiry held, to be faulty and defective and ignored it and bank's board of director ordered de-novo enuiry and disapproved lifting of suspension of the employee. The Association prevented holding of fresh enquiry.

The findings of the Enquiry Officer were that the charges framed against Sri Taranidhar Mahato were not established beyond reasonable doubt. The bank contended that the enquiry was not held in proper manner as required under the principles of natural justice and by allowing the Presenting Officer of the bank to cross examine the employee without allowing the employee to make deposition first thus the employee was denied reasonable opportunity to conduct defence. The findings of the Enquiry Officer did not give any reason on which his findings were based.

This is not the case of the Association who does not complaint anything about violation of principles of natural justice etc.

5.3. I find that the Branch Manager involved in this case was arrested by the Police authorities and case U|S. 457|380 IPC has been lodged. The Branch Manager is awaiting trial by the court of law. The Police had not levelled any charge against Sri Mahato nor any case is instituted against him.

5.4. The Bank charge sheeted the workman for misconduct :—

(i) Wilful negligence of duty;

(ii) Lack of devotion to duty and thereby causing monetary loss to the Bank;

(iii) Disobedience and wilful violation of the bank's rules.

The workman pleaded not guilty while replying to the charge-sheet. The bank has no regulations, rules standing orders detailing service conditions and procedure for dealing with employee's committing misconduct. Therefore, common law of master and servants has to be restored to process the misconduct of the servant.

5.5. The bank does not have nor the bank determined any standing orders or any regulations which laid down terms and conditions of service. This bank is creation of and under the Regional Rural Bank Act 1976 (No. 21 of 1976) and under sub-section (1) of Section 17 of the said Act, the Bank was expected to determine the terms and conditions of service.

5.6. Where there are standing orders they would of course constitute terms and conditions of services and to that extent, they will be binding on the parties thereto as a contract. But it does not follow what is not embodied in the standing orders can never be a misconduct if for instance an employee commits murder or other conizable offence which is not described in the Standng Orders which govern the service as a misconduct, surely it can not be said that on that account he is not guilty of misconduct making liable to disciplinary action entailing termination of service (LLJ 1965, Vol. II-Page 44 & 45—Bank of Madura case. Such views are also expressed in Exp. News Press Ltd. case—961 MLJ 100 at 106 Madras High Court. This is not defence of the Associaion nor it is contended by the Bank.

5.7. Under the circumstances we have to look for the provision of common law relating to master and servant. Under Common Law too there has been a riddle to define precisely the relationship of the master and servant. The relationship of master and servant arises from a contract of service. This has, therefore, to be determined according to the facts and circumstances of a particular case. In this case the terms of appointment do not spell out terms and service conditions of the employee concerned. Thus there does not exist any written contract which would be of any help to us in this case. The appointment letter to the workman is vague.

5.8 The Bank as already stated hereinabove held enquiry and Enquiry Officer held workman concerned not guilty. The enquiry has been held to be improper and de-novo enquiry was ordered.

5.9. A right to dismiss a workman exists under Common Law. The workman is under an implied duty to indemnify the employer in respect of the consequence of his negligent conduct-Lister-V-Ramfend Ice & Cold Storage Co.. Ltd. (1957) AC 555 HL. A workman owes a duty to his employer to exercise reasonable case in the performance of his duty. Where there is duty to take care or exercise certain skill, failure to take care, skill and deligence which is the duty of the person to belag in the performance of his work. In case negligence of a man does not ntend the conseuences is not at all relevant. The ommission to perform the duty may consist of variety of hings for instance—pretence of waiting instructions with a view to shirk work—1979 Vol. I LLJ—Loyality to the management are inherent in the jural relationship of master and servant and they need not be prescribed vide LLJ 1965 Vol-I-P. 349 and LLJ 1980 Vol-I page 295—where an employer order an employee that he should disclose the names of the members of superior staff who were in fault, it is the duty of the workman to comply with the order and his refusal to comply with the order will constitute the misconduct—LLJ Vol-I 1965-P-349—

Insubordinate of employee imports wilful disregard of express or implied direction.

5.10. In cases where standing orders or the service rules do not prescribe any procedure or there are no standing orders or service rules, the domestic enquiries though need not confirm to all requirements of judicial proceedings, they however, must satisfy the essential requirements of natural ustice—Central Bank of India Ltd. LLJ 1967 Vol. II—739 SC.

5.11 The evidence adduced before me by the parties and the evidence already available on the enquiry proceedings have been examined by me. I have applied my mind.

6.1. The Association contended repeatedly that the workman was not given training when the Gold Loan Scheme was introduced by the Bank and that the workman was never made aware by the Branch Manager of his responsibility, the guide-lines or requirements of circular No. MGL: HO|CM|114|79 dated 23-3-1979. The entire enquiry proceedings have been gone through by me. I find that the

Association streneously argued that since there was no training arranged for the workman, he was not aware of safe custody of gold pledged under the said Scheme. It is an admitted fact that there was no special training programme introduced by the management, this does not absolve anybody from responsibility. The plea advanced by the management was that their circular dealing with the scheme was so simple and laid down in detail the preliminary requirements to be fulfilled and that had the workman followed the circular which is written in simple language, there would not have been colossal loss to the Bank i.e. loss of about 1418.5 grames of gold. It is also an admitted fact that there was provided a fire-proof safe with double key lock system—one key of the safe was with the workman and the other was with the Branch Manager. It has been proved before the Enquiry proceedings that the gold bags were kept inside the drawer of safe by the Branch Manager. The plea of the employee has been that the key of the inside drawer of safe was kept with the Branch Manager and that he was not aware of the contents of the same drawer. The workman admitted that gold bags and some valuables were kept in the said drawer. It is strange that the employee took plea that he was not present whenever drawer/safe was opened. I fail to understand or to accept the plea of the workman that he was not present at the time of the opening of the drawer/safe when the safe is under double-lock-system and one of the keys are with him. It is not understandable nor acceptable that the workman was not present.

6.2. The Association pleaded that the employee was not made aware of his responsibility and that an impression was created amongst all the employees (total strength of Clerk of the branch including Manager was 3 only) that operation of the Gold Loan Scheme is the total responsibility of the Branch Manager and that the clerk-cum-Cashier is not at all involved. The Association brought forward Branch Manager who happens to be around the Enquiry Committee. The Branch Manager admitted that he never associated this workman with the handling of gold bags and that he had never shown the circular or instructions on the subject to the workman. To me, it seems that the Branch Manager had given the total cover to the workman for inaction or omission for the reasons known to him. It is surprising to as to how the Branch Manager was available when the Enquiry Proceedings were in progress, particularly when the Hd. Qrs. of the Branch Manager is 200 K.M. away from the place of enquiry. There was nothing to show that the Branch Manager was summoned in advance, neither he was stated as witness in the enquiry proceedings. However, it is strange and difficult to accept the situation how the Branch Manager was immediately available to give his statement before the Enquiry Officer. This leaves lot of area of doubt.

6.3. It is admitted before the Enquiry Officer that the workman had visited Hd. Qrs. office very often. It is inconceivable how the workman concerned failed to know elementary requirement of his responsibility, particularly when he was holding joint responsibility for the safe of which he was holding one key and in which gold bags were kept. It was a primary duty of a prudent person to know about his responsibility if he has any doubt or any impression. It could not be a plea that a workman who has put about 2 1/2 years of service as a Cashier, did not know anything about the safety of gold which was kept in a safe of which he one key was held by him. The workman admitted that key register exist in Branch which indicates the key of the lower drawer, any prudent person would have enquired about it, particularly when he has been holding joint custody of the safe and contents. It is admitted that the safe register was existing at the branch and it was not filled up by the Clerk, the reasons are better to be immagined in this case than to be described

7. In view of the above I find from the statement of the Association that the workman did not have reasonable opportunity to know his responsibility in the matter of gold loan. I do not agree with the Association.

7.1. It is admitted that the Gold Loan Scheme was circulated by the Bank on 29-3-1979. The scheme lays down following paragraphs for safely custody of ornaments :

"Ornaments pledged with the Bank must be kept in the fire proof safe and they should be under joint custody as applicable in case of cash. Pledged ornaments are to be kept separately in small cloth bags to be supplied by the Head Office as per indent placed by the Branch Manager.

Identification tags stating Gold Loan Account No. and name of the borrower is to be fastened with individual bag and another similar identity tag and testore certificate has to be placed inside the bag alongwith the pledged ornaments so that in case of outer card missing or destroyed, the inner one can help to ascertain the related Ornaments of the borrowal account."

In view of the above paragraphs, I do find that there was no need of any special training for any workman for the purpose. To advance a plea that the contents of the circular were not known to him is not acceptable for the simple reason that in the branch where there are only 2 clerks ,it can not be said that the circulars regarding safe or handling of gold was unknown. The clerks have received the circulars, dak from the Hd. Office and diarised them in the appropriate register. The plea of ignorance can not sustain.

7.2. As already stated in the foregoings paragraphs that the workman should have exercised reasonable care of his duty where there is duty to take care or exercise certain skill, the workman failed to do so, proved commitment or gross negligence on the part of the employee who might not have intended consequences and therefore he can not absolve of his liability. In this case the employee utterly failed to have due care in this regard which has resulted colossal loss to the Bank and as such the situation proved a lack of devotion to duty. I, therefore, find that the employee is guilty of lack of devotion to duty. There was no evidence to prove any wilful negligence or any disobedience or wilful violation of Bank's rules. He is not guilty on these counts.

8. I hold that the workman is guilty of lack of devotion to duty. I hold that the workman is not guilty of any misconduct of wilful negligence for duty and disobedience or wilful violation of Bank's rules.

8.1. Under the circumstances where the employee is not held guilty for misconduct for which there was charge, whether the employee is entitled to any relief as per terms of reference before me. Since the workman has not been held guilty on 2 grounds of misconduct referred to above, I hold that the employee is entitled to the following relief :

9. Shri Taranidhar Mahato is under suspension and from the date of suspension, till the date of this Award, no relief is admissible to the workman as he is guilty of lack of devotion to duty.

9.1. Since the employee is a young and he is not guilty on certain charges, he deserves some relief by way of giving him fresh appointment as Clerk-cum-Cashier and Sri Mahato should not be considered for promotion or upgradation for three years from the date of the appointment. The period from the date of suspension till the date of appointment shall not be treated for any benefit in effect this period shall be ignored for all the purposes. Sri Taranidhar Mahato shall commence his employment as new entrant for all the purposes. The relief to the workmen is qualified as above.

I award accordingly.

M. G. WANARE, Regional Labour Commissioner (C), Asansol

& Arbitrator U/s. 10A of the ID Act, 1947.

Place : Asansol.

Date : the 13th day of July, 1983.

[No. L-12012/160/83-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1983

का० आ० 3956.—मैसर्स कनिशा स्टील, आनन्द सोजित्रा रोड, बल्लभ विद्या नगर-388120, अहमदाबाद (गुजरात/6917) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(148)/83-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 1st October, 1983

S.O. 3956.—Whereas Messrs Kanisha Steels, Anand Sojitra Road, Vallabh Vidya Nagar-388120. Ahmedabad (GI/6917). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952). (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Schem, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(148)/83-PF. II]

**का० आ० 3957:**—मैसर्स एमसी० गम रविन्द्र लेबोरेटरीज (आई) लि०, अमराई वादी रोड, अहमदाबाद-380008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणिका भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/149/83-पी० एफ०-2]

S.O. 3957.—Whereas Messrs Mc. Gam-Ravindra Laboratories (I) Ltd., Amrai Vadi Road, Ahmedabad-380008. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time of time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with in 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(149)/83-PF. II]

**का० आ० 3958**.—मैसर्स तिरुपती कास्टिंग, आनन्द सोजित्रा रोड, वल्लभ विद्या नगर-388120, अहमदाबाद (गुजरात/4864-ए), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदें बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और, पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/150/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3958.—Whereas Messrs Trupti Casting, Anand Sojitra Road, Valabh Vidya Nagar-388120, Ahmedabad (GJ/4864-A). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estalishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (herinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him a a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benfits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(150)/83-PF. II]

का० आ० 3959.—मैसर्स मिलिंग ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, आनन्द सजोत्रा रोड, वल्लभ विद्या नगर-388120, अहमदाबाद (गुजरात/4864), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक, उस निधि तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/151/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3959.—Whereas Messrs The Milling Trading Private Company Ltd., Anand Sajitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120, Ahmedabad (GJ/4864), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceasd members who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S.35014(151)/83-PF.II]

का० आ० 3960.—मैसर्स इन्स्टीच्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेण्ट्स, चनाभट्टी सिओन (डाकघर) बम्बई-22 (महाराष्ट्र 1387) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध

बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/152/83-पी०एफ-2]

S.O. 3960.—Whereas Messrs Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Chanabhatti Sion (P.O.) Bombay-22 (MH/13287), (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the

Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(152)/83 PF III

का० आ० 3961.—मैसर्स फरुखाबाद ग्रामीण बैंक हेड आफिस, सहयोग भवन, चौरासी-फतेहगढ़, फरुखाबाद (तथा इसकी शाखाएं) (उत्तर प्रदेश/6560) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनूकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्यों के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि करने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/153/83-पी० एफ-2]

S.O. 3961.—Whereas Messrs Farrukhabad Gramin Bank, Head Office, Sahyog Bhawan, Chaurasi-Fatehgarh, Farrukhabad (and its branches) (UP/6560) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct, under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelld.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(153)/83-PF.II]

**का०आ० 3962.**—मैसर्स ई० हिल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० कारपेट मेन्यूफैक्चरर्स मिर्जापुर-1 पोस्ट बाक्स नं० 3 (उ०प्र०/27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य, निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/154/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3962.—Whereas Messrs E. Hill and Company Pvt. Ltd., Carpet Manufacturers, Mirzapur-1, Post Box No. 3 (UP/27) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishement are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(154)/83-PF. II]

**का०आ० 3963**—मेसर्स सुप्रीम रबर रिकलेमर्स लिमिटेड, कारंगलपेडी, मंगलौर (कर्नाटक/7751) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/(155)/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3963.—Whereas Messrs Supreme Rubber Reclaimers Ltd., Karangalpady, Mangalore (KN/7751), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952 (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted, under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(155)/83-PF. II]

**का०आ०** 3964.—मैसर्स दिल्ली आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०, जी०टी० रोड, पोस्ट बाक्स नं० 7 गाजियाबाद-201007 (उत्तर प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा निगम के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/156/83-पी० एफ०-2]

S.O. 3964.—Whereas Messrs Delhi Iron and Steel Co. Ltd. G.T. Road, Post Box No 7, Gaziabad-201001 (UP/70), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of

the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(156)/83-PF.II]

**का०आ० 3965.**—मैसर्स फिब्रेटेक इंजीनियर्स एण्ड मेन्यूफेक्चरर्स, जेय-केय पुरी, दादरी, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश/5073) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/157/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3965.—Whereas Messrs Fibretech Engineers & Manufacturers, Jay-Kay Puri, Dadri, District Ghaziabad (UP/5073), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, trasfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estament exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decea ed members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(157)/83-PF.II]

**का० आ० 3966**:—मैसर्स फार्ज एण्ड ब्लोवर कंपनी, नरोडा रोड, अहमदाबाद-380025 (गुजरात/20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर, के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा, निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/158/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3966.—Whereas Messrs Forge & Blower Co., Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/20), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the

Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahemdabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(158)/83-PF.I]

**का० आ०** 3967:—मैसर्स प्रयास कास्टिंगज प्राईवेट लिमिटेड, आनंद सचिवा रोड, बल्लभ विद्यानगर 388120 अहमदाबाद (गुजरात / 4477) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 को उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में हैं फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माल की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस 35014/159/83 पी० एफ०-2]

S.O. 3967.—Whereas Messrs Prayas Castings Private Limited, Anand Sajitra Road, Vallabh Vidya Nagar-388120, Ahmedabad (GJ/4477), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahemdabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of

the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(159)/83-P.F. II]

**का०आ० 3968.**—मैसर्स गुजरात स्टील ट्यूब्स लि०, बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, भद्र अहमदाबाद (गुजरात/4473) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निधि सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तो उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो वह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/160/83-पी० एफ०-2]

S.O. 3968.—Whereas Messrs Gujarat Steel Tubes Ltd., Bank of India Building Bhadra, Ahmedabad (GJ/4473), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(160)/83-PF.II]

का०आ० 3969:—मैसर्स मणीनागज प्रा० लिमि० कल्याण मिल्स के सामने ब्दोमी प्राईवेट लि०, प्रेमिसेस, नरोदा रोड, अहमदाबाद-25 (गुजरात / 4404), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन के, जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/161/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3969.—Whereas Messrs Machineage Pvt. Ltd. Opposite Kalyan Mills, Vdomi Private Limited., Premises, Naroda Road, Ahmedabad-25 (GJ|4404) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoy-

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(161)/83-PF.II]

का०आ० 3970:—मैसर्स उदय इण्डस्ट्रीज कोसी प्राइवेट लि०, प्रेमिसेस कल्याण मिल के सामने, नरोदा रोड, अहमदाबाद-25 (गुजरात/6478) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/162/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3970.—Whereas Messrs Uday Industries Vgoni Private Limited Premises Opposite Kalyan Mill, Naroda Road, Ahmedabad-25 (GJ/6478) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (herein after referred to as the said Act;)

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad. maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(162)/83-PF.II]

**का०आ० 3971**—मैसर्स वरूण सेल्प प्रा० लि०, फोर्ज एण्ड क्लोवर कं०, प्रेमीसेस नरोडा रोड, अहमदाबाद–25 (गुजरात/2327) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/163/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3971.—Whereas Messrs Varuna Sales Private Limited Forge and Blower Company, Premises Naroda Road, Ahmedabad-25 (GJ/2327) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

880 GI/83—12

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premiums in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covred under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(163)/83-PF.II]

**का०आ० 3972**:—मैसर्स सांगली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, सांगली (महाराष्ट्र 7202) और इसकी शाखाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रांतकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/165/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3972.—Whereas Messrs The Sangli District Central Co-operative Bank Ltd., Sangli (MH|7202) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inpection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(165)/83-PF. II]

का० आ० 3973.—मैसर्स बी० एस० मैटल प्रिंटिंग एण्ड प्रैसिंग वर्क्स, 74, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, आगरा-232006 (उ० प्र०/2821), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तरप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/166/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3973.—Whereas Messrs B. S. Metal Printing and Pressing Works, 74 Industrial Estate, Agra-282006 (UP/2821) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, trasfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(166)/83-PF. II]

**का० आ० 3974.**—मैसर्स उ० प्र० इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 10 अशोका मार्ग, पो० बक्स० नं० 213, लखनऊ-1 (उ० प्र०/5384), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा बीमा के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के निबंधों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो-

धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधी आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/167/83-पी० एफ०-2]

S.O. 3974.—Whereas Messrs U.P. Electronics Corporation Limited, 10 Ashoka Marg, P. Box No. 313, Lucknow-1 (UP/5384), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(167)/83-PF.II]

**का०आ० 3975.**—मैसर्स जौर्जिना एमसी–रोबर्ट मिमोरियल हास्पीटल, सिविल लाईन्स, कानपुर (उत्तर प्रदेश/4246), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचरियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/169/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3975.—Whereas Messrs The Georgina McRobert Memorial Hospital Civil Lines, Kanpur (UP|4246) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(169)|83-PF.II]

का०आ० 3976.—मैसर्स बेरको वेल्डिंग एण्ड इलैक्ट्रिकल्स प्रा०लि०, जी०टी० रोड, बाई-पास, जालन्धर सिटी (पंजाब/2569), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के वैधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/170/83-पी०एफ०-2]

S.O. 3976.—Whereas Messrs Berco Welding & Electricals Pvt Ltd, G. T. Road, Bye-Pass, Jullunder City (PN|2569) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and Pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir(nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(170)/83-PF. II]

**का०आ० 3977.**—मैसर्स भारत इन्डस्ट्रियल वर्क्स, 61-इन्डस्ट्रियल स्टेट, पी०बी० नम्बर 29, भिलाई-1 (मध्य प्रदेश/317), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/171/83-पी.एफ.-2]

S.O. 3977.—Whereas Messrs Bharat Industrial Works, 61, Industrial Estate, P.B. No. 29, Bhilai-1 (MP|317), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Fund, and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and Pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(171)/83-P.F. II]

का. आ. 3978.—मैसर्स बीको स्टील कास्टिंग्स, इण्डस्ट्रियल एरिया पो. बो. नं. 8, भिलाई-1, मध्य प्रदेश (म. प्र./2352), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए

बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्यप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/172/83-पी. एफ.-2]

S.O. 3978.—Whereas Messrs Beco Steel Castings, Industrial Area P.B. No. 8, Bhilai-1, Madhya Pradesh (MP/2352) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and Pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S. 35014(172)/83-P.F. II]

**का.आ. 3979.**—मैसर्स कार्दिला लेबोरेटरीज प्राइवेट लि. 294, जी. आई. डी. सी. इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर-2, गुजरात (गुजरात/1357-ए), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/173/83-पी. एफ.-2]

S.O. 3979.—Whereas Messrs Cadila Laboratories Private Limited, 294, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar-2, Gujarat (GJ|1357-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses invloved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S.35014(173)|83-PF.II]

का. आ. 3980.—मैसर्स यंओतमल डिस्ट्रिक्ट सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. (महाराष्ट्र/6887) और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां ऐसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल, रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/174/83-पी. एफ.-2]

S.O. 3980.—Whereas Messrs The Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd. (MH|6867) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme );

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(174)/83-PF. III]

का. आ. 3981.—मैसर्स भिलाई इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया, पो. बाक्स नं. 31, भिलाई, मध्य प्रदेश (म. प्र./756 इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन

के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन भूत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/176/83-पी. एफ.-2]

S.O. 3981.—Whereas Messrs Bhilai Engineering Corporation Limited, Industrial Area, P.B. No. 31, Bhilai, MP (MP/756) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme );

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All exepenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provision of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assumed to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(176)/83-PF II]

का. आ. 3982.—मैसर्स करुर व्यस्या बैंक लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 21, करुर-639001, (तमिल नाडु/4177), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/177/83-पी. एफ.-2]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 3982.—Whereas Messrs The Karur Vysya Bank Limited, P.B. No. 21, Karur-639001 (TN/4177) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ; including its branches which are reporting compliance through above code number only.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit—Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme );

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assumed to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(177)/83-PF.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 1st October, 1983

S.O. 3983.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No.1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahakali Colliery of Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-3 of 1982

PARTIES:—

Employers in relation to Mahakali Colliery of Messrs Western Coalfields Limited

AND

Their Workmen

APPEARANCES:—

For the Employer—Mr. P. Sadasivan Nair, Advocate
For Lalzanda Coal Mines Mazdoor Union, Nagpur—
Mr. S. R. Pendre, General Secretary

Industrial : Coal & Mines

STATE : MAHARASHTRA

Bombay, dated the 31st day of August, 1983

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-18012 (1)/82-IV(B) dated 27/29th April, 1982, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the management of Mahakali Colliery of Messrs Western Coalfields Limited and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below:—

SCHEDULE

"Whether the demand of the Lal Zhanda Coal Mines Mazdoor Union (CITU) Chandrapur for placing the 7 workmen shown in Annexure below in category-IV is justified? If so, from what date?"

ANNEXURE

1. Prashant Kumar Bhadra
2. Arun Sidam
3. Shalik Govinda
4. Bhaurao Narayan
5. Sanmuddin
6. Satyapal Narayan
7. Suresh Bankar

2. The management by its written statement dated 19-8-1982 raised a preliminary point. It was pleaded that at least six out of the seven workmen were not members of the Lalzanda Coal Mines Mazdoor Union (hereinafter referred to as the "Union") and, therefore, the said Union could not have taken up the case of non-members. The Union could only take up the case of their members and not the cases of outsiders. The sponsoring of the dispute by the Union was, therefore, illegal. It was pleaded that there was no industrial dispute before the Central Government and in the absence of an industrial dispute the Central Government had no

jurisdiction to make the reference to this Tribunal. The reference is, therefore, without jurisdiction.

3. On merits the management pleaded as follows. Seven workmen mentioned in the annexure of the order of reference were employed as badli workers except Arun Sidam and Sanamuddin who were appointed as truck loaders. The employment of a badli worker is not regular and depends upon the availability of vacancy. They are not on one job constantly and are allotted duties as per vacancies that may exist. They continued to work as badli workers till August, 1980. On creation of vacant posts, a D.P.C. (Departmental Promotion Committee) was held in the sub-Area level to fill up the posts from amongst the badli workers and others. On the basis of recommendation of the D.P.C. all the seven workmen were regularised as category-I mazdoor. They were attached to tyndal gang and sometime they were also called tyndal mazdoor category-I. However, in either cases they were category-I mazdoor and not tyndal. The management further pleaded as follows. None of the seven workmen worked as tyndal regularly and, therefore, the question of categorising them as tyndal does not arise. They are all doing the work of category-I mazdoor which is an un-skilled job. Mahakali Colliery has got certain sanctioned posts of tyndal with one tyndal supervisor and four tyndals who have been placed in category V & IV respectively. The management submitted that tyndal is a skilled post and the job description is given in the wage Board recommendations as "men generally employed in moving engineering stores, drums of oil and greases. They are also responsible for erection and dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery." This job requires good amount of skill. Tyndals are always assisted by mazdoors who are un-skilled and they are pleaced in category-I. The management pleaded that the Union has changed the stand at different stages. Firstly the Union submitted that all the workmen were working as tyndals from 1975. Subsequently, it submitted that they are working as tyndals from 1978. Before the Asstt. Labour Commissioner it was submitted that they are working as tyndal from 10-8-1980. According to the management, this contradictory stand of the Union clearly establishes the falhood of their case and total dis-regard for truth. It was submitted that the management which is run in the Public Sector does not indulge in the practice of taking work of different category or higher category from workers. The management asserted that the workmen were appointed as badli workers in 1975 and subsequently regularised as category-I mazdoors and they did not work and they were not employed as tyndals. The management prayed that the reference, therefore, be dismissed.

4. The Union filed a statement of justification on 18-8-1982 and another statement on 14-9-1982. It pleaded as follows. All the workmen were the members of the Union. The management did not object in the proceedings before the Asstt. Labour Commissioner that the workmen were not the members of the Union. Workman Prashant Kumar Bhadra was the Vice President of the Union. A statement in writing was obtained from the workmen by the officers of the management that they were not the members of the Union by telling them that they will be paid job rate for category IV. That writing is false. On merits the Union contended that the workmen were working as badli workers since 1975 and they were all along doing the work of tyndals since July 1978 and they are paid the wages for category IV Tyndals since June 1982 only. There is no designation as tyndal mazdoor. The Union, therefore, prayed that as the workmen are doing the work of category IV they should be paid wages of that category from July, 1978.

5. The management by its rejoinder filed on 27-9-1982 denied that a false writing was obtained from the workmen showing that they were not the members of the Union. It asserted that all the seven workmen were category-I mazdoors and they were attached to tyndal gang and that they performed the work of mazdoors and not tyndals. They assisted tyndals as mazdoors.

6. The question for consideration is whether the demand of the Union for placing the seven workmen in category IV viz., the category of tyndal is justified. And if so, from what date.

7. The management's witness Subodh Dube stated that all the workmen were doing the work of mazdoor and they were regularised in the month of August, 1980. It is common ground that these workmen were employed as badli workers in 1975. It is admitted by the Union in the statement of claim (see para 4 of the statement dated 18-8-1982) that the workmen were designated as tyndal mazdoor in August, 1980. Even though in their statement of claim in this reference the Union has claimed that the workmen are working as tyndals from July, 1978, their claim before the Asstt. Labour Commissioner (C) was that they were performing the duties of tyndals with effect from 10-8-1980, but that they were being paid wages of category-I as tyndal mazdoors. The contention of the Union is that there is no category as tyndal mazdoor and that when they were regularised they should have been regularised as tyndals and not as tyndal mazdoors. Admittedly, tyndal is category IV. Admittedly, the workmen were first employed as badli workers as mazdoors. Their claim now is that when they were regularised in August, 1980, they should have been straightaway regularised in category which is a much higher category and which consists of skilled workmen. Tyndal is category IV. It appears that the designation of "tyndal mazdoor" is not specifically mentioned in the Wage Board recommendations. When this question was put to MW-1, Dube, he stated that the category viz., tyndal mazdoor is not specifically mentioned. However, the category of mazdoor is there in the national Coal Wage Award No.1. He stated that there is a category of general mazdoor, mason mazdoor carpenter mazdoor, etc. He further stated that the wages of all of them are the same. He admitted that there is no express mention of tyndal mazdoor in the said award. Management's witness MW-3, Bhati who was for sometime working as the agent in Mahakali Colliery stated that tyndal mazdoor is one who assists tyndal. He also admitted that the category "tyndal mazdoor" is not specifically listed in the categories of workmen in their mines. He has, however, stated that even in the wage Board recommendations there is reference at one places to tyndal mazdoors differentiating from some oher mazdoors. Management's witness Dube has described in his evidence the work of tyndal as follows:—

> "Tyndal does the job of shifting engineering materials, and lubricants. They also do work of shifting of mining machinery such as pump, hallagues."

8. The contention of the Union is that there is no category specifically described as tyndral mazdoor. Therefore, when the workmen who were badli workers were regularised in August, 1980, they should have been straightaway designated as tyndal i.e. they should have been put in category IV. Now according to the management this Colliery has got certain special posts of tyndals with one tyndal supervisory. There are four tyndals who have been in category IV and one post of tyndal supervisor which is placed in category V. According to the management, tyndal is a skilled post. This is borne out by the recommendations of the Wage Board on which reliance is placed by both the sides. It is not in dispute that these workmen started as category-I mazdoor. The management's witness is Dube and Bhati stated about the procedure of promotion from category-I to II and so on. According to them before promotion from Class I there must be a vacancy for the post in category II. A workman has to complete three years in same category. Then he is eligible for promotion to higher category. Then D.P.C. considers the record of the workman and then they decide whether the workman should be promoted to higher category. Bhati stated that it is only in exceptional cases that an employee can be promoted to category IV from Category-I. This is done by D.P.C. He stated that the workmen in this reference are not promoted by D.P.C. It is even not the case of the workmen that they were placed in category IV by D.P.C. MW-1 Dube stated that there are four sanctioned posts of tyndals. In addition to these four there is one post of tyndal jamadar. It is not the case of these workmen that on account of their seniority they should have been promoted to posts of tyndals and that they are illegally superseded. In their statement of claim dated 18-8-1982 they

have stated that they are doing the work of tyndals since July, 1978, and that they should be paid the difference of wages on that basis because they were paid the wages of only category-I.

9. Now, beyond the bare word in respect of five workmen out of the seven (excepting workmen Arun Sidam and Shalik Govinda) there is no evidence that in fact they were doing the work of tyndals. In their statements of claim they contended that they were doing the work of tyndals from July, 1978. However, their case in the conciliation proceedings was that they were doing the work of tyndal with effect from 10-8-1980. The Union has produced two identity cards of Arun Sidam and Shalik Govinda. In those cards their designation is shown as tyndal. It does not appear from those cards on what dates they are issued. However, the evidence of MW-2, Helwade, throws light on that point. It appears from his evidence that the identity card was issued to Shalik Govinda on 17-3-1980 and to Arun Sidam sometime thereafter. MW-2 Helwade was examined by the management to show that the designation of "tyndal" was shown in the identity card by mistake. He was shown the identity card register in his evidence. That register showed that there was entry in respect of one Haridas at sr. no. 459 and his designation was shown as tyndal. The name of Shalik Govinda appears at sr. no. 462 and that of Arun Sidam appears at sr. no. 464. In those entries in respect of Shalik and Arun opposite the column "designation" the word "do" is written. These entries came below the entry of Haridas whose designation was shown as tyndal and that, therefore, the designation of these two workmen was also shown as the tyndal. That explanation is not convincing. However, what must have happened is that these two workmen might have been given the work of tyndal at that time temporarily for some time. It appears from the evidence that all the seven workmen were given the work of tyndal from June, 1982 to October, 1982 and thereafter they were again given the work of mazdoor. The claim in this reference, however, is that these workmen should be placed in category IV of tyndal which is a category of skilled workmen and the main reason why they claimed to be placed in that category is that there is no designation as tyndal mazdoor specifically in the Wage Board recommendations. Their claim, therefore, is that when they were regularised in August, 1980, they were wrongly described as tyndal mazdoors and that they should have been described as tyndal in category IV. It is difficult to unhold that claim. The Union has not brought any evidence to show that the cases of these workmen were of exceptional nature and that therefore when they were regularised in August, 1978 they should have been straightaway put in category IV. I therefore, find that the demand of the Union that these seven workmen should be placed in category IV is not justified.

10. One of the points raised on behalf of the management was that the Union was not competent to espouse the case of the workmen. It is substituted for the management that the seven workmen were not the members of the Union. Reliance is placed on behalf of the management upon a writing signed by six workmen. That writing is in the form of a letter addressed to the Secretary of the Union. It is dated 24-2-1982. The six workmen purported to tell in that writing to the Secretary that they were never the members of the Union and that they have never paid the subscription of the Union and the they were, therefore, not concerned with the Union. It is not clear whether this writing was in fact ultimately sent to the Secretary. However, that writing which bears the signatures of the six workmen is produced on record by the management. It is the contention of the Union that this writing was obtained by some officers of the management by bringing pressure on these illiterate workmen. The Union has examined two witnesses on that point by name Prashant Kumar Bhadra and Shalik Govinda. This writing is produced by the management. I am not inclined to place on reliance on it.

11. It is, however, contended on behalf of the management that it is not proved that all the seven workmen were the members of the Union. It is also submitted that the Union has not produced before the Tribunal the register of the members. The Union has, however, produced office copies of two receipts purporting to have been issued to the workmen Prashant Kumar Bhandra and Shalik Govinda. They are of the year 1981. It cannot be said on the basis of these receipts that all the workmen were the members of the Union in the year 1981 when the dispute was raised by the Union on their behalf. The two witnesses examined for the Union have stated that all the workmen were the members of the Union. However, they are not corroborated by documentary evidence in that behalf. Apart from this, Mr. Pendre, the General Secretary of the Union stated that this Union functioned not only in this Colliery i.e. Mahakali Colliery but it functioned in four other Collieries also. He further stated that in Mahakali Colliery there are four Unions. How many workmen working in the Mahakali Colliery are the members of this Union has not been brought on record. This Union therefore is not the Union of this establishment only. As it is not shown how many workmen of the Mahakali Colliery are the members of this Union, it is difficult to hold that this Union is competent to espouse the cause of the workmen in this reference. If the Union is not competent to espouse the cause of the workmen it will have to be held that there is no industrial dispute properly raised before the Central Government. I am, however not disposing of the reference on this preliminary point. Even on merits I have held that the Union has failed to show that its demand to place the seven workmen in category IV is justified. This reference, therefore, will have to be rejected.

12. My Award accordingly. No order as to costs.

M. D.KAMBLI, Presiding Officer

[No. L-18012(1)/82-D.IV(B)/III(B)]

S. S. BHALLA, Under Secy.

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 3984.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Akashkinari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 26th September, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 47 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Akashkinari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 20th September, 1983

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012 (427)/81-D.III(A) dated the 23rd April, 1982, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute

between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the Schedule to the said order and the said Schedule runs as follows :—

"Whether the demand of the workmen of Akashkinari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Area No. III, Post Office Sonardih, District Dhanbad for resumption of duty by Shri Thakur Manjhi, Miner is justified ? If so, to what relief is the workmen concerned entitled."

2. The dispute has been settled out of court. A memorandum of settlement dated 20-9-1983 has been filed in court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Reference No. 47/82

Employers in relation to the management of Akashkinari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited;
AND
Their Workmen

The humble petition on behalf of the parties above named most respectfully sheweth :—

1. That without prejudice to the contentions of the parties contained in their respective written statements, they have settled the dispute on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That the concerned workman Shri Thakur Manjhi shall be allowed to resume his duties as piece rated miner within 15 days from the date of this settlement provided he reports for his duties within that period. His option for resumption of his duties will be available for a period of 30 days only failing which he shall not be entitled for any job under the management.

(b) That the entire period of his absence from the year 1976 till the date of his resumption of his duty shall be treated on leave without wages and the concerned workman Shri Thakur Manjhi will not be entitled for wages, bonus or any other amount except the continuity of service.

(c) That the concerned workman will not absent from his duty without permission or authorised leave in future.

(d) That this settlement should be treated as a special case and will not be cited as a precedent in future.

(e) That in view of this settlement there remains nothing to be adjudicated

Under the facts and circumstances stated above, the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to hold the settlement as fair and proper and will be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For the Workmen :

1. Sd/- (Illegible)
2. Sd/- (Illegible)

For the Employers :
Sd/-
General Manager
Sd/-
Personnel Manager

Declaration

I, Shri Thakur Manjhi, the concerned workman do hereby declare and state that the contents of the terms of the settlement were duly explained to me in Hindi and I have fully understood the same and I accept the same on my own volition without any pressure from any side and I put my L.T.I. in the presence of witnesses in token of acceptance of terms of the settlement.

Witnesses :
1. Sd/- (Illegible)
2. Sd/- (Illegible)

L.T.I. of Shri Thakur Manjhi
(To be written in the presence of the witnesses).

[No. L-20012/427/81-D.III(A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 1st October, 1983

S.O. 3985.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of J. K. Nagar Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, P.O. J. K. Nagar, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28th September, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 104/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of J. K. Nagar Colliery of Eastern Coalfields Ltd. P.O. J. K. Nagar, Dist. Burdwan.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 22nd September, 1983

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U|Sub-Section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 referred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal-cum Labour Court, Calcutta for adjudication. Subsequently by Order No. S-11025(4)/80-D.IV(B) dated 14th/17th November, 1980 the dispute has been transferred to this Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the management of J. K. Nagar Colliery is justified in requiring the workmen (as per annexure) who have been working as underground haulage Khalasis/S. B. Attendant at J. K. Nagar Colliery to continue to put on the D. B. Switches which they are operating since take over in addition to the work of Haulage Khalasis. If not, to what relief the said workmen are entitled to."

ANNEXURE

| Sl. No. | Name of the workmen |
|---|---|
| 1 | Shri Ram Prabesh Tewari |
| 2. | Shri Hari Ahir |
| 3. | Shri Jatalal Agarwal |
| 4. | Shri Jagdish Mahato |
| 5. | Shri Jhagru Singh |

6. Shri Ramavatar Shaw
7. Shri Ram Chandra Ahir
8. Shri Ram Lakhan Singh
9. Shri Chandrama Ahir
10. Shri Gurnam Singh
11. Shri Ram Chandra Singh
12. Shri Ram Charan Chamar
13. Shri Changur Horijan
14. Shri Sidhu Harijan
15. Shri Ponya Singh
16. Shri Narayan Bouri
17. Shri Suhandar Singh
18. Shri Biswanath Pandey.

2. The case of the workmen is that they are designated and paid as haulage khalasis according to N.C.W.A.-I and II. It is, however, stated that they were ordered by the management to do the work of substation attendant in addition to their own duties as haulage khalasi. It is submitted that the said work does not come under the duties assigned to them and therefore they demanded for increased wages for additional work performed by them though the management unilaterally altered their designation as haulage khalasi-cum-Switch Board Attendant It is further stated that for doing the additional duty the workmen concerned are entitled to get wages of one category higher but as they have not been paid the said wages hence this Reference and prayer is that they are entitled to the wages of the next higher category with retrospective effect.

3. The case of the management, however, is that the concerned workmen have got no case at all. It is stated that all the 18 concerned workmen in the colliery in question since prior to take over by the Central Government used to perform the same duty which they have been doing even now after take over. It is stated that since prior to take over the concerned workmen besides operating on the haulage were also putting on the distribution switches fixed near the haulage operated by them. It is submitted that the haulage operated by the concerned workmen are driven by electricity and the supply of requisite power required for operating the haulage is controlled by distribution switch fixed at a place nearer to place where haulages are working and when there is power failure the said switches trip and the operation of the haulages automatically stop till the power comes back and when the power comes back the switches supply power to the haulage in the distribution board which have to be manually put on and this work is done by the haulage khalasis themselves because unless the switches are put on the haulage cannot operate. This job of putting on the distribution switches is a simple job and does not require any skill or training nor it involves any strain nor it takes any time. According to the management the said work of putting on the said switches is done by the haulage khalasis during their duty hours and this is done only when the haulage remains dead due to absence of power. It is further stated that unless distribution board switches are put on the haulages cannot work and thus it is a part of the duty of the haulage khalasis to put on the distribution switches meant for the haulages and so there is no question of giving any additional wages to these persons.

4. It is further stated on behalf of the management that besides haulage khalasis for operating haulages there are other machines such as pumps, coal cutting machines, drills etc. for which there are separate operators. For operating the pumps, coal cutting machines and drills etc. there are separate operators and there are separate switches for pumps, coal cutting machines and drills and the Pump Khalasis, Coal Cutting Machine Drivers, Drillers etc. have also to put on their respective switches supplying power to their machines operated by them for which no extra wages are being paid to them also because this practice and tradition is existing in the coal mining industry since before nationalisation. It is, however, stated that on the request of haulage khalasis their designation was put as Haulage Khalasi-cum-Switch Board Attendant but there was never any assurance by the management that after change of designation any extra wages would be paid by the management. It is submitted that as the demand of the union is fully unjustified the workmen concerned are not entitled to any relief.

5. The point to be decided is as to whether the management is justified in requiring the concerned workmen who have been working as underground Haulage Khalasi/Switch Board Attendant to continue to put on the distribution board switches which they are operating since take over in addition to the work of haulage khalasi. If not, to what relief the said workmen are entitled.

6. On behalf of the workmen 2 witnesses have been examined while the management has examined MW-1 the Manager. It may be stated that though in the evidence the workmen have come to state that the work of putting on the distribution board switches are taken from them after take over, but this fact is not stated in their respective statements at all. Rather, it is the definite case of the management that the work of putting on the distribution board switches after the power is restored is being done by these workmen since before take over. From the evidence of the witnesses examined from both sides it will appear that there is a substation on the surface from where power is supplied underground. There are separate attendants for the substation on the surface for putting on the switches on the surface. From the surface power is transmitted underground through distribution switches and the distribution line supply power to the machines known as haulage, coal cutting machines, pumps and drills. On the distribution board there are separate switches for haulages, drills, pumps and coal cutting machines. When there is power failure and again power is restored, respective operator of these machines go to their respective switches on the distribution board and switch on their respective switches so that their machines can work and unless the switches are put on the respective machine cannot operate. This fact is admitted by the workmen witnesses themselves. WW-2 in his very chief has stated that there are separate switches for drills, pumps, haulages etc. and each machine has also got a separate switch and when the main switch is on the switches for different machines at different sections are put on. It is also admitted by him that on the surface there is a separate switch board for which there is a separate Switch Board Attendant of Category III. This witness in paragraph 6 has further admitted that haulage khalasi has got no concern with coal cutting machines, drills, pumps etc. and there are separate operators for them and they have also got switches in concerned section. It is also admitted by him in paragraph 8 that it takes no time to put the switch on but time is taken only for going to the distribution board. WW-1 has admitted in para 6 of his cross-examination that operators operate their own switches on the machines and there is a cable connecting the distribution box for each machine It is also stated by him that the switches on the distribution box trip when there is electrical break down and when the power is restored they have to make their switches on. This fact is stated by MW-1 also. He has also stated that power is supplied by distribution board switches and there are distribution board switches for coal cutting machines, drills and pumps. Thus from the evidence of the workmen themselves it is clear that when the power is restored the haulage khalasis that is the concerned workmen only go near the distribution board and put their respective switches on for which almost no time is required There is no evidence nor there is any denial that the putting on of the switches require any skill. This work is done by the concerned workmen during their duty hours only when there is power failure. Now unless switches are put on the haulages cannot operate and thus apparently this is a part of the duty of the haulage khalasi to put on the switches on the distribution board so that their machines can operate. This work according to the management is done by them since before the date of nationalisation. As stated earlier the workmen have stated that this additional work is done by them after nationalisation but it is not their case in their written statement filed before this Tribunal.

7. Though in evidence the workmen have stated that their designation was changed to haulage Khalasi/Switch Board Attendant against their will but WW-1 has admitted in para 9 of his cross-examination that they had requested the management to change their designation There is no iota of evidence to show that the management ever assured of any extra wages for change of their designation.

10. It was, however, contended on behalf of the workmen that the job description of Haulage Khalasis is mentioned in the Coal Wage Board recommendation and it does not say that the job of putting on the switches on the distribution board is also part of their duty and so this is an extra work for which the workmen should get extra wages. But it may be mentioned that the job description as given in the Coal Wage Board recommendation is simply illustrative and not exhaustive and further unless switches on the distribution board meant for operation of haulage are put on, the haulage cannot operate and so automatically for operating the haulage it is the part of the duty of the Haulage Khalasi to put on their respective switches.

11. On behalf of the workmen Ext. W-2 series have been filed to show that their designation has been change as Haulage Khalasi-cum-Switch Board Attendant. These documents are not at all material as this fact is admitted by the management also. Exts. W-1 & W-1|1 are the pay slips of the concerned workmen but they are not at all relevant for the purpose of this case. It is, however, contended on behalf of the workmen that Exts. W-3|4 is the wage slip of one Juman Mia of another colliery which shows that besides getting wages of haulage Khalasi he is getting Rs. 2|- Per day for working as Switch Board Attendant and on the basis of this pay slip, it is contended, that the concerned workmen should atleast get Rs. 2|- per day for putting on the Switches. Ext. W-3|4, however, does not indicate that some amount has been paid to that workman as his extra wages.

12. From the evidence of the management it is clear that the concerned workmen were also putting on their respective switches since before nationalisation and so no additional work is being taken from them and further from the circumstances of the case it is clear that it is part of their duty. The mnnagement has filed Ext. M-1 series to show the distance of the distribution switch from the place where the haulages operate and the distance is about 200 to 500 ft. only. The task of going to the distribution switch board for putting the switch on is done only when the haulages do not operate due to power failure and so the job of putting on the switch is done by them during their duty hours for which no extra skill is required.

13. Considering the evidence on record and facts and circumstances of the case, I shold that the management is justified in requiring the concerned workmen to continue to put on the distribution switches which they are operating since long and in the circumstances they are not entitled to any extra wages nor to any other relief.

14. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(28)|79-D.IV(B)]

A. K. SAHA MANDAL, Desk Officer

New Delhi, the 30th October, 1983

S.O. 3986.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. H. Curranee and Company, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th September, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambli Esqr., Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-27 OF 1981

PARTIES :

Employers in relation to M/s. H. Curranee and Company, Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer : Mr. K. R. Dengle, Advocate

For Bombay Port Trust Employees' Union, Bombay : Mr. S. K. Shetye, General Secretary

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 31st day of August, 1983

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by order No. L-31011(11)|81-D. IV(A) dated 2nd December, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to M|s. H. Curranee and Company, Bombay, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. H. Curranee and Company, Clearing and Forwarding Agents, Bombay, in depriving the under-mentioned 168 Filling workers of employment from 22nd January, 1981, is fair and justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

(Names of the workmen are attached as annexure 'A' to this Award).

2. The Bombay Port Trust Employees' Union (hereinafter referred to as the "Union") in the statement of claim submitted that M/s. H. Curranee and Company (hereinafter referred to as the "Company"), clearing and forwarding agents, Bombay, engaged 168 filling workmen and 45 stitching workmen in connection with filling bags and stiching bags of bulk sulphur brought in ships and unloaded at various wharves at Indira Dock, Prince's Dock and Victoria Dock at Bombay port right from the period of January, 1975, till 22-1-1981. The Union submitted that the required labour force as above was supplied to the Company by M/s. Shroff & Company, shipping, clearing, forwarding and transport agents. The filling workmen are working in 21 gangs each time per shift and each gang consisted of 8 filling workmen. After the bulk sulphur was unloaded from the ship with the help of wharf cranes of Bombay Port Trust the same was filled into bags by these filling workmen and thereafter bags were stitched for closing them by the 45 stitching workmen. The Union further stated that in the year 1979 all these workmen joined the Union. This action on the part of the workmen in joining the Union was not liked by Chinnathambi, who was working as the muccadam of the Company in the name of his son C. Selvaraj. Chinnathambi was looking after the work of supply of labour to both M|s. Shorff & Company as well as this Company. According to the Union, right from the year 1975 till January, 1980, whenever ships carrying bulk sulphur visited this port for unloading the cargo, invariably these 213 workmen were engaged for the work of filling and stitching of bags of bulk sulphur unloaded in the docks. But, after they joined the Union, Chinnathambi who was supplying labour from the pool of labour of M/s. Shroff & Company started harassing them and from January 22, 1980, the Company engaged altogether new labour for carrying out the work of filling the bags and stitching them and thereby deprived the regular workmen concerned in this reference of thier legitimate work. The Union states that when the aggrieved workmen approached the Company with their complaint they were told that the company had engaged new labour in their places as their work was not found satisfactory. Aggrieved by this unjust action of the Company all the workmen approached the Union and requested them to raise an industrial dispute on their behalf. It is submitted by the Union that the Union enquired of the Company as to why the workmen were deprived of their job. However, the Company did not give any satisfactory reply and continued to engage outside labour. The Union, therefore, raised an Industrial dispute with the Regional

Labour Commissioner, Bombay, on 23-1-1981. The matter was taken up in conciliation by the Asstt. Labour Commissioner. However, the conciliation proceedings failed to bring about an amicable settlement and the Asstt. Labour Commissioner submitted the failure report to the Government. The Union submitted that on an average each workman was earning Rs. 400/- per month. The Union, therefore, prayed that the Company be directed to restore the work of bagging and stitching of bulk sulphur unloaded at the port of Bombay to 213 workmen including 168 filling workmen and 45 stitching workmen.

3. It may be mentioned that the reference made by the Central Government is in respect of 168 filling workmen only. The Union, however, in its statement of claim prayed for relief in respect of stitching workmen also though they are not covered by this reference.

4. The Company by its written statement filed on 18-5-1982 submitted that it had never employed the workmen under reference for its work in the Bombay Docks. The Company pleaded as follows. Chinnathambi was the Company's contractor for handling bulk sulphur in the Docks. The workmen, if any, for handling the bulk sulphur were engaged by Chinnathambi. The Company had nothing to do with their employment or their appointment or their wages. In fact, the Company never issued any dock entry permit to the workmen concerned. The Company is, therefore, wrongly impleaded in the dispute. No valid industrial dispute has been raised with the Company Without any prior notice or intimation to the Company, Chinnathambi abruptly abandoned the contract and caused considerable loss and inconvenience to the Company. The Company had, therefore, no other alternative but to seek and enlist the services of another contractor to handle the bulk sulphur in the Docks. By itself the Company had never engaged any workmen for their work as such. The Company has now found that Chinnathambi got himself employed in the Food Corporation of India. The dispute, if any exists between Chinnathambi and the workmen. On these pleadings the Company submitted that it had nothing whatsoever to do with the dispute between Chinnathambi and its workmen and the reference against this Company may, therefore, be rejected.

5. By its rejoinder to the statement of claim the Company reiterated the above pleas.

6. The points that arise for my consideration in this reference are (i) whether the workmen were employed by the Company, (ii) whether the Company has deprived the workmen of employment and (iii) to what relief the concerned workmen are entitled as against the Company.

7. The parties have filed a few documents. By way of oral evidence the Union examined one of the workmen by name Perumal Bhagwati as (UW-1). The Company examined one Ganapatrao Honavar, the Proprietor of the Company.

8. After the workmen were stopped from work, no any dispute has been raised by them or by the Union with the Company. It is for the first time in the examination-in-chief that witness Perumal stated that they asked for rise in the rate of wages; that they, therefore, approached the Proprietor of the Company; that therefore, they were stopped from work. This plea has not been raised by the workmen or the Union either in the letter dated 21-1-1981 to the Regional Labour Commissioner nor in the statement of claim filed by the Union nor in the affidavit filed by Perumal by way of examination-in-chief. It is only in the supplementary examination-in-chief that this plea has been taken up. Apart from this, it is not the case of the Union that after the workmen were stopped from the employment a demand was made on behalf of the workmen with the Company to take them back for work. Before taking up the dispute with the Regional Labour Commissioner by its letter dated 23-1-1981; no demand was made by the Union or workmen on this Company.

9. In the statement of claim in para 4 it is admitted that the labour force consisting of filling workmen and stitching workmen was supplied to the Company by M/s. Shroff & Company. In para 5 it is stated that one Chinnathambi is the muccadam of the Company and he did not like the action of the workmen in joining the Union in 1979. In para 6 of the statement of claim it is stated that the workmen after they joined the Union were harassed by Chinnathambi. It will thus be seen that it is not even the case of the Union that these workmen were employed by the Company. The case of the Company is that Chinnathambi was its contractor for handling bulk sulphur and the Company had nothing to do with the employment of the workmen. In his affidavit Company's Proprietor Honavar has stated that he never employed the workmen and that the Company never paid any wages to the workmen. He added that they were never on Company's muster-roll or pay-roll. However further stated that Chinnathambi was also never on Company's pay-roll or muster-roll, Honavar has affirmed in his affidavit that his Company has no direct or indirect relations with the workmen under reference. He stated that neither the workmen nor the Union served any notice on him, about their claim. They received the notice for the first time from the conciliation officer. He added in his supplementary examination-in-chief that the workmen under the reference never came to him with any grievance. However stated that he made payments to Chinnathambi on the basis of tonnage and also on the basis of number of bags filled. He stated that he never issued any dock entry pass to any of the workmen. It appears that the dock entry permits are issued by Yellowgate Police Station and the companies interested in the workmen write letters to that Police Station to issue necessary permits. Honavar stated in his deposition that he never issued letters requesting the Police Station to issue permits to these workmen. A question was put to Honavar in his cross-examination to the effect that Chinnathambi was looking to his work of handling bulk sulphur in the Docks. A further question was put to him that Chinnathambi was using the same labour for this Company and also for M/s. Shroff & Company. The witness replied to these question in the affirmative. These suggestions on behalf of the Union also support the case of the Company that the workmen were employed by Chinnathambi. A question was asked to Honavar as to whether he knew why Chinnathambi stopped employing the labour for his (Company's) work. Honavar stated in reply to this question that Chinnathambi told him that he was not interested in the contract. He (Honavar) did not ask him why he was not interested in the contract.

10. The Company has produced two bills on record. These bills were sent to the Company by Chinnathambi claiming their bill for the work done. These bills show that the Company paid the amount to Chinnathambi. Even the Union does not claim that the workmen were paid by the Company.

11 UW-1, Perumal, one of the workmen stated in his cross-examination that in order to enter the Docks a pass is required to be obtained. He stated that M/s. Shroff & Company issued such a pass in his favour. What he meant to say is that M/s. Shroff & Company gave letter addressed to the Inspector of Police, Yellowgate Police Station stating that they were their workmen and the Yellowgate Police Station in the basis of that letter issued dock entry passes. Perumal admitted that M/s. Shroff & Company gave such letters to all the workmen. He stated that he was an ordinary workman in M/s. Shroff & Company and this Company gave him work for the last 12 years. He added that Chinnathambi prepared a voucher on behalf of the Company and made payments. He admitted that the Company never gave letters to them for obtaining dock permits. He admitted in clear term that Chinnathambi made payments to them.

12. The Company has produced the letter dated 18-8-1981 addressed to the Astt. Labour Commissioner in the course of the conciliation proceedings. There the Company had asserted that they did not receive any notice of demand from the Union. It was clearly stated in that letter that the Company did not receive the Union's alleged letter dated 23-1-1981 claimed to have been written to the Company. It would appear from all these materials that these workmen were employed by the contractor, Chinnathambi and that they were stopped from work by him. That Chinnathambi was their employer has been accepted by the workmen. When they were stopped from work they never made a demand to this Company calling upon it to take them back for work. I, therefore, hold that these workmen were not employed by this Company and they were engaged by the contractor. The contractor must have used them for the work of this Company. The contractor received the amounts for the work done on the basis of tonnage and the bags filled. These workmen, therefore, were not the workmen of this company.

13. Mr. Shetye, the General Secretary of the Union, referred to the terms of reference as embodied in the schedule and submitted that according to the Central Government it was the Company who had employed these workmen and who had deprived the workmen of the employment. The letter sent by the Company to the Asstt. Labour Commissioner dated 18-8-1981 in the course of the Conciliation proceedings is referred to above. In that letter the Company has clearly alleged that Chinnathambi was their contractor and that the Company is not concerned in the alleged dispute. It was only to honour the notices sent by the Asstt. Labour Commissioner that they appeared in the conciliation proceedings. The Company, therefore, prayed in that letter that they should not be impleaded in the dispute for which they are not responsible. The Union has not produced before me a copy of the failure report. It appears that the allegation of the Union was that the workmen were terminated from doing the work of the Company. It appears that on the basis of that allegation the term of the reference came to be framed. From the material placed on record, it cannot be said that this Company had employed these workmen. It is open, in my view, to the Company in this reference to show that they had not in fact employed the workmen and there was no relationship of employer and employees between them and the workmen.

14. Though it is not specifically pleaded in the statement of claim filed on behalf of the Union it is argued that the workmen are entitled to relief from Company, on the basis of the provisions in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Mr. Dengle, the learned counsel for the Company, submitted that the provisions in the Act do not apply to establishments in which work only of an intermittent or casual nature is performed. He referred in this behalf to the provisions in Section 1(5)(a) of the said Act. It is admitted in the statement of claim that the workmen came to be employed whenever the Ships carrying bulk sulphur visited the port for unloading the cargo in the Docks (see para 6 of the statement of claim). MW-1 Perumal admitted in para 2 of the affidavit that besides the work of M/s. Shroff & Company he had been also attending to the work of this Company. In para 5 of the affidavit he admitted that from the year 1975 till January, 1980 whenever ships carrying bulk sulphur visited the port for unloading the cargo in the Docks of Bombay Port Trust these workmen were employed for filling and stitching the bags of bulk sulphur. Perumal admitted in his deposition that during the last 12 years he is working in three companies i.e. two other companies besides this Company. However stated in his deposition that this Company is handling about 8 to 10 ships per year for unloading sulphur. It would thus appear that the work performed by the workmen, so far as this Company was concerned, was of intermittent nature. Apart from this, the question is whether the workmen are entitled to any relief against this Company under the provisions of the said Act.

15. Chapter V of the Act deals with certain amenities required to be provided under Section 16 to 19 of the Act for the benefit of the contract labour employed in an establishment and it further states that if any such amenity is not provided by the contractor within the time prescribed therefor, such amenity shall be provided by the principal employer. Section 21 makes principal employer also responsible for payment of wages. No any provision from this Act is shown to me casting some liablity on the principal employer if the contractor stops the workmen from service. Apart from this provision, the work performed by the workmen was of an intermittent nature. They were not doing the work in connection with the sulphur bags of this Company only but admittedly they were working for other Companies also. Another most important circumstance to be noted is that the workmen have not made any claim against Chinnathambi. The Company has specifically stated that Chinnathambi was necessary party to this dispute. Still the Union has not taken steps either at the time of raising the dispute or in this reference to implead Chinnathambi as a party. In the absence of Chinnathambi it would not be proper to grant relief to workmen as against this Company.

16. In the result, I find that it is not proved that the management of M/s. H. Curranee and Company has deprived the workmen of employment and that, therefore, the workmen are not entitled to any relief as against this Company.

17. My award accordingly. No order as to costs.

Encl :—Annexure 'A'.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

Names of the workmen :

1. Peria Samy Kurmansamy
2. Pannear Krishnan
3. Thangaraj Mailan
4. Irison Sadaiyan
5. Murugan Pichaigaran
6. Palani Chellamuttu
7. Seliamani Mayavan
8. Kolanchi Kuppan
9. Ranganathan Rama Samy
10. Vijayan Palanisamy
11. Perumal Pagavati
12. Muttu Sadalai
13. Kannan Madasamy
14. Netaranjan Seeman
15. Paneer Selvan Venkatmsamy
16. Arumugan Karuppan
17. Chelaiya Sundran
18. Raju Karuppusamy
19. Velu Pichiya
20. Velu Sudalli
21. Durai Pandi Palavasan
22. Ashok Essiki
23. Natrajan Ramayya
24. Raju Subhaish
25. Paramesivam Sudalai
26. Sarangam Pawadai
27. Kasi Mailan
28. Selwaraj Ponensamy
29. Kesavan Muthuswamy
30. Venkatesa Arumugam
31. Murgesan Muniyan
32. Arumugam Sadayan
33. Devrajan Kathar
34. Durairaj
35. Tukaram Vithal
36. Abhiman Vishwanath
37. Manohar Dhabani
38. Mahadev Devrao
39. Limbaji Usane
40. Sambhaji Chotta Kamble
41. Bhimsa Kalu Surease
42. Gangaram D. Hawale
43. Damaji Eknath Sarvade
44. Ankush Tulsiram Survese
45. Abhiman Namdev Survese
46. Dasharath Vaisnath Survese
47. Shivaji Sawle Survase
48. Udayar Fasaki

49. Mani Annamalai
50. Pandiyan Sabramani
51. Sitthatinam Khanigaivel
52. Kolanchi Sami Kann
53. Curuswamy Thavai
54. Shiru Anandaram
55. Dayasundar an Sankarai
56. Ayyaswamy Subhaish
57. Muniyaswamy Subbaish
58. Tavdan Annadappan
59. Murugasan Pariyaswamy
60. Balaji Kottanayagan
61. Sadvan Chinnappayan
62. Anthony Pregesh
63. Andi Palani
64. Kannan Kandan
65. Swami Durai
66. Thangaraj
67. Kannayiram Duraiswamy
68. Kuppan Kali
69. Mayavan Narayan
70. Kadirvelu Netasan
71. Krishna Murthy Ponnuswamy
72. Saravannan Narayanan
73. Gunasekaran Narayanan
74. Narayanan Manikam
75. Gopal Ammavasai
76. Arumugam Narayanan
77. Murgesan Velayudan
78. Selvaraj Periyaswamy
79. Thangavel Verran
80. Thangraj Substiyan
81. Perumal Pachamuthu
82. Rajakannu Periayn
83. Rajalingam Annamalai
84. Thangarj Madaswamy
85. Perumal Pachamuthu
86. Pichiya Karuppuswamy
87. Periyaswamy Erusan
88. Kolanchi Poomalai
89. Sundar Husainappa
90. Amrut Rayappa
91. Mustan Tukaram
92. Nallappa Lalappa
93. Arjun Sanappa
94. Barat Lalppa
95. Iswar Lalappa
96. Pandhari Bhosappa
97. Pashamiya Mahboob Saheb
98. Janimiya Rukumuddin
99. Issawuemiya Mahaboob Saheb
100. Anand Tjopanna
101. Jarippa Ramanana
102. Dasharath Hanumanta
103. Nasirmiya Mahaboob Saheb
104. Sardarmiya Mahaboob Saheb
105. Erappa Hanumanta
106. Malikasum Bhimanna
107. Amrut Rayan Sidapan
108. Hanumanta Kalappa
109. Kadersha Mahaboob Sha
110. Sayed Allabaksh
111. Habib
112. Mainecrdin Mahaboob Sahab
113. Mainuddin Lalsha
114. Yusuf Sha Lalsha
115. Yusuf Usman Ali
116. Dashrath Ratnappa
117. Arjun Devappa
118. Chhotamiya Rajamiya
119. Beerappa Mugalappa
120. Adigappa Narseppa
121. Gundappa Narsappa
122. Mallappa Narsappa
123. Bhimsa Shankar
124. Manik Nagappa
125. Manik Tukappa
126. Bhimsa Narsappa
127. Amrut Nagappa
128. Bhimsa Nagappa
129. Kashinathan Pariyaswamy
130. Palraj Venkataswamy
131. Thandepani Duraiswamy
132. Veeragu Lingarajan
133. Arasan Kothapalai
134. Satoo Veerswamy
135 Mayavan Abbai
136. Sinnathambi Sanyasi
137. Kasi Mari
138. Mari Veeran
139. Mani Kesavan
140. Babu Poomalai
141. Meerasa Nattrasa
142. Armugam Ramaswamy
143. Raju Perumal
144. Sekkalingam Rangaswamy
145. Thangaraj Rangaswamy
146. Samba Ananda Shinde
147. Baboo Sivram Balerao
148. Vasani Madhav Gaikwad
149. Dharmu Sakharam Bhalerao
150. Naganath Manjappa Howle
151. Ram Rayappa Shine
152. Bansi Pandhari Pol
153. Sitaram Vithal Kasbe
154 Uttam Maruti Landhe
155 Tulsiram Gaikwad
156. Vemboo Kamanna
157. Raman Gurunathan
158. Arumugam Erusan
159. Francies Anthony Swamy
160. Selvaraj Janatikkan
161. Kaliyan Kandeswamy
162. Muthu Usukettan
163. Manikam Thangavelu
164. Chinnathambi Rangaswamy
165. Narutamuthu Arumugam
166. Govundaraj Ramaswamy
167. Balamani Puthiyavan
168. Thangam Sudalai

[No. L-31011|11|81|D. IV(A)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983